राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 8 अंक 169

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, मंगलवार, 26 नवंबर, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

पर्थ में भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत

>> 12

जागरण विशेष

मतांतरण रोक संरक्षित किया स्वतंत्रता का अधिकार

डिंडौरी: मप्र के डिंडौरी में जनजाति कल्याण केंद्र आदिवासियों के साथ संरक्षित जनजाति बैगा को मिशनरियों के जाल से बचाकर इनके अधिकारों का संरक्षण कर रहा है। • पेज-7

संपादकीय

जन-जन के मन का दस्तावेज है संविधान: भारत का संविधान कोई न्यायिक या वैधानिक दस्तावेज मात्र नहीं है। वह भारत की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि है। **भूपेंद्र यादव** का आलेख।

मेडिकल टूरिज्म का गढ़ बनता भारत: आधुनिक चिकित्सा के साथ ही आयुर्वेद एवं अन्य परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का और अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। **आरके सिन्हा** का दृष्टिकोण। • पेज-8

विमर्श

अमेरिका की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां: अनेक कारणों से आज लगभग पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद उभार पर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम भी उसी तर्ज पर माने जा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में बदलाव को विश्लेषित कर रहे हैं, **डा. अश्विनी महाजन।**

नागरिक अधिकारों का संरक्षण: आज हमारे देश में हर जगह 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की बात जोर-शोर से हो रही है। इसके पीछे संविधान की अपनी शक्ति का विशेष योगदान है। **डा. कन्हैया त्रिपाठी** का आलेख। • पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

अंतस और अध्यात्म का

स्वयं को करें स्वीकार

लोककल्याण के लिए हुआ एकादशी का प्रादुर्भाव

• पेज-13

जिनको जनता ने बार-बार नकारा, वे हुड़दंगबाजी से करना चाहते हैं संसद पर कंट्रोल : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ हंगामा कर संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष पर बोला हमला

▸ कहा, जनता द्वारा 80-90 बार नकारे गए लोग संसद में नहीं होने दे रहे चर्चा

नई दिल्ली में सोमवार को संसद के शीतसत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएफपी

हंगामा कर संसद की कार्यवाही को बार-बार बाधित करने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले मोदी ने विपक्ष की हंगामा करने की प्रवृति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, 'जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है, वे राजनीतिक लाभ के लिए संसद को भी मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।'

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नकारात्मक राजनीति की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, संसद में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 80-90 बार जनता द्वारा नकार दिए गए लोग न तो संसद में चर्चा होने देते हैं और न ही लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। मोदी ने कहा,एक दशक से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस व विपक्षी दलों को बार-बार मिल रही हार की वजह जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने में उनकी विफलता है। उनके लिए जनता की आकांक्षाओं की कोई अहमियत नहीं है। पीएम के अनुसार, कई विपक्षी दल ऐसे भी हैं, जो संसद में बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते है और सुचारू रूप से सदन चलाना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर ऐसे दलों की आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया। साथ ही विपक्षी दलों को सावधान करते हुए कहा , जनता उनके सारे व्यवहार देखती है और समय आने पर न्याय भी करती है।

मोदी ने कहा, सबसे परेशान करने वाला पहलू यह है कि ऐसा व्यवहार उन नए सांसदों के अधिकारों का भी हनन करता है जो सभी पार्टियों से नए विचार व ऊर्जा लेकर आते हैं। नए सदस्यों को अक्सर सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी की यह जिम्मेदारी है कि वह अगली पीढ़ी को तैयार करे। पीएम ने उम्मीद जताई कि सभी पार्टियों के नए सदस्यों को सदन में बोलने का मौका मिलेगा। साथ ही कहा, 'आज दुनिया बड़ी उम्मीद से भारत की ओर देख रही है। संसद सदस्य के तौर पर हमें अपना समय भारत का वैश्विक सम्मान व आकर्षण और बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। भारत जैसे अवसर आज विश्व मंच पर दुर्लभ हैं। भारत की संसद से संदेश में लोकतंत्र के प्रति मतदाताओं का समर्पण, संविधान के लिए उनकी प्रतिबद्धता और संसदीय चलन में उनका विश्वास परिलक्षित होना चाहिए।' मोदी ने कहा, 'उनके प्रतिनिधियों के रूप में हमें इन भावनाओं पर खरा उतरना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम उस समय पर विचार करें जो हमने अब तक खोया है और सदन में विभिन्न मुद्दों पर गहन बहस करके इसकी भरपाई करने का संकल्प लें। भावी पीढ़ियां इन चर्चाओं को पढ़ेंगी और प्रेरणा लेंगी। पीएम ने संविधान के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर हो रहे संसद सत्र को ऐतिहासिक बताया और कहा, 'मुझे उम्मीद है कि यह सत्र काफी उत्पादक होगा, संविधान के 75वें वर्ष की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगा, नए सांसदों को अवसर देगा। नए विचारों का स्वागत करेगा।' मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब भी दिया। पीएम पहले भी 60 वर्ष बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मिले जनमत को ऐतिहासिक बता चुके हैं। उनके अनुसार हरियाणा व महाराष्ट्र के विस चुनाव नतीजों से राजग को और अधिक ताकत मिली है। उन्होंने इसे जनता की भावनाओं का आदर करने और उनकी आशाओं-अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन-रात की गई मेहनत का परिणाम बताया।

अदाणी मुद्दे पर चर्चा व जेपीसी पर अड़ा विपक्ष

नई दिल्ली : सोमवार को दोनों सदनों की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी पार्टियों ने स्थगन प्रस्ताव देते हुए अदाणी और मणिपुर हिंसा पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। लोकसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संभल में हुई घटना को लेकर आवाज उठाई। (पेज-3)

प्राकृतिक कृषि को मिलेगा प्रोत्साहन, बिना उर्वरक खेती करेंगे किसान

कैबिनेट के फैसले ▸ 2,481 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ एक करोड़ किसानों को फायदा, सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था

नई दिल्ली में सोमवार को कैबिनेट बैठक की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रेट्र

कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को हरी झंडी दिखा दी है। इसके लिए कुल 2,481 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती (बिना उर्वरक) के लिए प्रेरित करना है। योजना से मिट्टी की सेहत सुधरेगी। खेती की लागत में कमी आएगी और टिकाऊ खेती का माहौल तैयार होगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई है। योजना को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष (2025-26) में 2,481 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र का हिस्सा 1,584 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने कहा, जमीन को रसायन मुक्त रखने की बड़ी जरूरत है। इस योजना से मिट्टी की सेहत, उर्वरता व गुणवत्ता को पुनः जिंदा करने के साथ जलभराव, बाढ़ एवं सूखा आदि संकटों से बचाव में मदद मिलेगी।

वैष्णव ने कहा, विरासत में मिले पारंपरिक ज्ञान के आधार पर किसान रसायन मुक्त खेती को अपनाएंगे, जिसमें पशुधन एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके, विविध फसल प्रणाली आदि शामिल हैं। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य सबके लिए सुरक्षित व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इससे खेती की लागत भी कम होगी। उर्वरकों पर निर्भरता भी खत्म होगी। जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। जलवायु के हिसाब से फसल प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। किसानों को उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र एवं ब्रांडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सकें। आनलाइन पोर्टल के जरिये निगरानी की जाएगी। अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को इससे जोड़ा जाएगा और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू होगी। दस हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

अनुभवी किसान बन सकेंगे ट्रेनर : किसानों को प्रेरित करने के लिए प्राकृतिक खेती के लिए चयनित भूखंड के पास के कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं संबंधित खेतों पर दो हजार माडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। अनुभवी किसानों को ट्रेनर बनाया जाएगा।

पेपरलेस और आनलाइन होगी पैन कार्ड की मौजूदा प्रणाली

नई दिल्ली, जेएनएन : आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा, पैन कार्ड जिंदगी का एक हिस्सा है। यह मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पैन 2.0 परियोजना के तहत मौजूदा प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा। इसे पेपरलेस और आनलाइन रखेगा। व्यापार जगत की तरफ से बहुत ज्यादा मांग हो रही थी कि क्या तीन चार अलग-अलग 'सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता' की जगह कोई एक आइडेंटीफायर हो सकता है? इसे देखते हुए पैन, टैन आदि को एकीकृत किया जाएगा। पैन डाटा वाल्ट सिस्टम को भी अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग कई जगह पैन का विवरण देते हैं। डाटा वाल्ट सिस्टम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन लोगों ने हमारा पैन विवरण लिया है, वे उसे सुरक्षित रखेंगे। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा। शिकायतों के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा। लोगों को किसी तरह की समस्या होने पर उसका जल्द समाधान किया जाएगा।

सुनियोजित थी संभल हिंसा, सपा सांसद जियाउर्रहमान नामजद

जागरण संवाददाता, संभल

संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार को भड़की हिंसा सुनियोजित थी। घायल सीओ, डिप्टी कलेक्टर व पुलिसकर्मियों की ओर से सोमवार को 3,750 से अधिक लोगों के खिलाफ सात अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। दरोगा दीपक राठी की ओर से प्राथमिकी में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल व आठ सौ से अधिक अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। सांसद व विधायक पुत्र पर भीड़ को हिंसा करने के लिए भड़काने का आरोप है। 25 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। जामा मस्जिद के सदर व मस्जिद की ओर से वकील जफर अली सहित दो सौ से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि, पूछताछ के बाद जफर अली को छोड़ दिया गया।

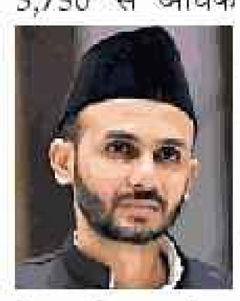

जियाउर्रहमान बर्क।

शहर में सोमवार को दूसरे दिन भी तनावपूर्ण स्थिति रही। पुलिस, पीएसी व रैपिड एक्शन फोर्स के जवान गश्त करते रहे। दहशतजदा व्यापारियों ने दुकानें नहीं खोलीं। इंटरनेट सेवा व स्कूल-कालेज मंगलवार को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के जुटने की आशंका के मद्देनजर 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

मस्जिद के सर्वे पर बवाल

▸ भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप, प्राथमिकी में सपा विधायक के पुत्र का भी नाम

▸ सात अलग-अलग प्राथमिकी, 25 को भेजा जेल, 3750 से अधिक के खिलाफ मुकदमा

▸ संभल में दूसरे दिन भी तनाव, जामा मस्जिद के सदर सहित दो सौ से अधिक हिरासत में

▸ बाजार सोमवार को भी नहीं खुला, इंटरनेट सेवा और स्कूल आज भी बंद रखने का आदेश

चलाया धरपकड़ अभियान

अधिकारियों ने सोमवार को उपद्रवियों की धरपकड़ का अभियान चलाया। पुलिस ने वीडियो जारी किए हैं, जिनके आधार पर आरोपितों को चिह्नित किया जा रहा है।

19 नवंबर को जिला अदालत ने मस्जिद के सर्वे का दिया था आदेश पेज>>5

पाक के गृह मंत्री बोले, गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोग देश के नागरिक नहीं, दहशतगर्द हैं

जेएनएन, नई दिल्ली

▸ मंत्री मोहसिन नकवी आलोचना होने पर अपने बयान से पलट गए

मोहसिन नकवी। फाइल

इंटरनेट मीडिया पर जमकर हुए ट्रोल, लोग बोले- आखिर सच्चाई दुनिया के सामने आ ही गई

गुलाम जम्मू-कश्मीर को लेकर पाक के दिल की बात सोमवार को आखिर उसकी जुबान पर आ ही गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि वहां के लोग दहशतगर्द हैं। वह पाकिस्तानी नागरिक ही नहीं हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान गुलाम जम्मू-कश्मीर को लेकर पिछले करीब सात दशकों से घड़ियाली आंसू बहाता रहा है लेकिन उसके गृह मंत्री ने आखिर सच उगल ही दिया। अपने इस सनसनीखेज बयान पर नकवी इंटरनेट मीडिया पर भी खूब ट्रोल हुए। लोगों ने लिखा- आखिर गुलाम जम्मू-कश्मीर को लेकर सच्चाई दुनिया के सामने आ ही गई। वैसे भी गुलाम जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाक ने इस क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर रखा है। हालांकि देर शाम नकवी अपने बयान से पलट गए और कहा कि इंटरनेट मीडिया पर चल रहा उनका बयान बेबुनियाद और झूठ पर आधारित है। फेक न्यूज फैलना गैरकानूनी और देशहित में नहीं है।

पत्रकार इमरान रियाज ने पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नकवी ने इमरान खान के समर्थन में गुलाम जम्मू-कश्मीर से इस्लामाबाद आने वाले उनके समर्थकों को रोकने के लिए न केवल सड़कें खुदवा दीं हैं बल्कि वहां के लोगों को दहशतगर्द भी बताया है।

बता दें कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के हजारों कार्यकर्ता सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और इंटरनेट सेवाओं पर रोक के बीच विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजधानी इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। पीटीआइ ने गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए लोगों से मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है।

यह पहली बार नहीं जब लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं पेज>>11

डूसू अध्यक्ष पद पर सात वर्ष बाद एनएसयूआइ का कब्जा

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) में सात साल बाद नेशनल स्टूडेंट यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआइ) ने कब्जा जमाया है। रौनक खत्री अध्यक्ष और लोकेश चौधरी संयुक्त सचिव बने हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के भानु प्रताप उपाध्यक्ष और लक्ष्मीबाई कालेज की छात्रा मित्रविंदा करनवाल सचिव पद पर निर्वाचित हुई हैं। (पेज-2)

दिल्ली छोड़ पूरे देश में दो रुपये महंगी हुई सीएनजी

नई दिल्ली : देश के कई शहरों में सीएनजी की कीमत में दो रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है, लेकिन चुनावी राज्य दिल्ली में उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे छूट दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में सीएनजी व खाना पकाने के लिए घरों में पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस पहुंचाने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दाम में इजाफे की घोषणा की है। (पेज-10)

अंडमान में पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप

▸ मछली पकड़ने वाले जहाज में में रखी गई थी 6,000 किलो मेथमफेटामाइन

▸ तटरक्षक बल ने जहाज पर मौजूद म्यांमार के छह नागरिकों को किया गिरफ्तार

पोर्ट ब्लेयर में सोमवार को जहाज में बरामद की गई मेथमफेटामाइन की सबसे बड़ी खेप के साथ भारतीय तटरक्षक बल के जवान। प्रेट्र

पोर्ट ब्लेयर, प्रेट्र : मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जारी अभियान में सरकार को एक और बड़ी सफलता मिली है। भारतीय तटरक्षक बल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास 6,000 किलोग्राम प्रतिबंधित मेथमफेटामाइन ले जा रहे एक जहाज को जब्त कर लिया और म्यांमार के छह नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। यह मादक पदार्थ दो-दो किलोग्राम वजन के करीब 3,000 पैकेट में पैक पाया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कई करोड़ रुपये है। यह देश में पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप है।

इससे पहले सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर हुई थी, जहां करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। इसी माह की 14 तारीख को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), नौसेना व गुजरात एटीएस ने संयुक्त अभियान में गुजरात के करीब अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र से 700 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त कर आठ ईरानी नागरिकों को पकड़ा था। एनसीबी ने उसी दिन दिल्ली में 900 करोड़ रुपये मूल्य की 82 किलो कोकेन जब्त की थी।

रक्षा अधिकारी ने बताया कि 23 नवंबर को तटरक्षक बल का विमान गश्त पर था। पायलट ने पोर्ट ब्लेयर से 150 किमी दूर बैरन द्वीप के पास मछली पकड़ने वाले जहाज की संदिग्ध गतिविधि देखी। उसे चेतावनी दी गई और गति कम करने को कहा। इस बीच पायलट ने अंडमान एवं निकोबार कमान को इसकी जानकारी दी। तत्काल नजदीकी गश्ती जहाज बैरन द्वीप रवाना हो गए तथा मछली पकड़ने के जहाज को जांच के लिए 24 नवंबर को पोर्ट ब्लेयर ले गए। अधिकारी ने कहा, हमने जहाज पर सवार म्यांमार के छह नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है।

भारत व पड़ोसी देशों में खपाने के लिए लाई जा रही थी मेथमफेटामाइन पेज>>6

सुप्रीम व्यवस्था

शीर्ष अदालत ने 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द हटाने की मांग खारिज की, दोनों शब्दों को जोड़े जाने के 44 वर्ष बाद चुनौती दिए जाने पर भी उठाया सवाल

संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के जरिये प्रस्तावना में जोड़े गए इन दोनों शब्दों को 44 वर्ष बाद चुनौती दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा, इतने समय बाद चुनौती देने का न्यायोचित आधार नजर नहीं आता। याचिका पर विस्तार से विचार करने की जरूरत नहीं लगती। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में कहा,संविधान जीवंत दस्तावेज है। संसद को संविधान संशोधन की निर्विवाद शक्ति प्राप्त है और यह शक्ति प्रस्तावना में संशोधन तक विस्तारित है।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इसके साथ ही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी तथा अन्य की तीन याचिकाएं खारिज कर दीं। तीनों ही याचिकाओं में आपातकाल के दौरान 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संशोधन के जरिये संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्ष' को चुनौती दी गई थी। इनमें कहा गया था कि संविधान में शुरू में ये दोनों शब्द नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया और वह भी पूर्व तिथि यानी संविधान अंगीकर करने की तिथि 26 नवंबर, 1949 से प्रभावी किया गया। संशोधन को पूर्व तिथि से लागू करना गलत था। याचिकाएं खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,संविधान का अनुच्छेद-368 संसद को संविधान संशोधन की इजाजत देता है। अगर याचिकाकर्ताओं की पूर्व तिथि से संशोधन लागू करने की दलील स्वीकार की जाएगी तो यह चीज संविधान के किसी भी हिस्से में किए गए संशोधन पर समान रूप से लागू होगी।

कोर्ट ने कहा,यह सही है कि संविधान सभा प्रस्तावना में 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ने को राजी नहीं थी, पर संसद को इसमें संशोधन की शक्ति दी गई है। समय के साथ भारत ने पंथनिपेक्षता की अपनी व्याख्या विकसित कर ली है। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 से आता है जो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। साथ ही कानून के समक्ष समानता और रोजगार के अवसरों में समानता की गारंटी देता है। प्रस्तावना का मूल तत्व समानता, बंधुत्व व गरिमा है। कोर्ट ने संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राप्त विभिन्न अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बावजूद अनुच्छेद-44 के नीति निदेशक तत्वों में सरकार को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की इजाजत दी गई है। केशवानंद भारती सहित कई पूर्व फैसलों में कहा जा चुका है कि पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल तत्व है। यह सिद्धांत समानता के अधिकार के एक पहलू को प्रदर्शित करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजवाद का अर्थ सरकार की आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसे स्वीकार किया जा चुका है।

> पंथनिरपेक्षता की धारणा समानता को प्रदर्शित करती है जो संविधान का मूल स्वरूप है। इसी तरह समाजवाद शब्द को सिर्फ आर्थिक नीतियों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाजवाद कल्याणकारी राज्य की प्रतिबद्धता का द्योतक है जो राज्य द्वारा अवसर की समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। - सुप्रीम कोर्ट

बांग्लादेश में इस्कान के सचिव रहे चिन्मय गिरफ्तार, विरोध में उतरे हिंदुओं पर हमले

▸ देश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शनों की अगुआई की थी चिन्मय ने

चिन्मय की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश पुलिस ने सोमवार को ढाका में हिंदू समूह सम्मिलिता सनातनी जोत के नेता एवं इस्कान ट्रस्ट के सचिव रहे चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की। इस दौरान हिंदू प्रदर्शनकारियों पर हमले भी किए गए, जिसमें एक प्रोफेसर के घायल होने की सूचना है। ज्ञात हो, चिन्मय ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रदर्शनों की अगुआई की थी।

पुलिस प्रवक्ता रेजाउल करीम ने कहा कि चिन्मय को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्होंने उन आरोपों का विवरण नहीं दिया जिनके लिए उन्हें पकड़ा गया। बंगाली भाषा के अखबार प्रोथोम अलो ने बताया कि दास इस्कान ट्रस्ट के लीडर थे। उन्हें हाल में वहां से निष्कासित कर दिया गया था। बांग्लादेश में इस्कान नेता तुरंत टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि इससे विदेशों में देश की छवि खराब होगी।

चिन्मय समेत 19 के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा पेज>>11

****

14 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते रोजाना एम्स की ओपीडी में पहुंचते हैं। इनकी सुरक्षा में करीब 3200 सुरक्षा गार्ड हैं। अब इनमें एक तिहाई सुरक्षा गार्ड महिलाएं होंगी। एम्स निदेशक ने इसका आदेश जारी किया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 26 नवंबर, 2024

आज का मौसम

सुबह स्माग एवं मध्यम श्रेणी का कोहरा रहने की संभावना। रात में भी यही स्थिति रहेगी। दिन में आसमान साफ रहेगा।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
26 नवंबर	26.0	12.0
27 नवंबर	26.0	11.0
नोएडा		
26 नवंबर	26.0	12.0
27 नवंबर	26.0	9.0
गुरुग्राम		
26 नवंबर	27.0	12.0
27 नवंबर	26.0	11.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

दिल्ली दंगा : आरोपितों की अर्जी पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपितों की जमानत याचिका पर छह दिसंबर को सुनवाई करेगा। आरोपित और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और अन्य ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और शलिंदर कौर की पीठ जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की इसी तरह की याचिका के साथ इस मामले की भी सुनवाई करेगी। (जासं)

ड्रग तस्करी मामले में आरोपित कनाडाई नागरिक को जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट), 1985 के तहत ड्रग तस्करी मामले में शामिल होने के आरोपित कनाडाई नागरिक मनप्रीत सिंह गिल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। अदालत ने आरोपित पर अपना पासपोर्ट सरेंडर करने व देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने की शर्त लगाई है। कहा है कि सह-आरोपित के बयान बिना पुष्टि के कोई साक्ष्य मूल्य नहीं रखते। (जासं)

माप में कम मिला डीजल-पेट्रोल तो लगेगा 50 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली : दिल्ली में गैर मानक वाले बाट या उपकरणों से सामान तौलने वाले दुकानदारों की खैर नहीं है। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि खुदरा विक्रेता द्वारा गैर-मानक बाट या माप के इस्तेमाल करने पर अब जुर्माना 2500 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया जाएगा। थोक व्यापारी के लिए यह जुर्माना राशि 10 हजार और पेट्रोलियम उद्योग/पेट्रोल पंप के लिए यह राशि 50 हजार रुपये होगी। (राब्यू, जागरण)

केजरीवाल का बड़ा दांव, 80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन

पूर्व मुख्यमंत्री का दावा ▸ दिल्ली में पहले 3.32 लाख बुजुर्गों को मिलती थी पेंशन, संख्या बढ़ाकर 5.30 लाख की

समाज कल्याण विभाग ने शुरू किया पोर्टल, 24 घंटे में आए 10 हजार आवेदन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कूद चुकी आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री आतिशी की उपस्थिति में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 80 हजार नए बुजुर्गों के लिए पेंशन शुरू करने की घोषणा की। ये पेंशन पहले से दी जा रहीं पेंशन से अलग होंगी। सरकार ने आवेदन के लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया है, जिस पर 24 घंटे में 10 हजार आवेदन आ चुके हैं।

केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अब पांच लाख 30 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। 80 हजार नए पात्रों को आवेदन मिलने तक यह पोर्टल सक्रिय रहेगा। बता दें कि पेंशन स्कीम में 2017 के बाद से धीमी गति से बुजुर्गों को जोड़ा जा रहा था।

पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में केजरीवाल ने कहा, आप सरकार से पहले दिल्ली में 3.32 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। जब उनकी सरकार आई तो इसे बढ़ाकर साढ़े चार लाख कर दिया गया था। इसमें अब 80 हजार नई पेंशन और शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में बुजुर्गों को 500 से 1,000 रुपये ही पेंशन मिलती है, जबकि आप की सिंगल इंजन की सरकार में 2,500 तक पेंशन मिलती है।

केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली में जब भी पदयात्रा करता था और लोगों से बातचीत करता था तो बुजुर्ग मुझसे यही मांग करते थे कि उनकी पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन लगवा दो। दिल्ली में उनकी सरकार आने से पहले 60 से 69 साल के बुजुर्गों को हर महीने एक हजार और 70 साल या इससे अधिक उम्र वालों को 1500 रुपये पेंशन मिलती थी। 2015 में हमारी सरकार आने पर इसे दोगुना किया गया। केजरीवाल ने कहा कि मेरे जेल जाने पर अन्य कामों के साथ-साथ बुजुर्गों की पेंशन भी रोक दी गई।

अन्य राज्यों में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन : आप के अनुसार, राजस्थान में 1,150 रुपये, उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये, गुजरात में 700, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में 600 रुपये, ओडिशा में 300 रुपये, असम व गोवा में 500 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती है।

नई दिल्ली में सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। साथ हैं मुख्यमंत्री आतिशी। एएनआइ

दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन

दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए दिल्ली में एक बड़ी रकम दी जा रही है। 60 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को पांच हजार रुपये महीना पेंशन दी जाती है। इस स्कीम में नए दिव्यांगों को जोड़ने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुका है और जल्द ही इसके लिए भी आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के तहत 60-69 वर्ष उम्र वर्ग के वृद्धजनों को 2,000 रुपये प्रतिमाह (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अतिरिक्त 500/- रुपये प्रतिमाह) एवं 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वृद्धों को 2,500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

पेंशन लेने के लिए निर्धारित पात्रता

- उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
- आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पांच वर्ष से निवासी हो।
- परिवार की आय 10 हजार रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
- आधार नंबर आवेदन करने हेतु अनिवार्य है।
- किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता, जो कि आधार से जुड़ा हुआ हो।
- अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

- यदि प्रार्थी इस योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता को पूर्ण करते हैं तो वे आनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.delhigovt.nic.in) पर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की पूछताछ, सहायता हेतु प्रार्थी संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
- संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालयों के नाम, पते की सूची विभागीय वेबसाइट (https://socialwelfare.delhi.gov.in) पर उपलब्ध है।

2025 में भाजपा की बनी सरकार तो सभी बुजुर्गों को देंगे पेंशन : सचदेवा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली में आप के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा अतिरिक्त 80 हजार लोगों को पेंशन देने की घोषणा पर भाजपा ने पलटवार कर कहा कि इससे आधे बुजुर्गों को भी लाभ नहीं मिलेगा, जबकि फरवरी 2025 में भाजपा की सरकार आएगी तो सभी बुजुर्गों को आन डिमांड पेंशन मिलेगी। भाजपा ने कहा, पूर्व सीएम द्वारा 80 हजार और बुजुर्गों को पेंशन की घोषणा करना भाजपा के संघर्ष और राजनीतिक दबाव का परिणाम है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप सरकार नई पेंशन जारी करना तो दूर जो पेंशन मिलती भी रही हैं, उनमें भी बुजुर्ग पेंशनधारकों को कई माह तक इंतजार करना पड़ता है।

सचदेवा ने पूर्व सीएम की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई पेंशन नियमित मिलती रहे, यह एक प्रशासनिक निर्णय है, इसे सीएम या समाज कल्याण मंत्री को करना चाहिए था। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा इसकी घोषणा करना साफ दिखाता है कि यह एक राजनीतिक छलावा है, जो चुनाव बाद लटक भी सकता है। साथ ही यह साबित हो गया है कि आतिशी एक डमी मुख्यमंत्री हैं।

दिल्ली में दमघोंटू हवा बरकरार, राहत के भी अभी नहीं आसार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सोमवार को भी दमघोंटू ही बना रहा। 24 घंटे का औसत एक्यूआइ रविवार के 318 से बढ़कर 349 हो गया। मौसमी परिस्थितियों के चलते दिनभर स्माग की पतली चादर भी आसमान पर छाई रही। स्विस कंपनी के एप आइएक्यू एयर और सीपीसीबी के आंकड़ों में आज भी अंतर देखने को मिला। अगले तीन से छह दिनों तक वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में ही रहने का अनुमान है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर हर घंटे अपडेट देने वाले सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार सोमवार सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआइ 218 दर्ज किया गया था, लेकिन हवा की कम रफ्तार के कारण शाम सात बजे यह बढ़कर 377 हो गया। दिल्ली के 38 वायु गुणवत्ता-निगरानी स्टेशनों में से सात ने शाम 5:30 बजे एक्यूआइ स्तर को 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया, जिसकी संख्या शाम सात बजे बढ़कर 14 हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआइ शाम चार बजे दर्ज किया गया, जो 349 था। आइक्यू एयर ने इसी दौरान 371 एक्यूआइ दर्ज किया।

पर्यावरणविद् भवरीन कंधारी ने कहा कि 10 किमी प्रति घंटे से कम गति वाली स्थिर हवा और गिरते तापमान के कारण एक्यूआइ में वृद्धि हुई है। सोमवार को वायु गुणवत्ता खराब करने में योगदान देने वाला प्राथमिक प्रदूषक पीएम 2.5 था, जिसका स्तर शाम चार बजे 166.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था।

नई दिल्ली में छाए घने कोहरे व स्माग में लाइटें जलाकर चलते वाहन चालक। ध्रुव कुमार

सीएक्यूएम ने स्कूलों के लिए ग्रेप नियमों में किया बदलाव

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बच्चे मिड-डे मील से वंचित व कुछ बच्चों के पास नहीं है आनलाइन क्लास की सुविधा
- एनसीआर के राज्यों को दिया निर्माण कार्यों के श्रमिकों को लेबर सेस से भत्ता देने का आदेश
- प्रदूषण के स्तर में लगातार कमी आने तक लागू रहेंगे ग्रेप-चार के प्रतिबंध

प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार देर रात एक नया आदेश जारी किया है। एनसीआर के स्कूलों को लेकर ग्रेप के कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि एनसीआर में सभी स्कूल प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएं। यानी ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में आनलाइन और फिजिकल क्लास दोनों ही मोड में स्कूल चलाए जाएं।

इसका मतलब है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो वे भेज सकते हैं या फिर अगर अभिभावक नहीं चाहते कि बच्चों को स्कूल भेजें तो वे आनलाइन मोड में क्लास ले सकते हैं। ये राज्य सरकारों और अभिभावकों पर निर्भर करेगा। सीएक्यूएम का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतमबुद्ध नगर के लिए अनिवार्य है। शेष जिलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को विचार करने के लिए कहा गया है।

जागरण ब्यूरो के अनुसार, इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बच्चों के पास आनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित होने और स्कूल बंद होने के कारण मिड-डे मील से वंचित हो रहे बच्चों की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से स्कूलों को खोलने पर विचार करने को कहा था। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने एनसीआर के सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जब तक निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध है तब तक वे श्रमिक कल्याण के लिए एकत्र किए गए लेबर सेस से श्रमिकों को साप्ताहिक भत्ता दें जिससे उनका गुजारा हो।

ये निर्देश जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सोमवार को दिए। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने से ग्रेप-चार के प्रतिबंध लागू हो गए हैं, जिसके कारण स्कूल-कालेज बंद हैं। ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं जिनके पास आनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं हैं या जिन स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं हैं। साथ ही स्कूलों और आंगनबाड़ियों के बंद होने से बच्चे मिड-डे मील से भी वंचित हो रहे हैं। इन पहलुओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि वह कुछ ऐसे वर्गों को छूट देने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि आयोग तीन श्रेणियों को छूट देने पर विचार करे। पहला तो बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो स्कूल और आंगनबाड़ी बंद होने से मिड-डे मील से वंचित हो गए हैं। दूसरे, बड़ी संख्या उन बच्चों की हैं जिनके पास आनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं हैं, बहुत से स्कूलों के पास आनलाइन क्लास के साधन नहीं हैं। तीसरी श्रेणी ऐसे छात्रों की है, जिनके घर एयर प्यूरीफायर नहीं हैं, ऐसे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्कूल जाएं या घर में रहें। कोर्ट ने ग्रेप-चार के प्रतिबंधों में छूट पर कहा कि जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता कि प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है तब तक दूसरी और तीसरी श्रेणी ग्रेप में जाने की इजाजत नहीं देगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छात्रों को राहत।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश

ग्रेप-चार के प्रतिबंध लागू होने पर दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती में ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि कुछ ही एंट्री प्वाइंट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, वे भी बिना किसी निर्देश के। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि कोर्ट के 22 नवंबर के आदेश के बाद पुलिस की तैनाती की गई। यह गंभीर चूक है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया है कि वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सीएक्यूएम एक्ट, 2021 की धारा-14 के तहत कार्रवाई शुरू करे।

सीवेज ट्रीटमेंट पर गुमराह करने के लिए डीजेबी को फटकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- एनजीटी ने कहा, डीजेबी और डीडीए मामले में आपसी मतभेदों को सुलझाए
- सुनिश्चित करे कि स्मृति वन के तालाब में केवल उपचारित पानी प्रवाहित हो

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी को दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित स्मृति वन में सीवेज उपचार संयंत्र के कामकाज के संबंध में गुमराह करने को लेकर फटकार लगाई। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डीजेबी का उद्देश्य मछली के तालाब को पुनर्जीवित करना था, लेकिन तालाब में सीवेज भरा जा रहा है। पीठ ने डीजेबी और डीडीए को अपने मतभेदों को सुलझाने और सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि तालाब में केवल उपचारित पानी ही प्रवाहित हो। पीठ ने दोनों एजेंसियों को बैठक करने व जल निकाय और विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र (डीएसटीपी) की स्थिति पर नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

पीठ ने कहा कि मामले को लेकर जब डीजेबी से पूछा गया कि डीएसटीपी में क्या उपचारित किया जाता है तो डीजेबी अधिकारी ने कहा कि डीएसटीपी में सीवेज नहीं बल्कि वर्षा जल को उपचारित किया जाता है। फिर कुछ और दलीलों के बाद उन्होंने कहा कि डीएसटीपी में नाले के पानी को उपचारित किया जाता है। नाले के पानी के उपचार के बारे में कुछ तर्क के बाद, उन्होंने फिर से अपना रुख बदल दिया और कहा कि डीएसटीपी में सीवेज का भी उपचार किया जाता है।

पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा बार-बार रुख बदलने से ऐसा प्रतीत होता है न्यायाधिकरण को गुमराह करने का प्रयास किया गया। डीजेबी के जवाब से पता चलता है कि डीजेबी और डीडीए के बीच उचित समन्वय नहीं है। इसलिए डीजेबी के सीईओ और डीडीए के उपाध्यक्ष या कार्यवाहक उपाध्यक्ष बैठक करें और इस मतभेद को सुलझाएं। पीठ ने कहा कि डीजेबी और डीडीए के अधिकारी तीन सप्ताह के अंदर एक हलफनामा दाखिल करेंगे।

हाई कोर्ट ने पूछा, असुरक्षित फ्लाईओवर गिर गया तो कौन होगा जिम्मेदार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- हाई कोर्ट ने फ्लाईओवर मरम्मत पर दिल्ली सरकार के दो विभागों के बीच विवाद पर जताई नाराजगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फ्लाईओवर की मरम्मत के संबंध में दिल्ली सरकार के दो विभागों के बीच फंड विवाद पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने दोनों विभागों को कहा कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस फ्लाईओवर में संरचनात्मक दोष हैं और यह जनता के लिए असुरक्षित है तो इस मामले में किसी वित्तीय या तकनीकी मुद्दे का सवाल ही कहां उठता है? यदि इस बीच फ्लाईओवर गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सुरक्षा सर्वोपरि है और मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने टिप्पणी की कि चाहे फंड पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (टीटीडीसी) द्वारा दिया गया हो या लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा, इसका बोझ अंततः दिल्ली सरकार को ही उठाना था। वह यह नहीं समझ पा रही है कि दिल्ली सरकार के दोनों विभाग एक-दूसरे का विरोध क्यों कर रहे हैं, खासकर तब जब यह एक स्वीकृत तथ्य है कि फ्लाईओवर जनता के लिए असुरक्षित है।

पीडब्ल्यूडी के अधिवक्ता ने दलील दी कि शुरुआती निर्माण टीटीडीसी ने वर्ष 2015 में किया था, इसलिए उसे जल्द से जल्द फ्लाईओवर की मरम्मत करनी थी। दूसरी ओर, टीटीडीसी के अधिवक्ता ने दलील दी कि वह फंड के लिए पीडब्ल्यूडी पर निर्भर है और शुरुआती ठेकेदार को आठ करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था, जिसका भुगतान पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया है।

याचिकाकर्ता भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल ने कहा कि दोनों विभाग मामले में अपना दायित्व एक-दूसरे पर डाल रहे हैं, जिससे अंततः जनता को असुविधा हो रही है।

नत्थू कालोनी चौक के पास फ्लाईओवर को लेकर है विवाद : महाजन ने नत्थू कालोनी चौक के पास स्थित इस फ्लाईओवर की मरम्मत करने और उसे फिर से खोलने का निर्देश देने की मांग की थी। याची ने पिछले दो वर्षों से भारी वाहनों के लिए फ्लाईओवर बंद होने पर कहा कि इससे जनता को असुविधा हो रही है।

नत्थू कालोनी फ्लाईओवर पर लगा बैरियर। आर्काइव

> ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के पास बुनियादी ढांचे के सुधार करने के लिए खर्च करने को पैसे नहीं हैं। वे कोई कर नहीं लेते। वे कोई पैसा खर्च नहीं करते। वे केवल दान और मुफ्त में चीजें देते हैं।
>
> – दिल्ली हाई कोर्ट

डूसू अध्यक्ष पद पर सात वर्ष बाद एनएसयूआइ का कब्जा

डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए जीते एनएसयूआइ के रौनक खत्री (दाएं) और संयुक्त सचिव लोकेश चौधरी खुशी का इजहार करते हुए। ध्रुव कुमार

आर्ट फैकल्टी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर डूसू चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए जीते एबीवीपी के भानु प्रताप (बाएं से दूसरे) व सचिव मित्रविंदा (बाएं)। ध्रुव कुमार

उदय जगताप ● जागरण

- मतगणना के दो महीने बाद आया दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम
- एनएसयूआइ के रौनक खत्री बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव पद एबीवीपी के खाते में

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) में सात साल बाद नेशनल स्टूडेंट यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआइ) ने अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है। विधि संकाय के छात्र रौनक खत्री अध्यक्ष और बौद्ध अध्ययन केंद्र के लोकेश चौधरी संयुक्त सचिव बने हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के विधि संकाय के भानु प्रताप उपाध्यक्ष और लक्ष्मीबाई कालेज की छात्रा मित्रविंदा करनवाल सचिव पद पर निर्वाचित हुई हैं। इससे पहले 2017 में एनएसयूआइ ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद जीता था।

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. सत्यपाल सिंह ने बताया कि डूसू चुनाव के लिए 27 सितंबर को वोट डाले गए थे। करीब दो महीने बाद सोमवार को चुनाव परिणाम जारी किए गए। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआइ के रौनक खत्री को कुल 50,689 वोटों में से 20,207 वोट मिले। उन्होंने एबीवीपी के ऋषभ चौधरी को 1,339 वोटों से शिकस्त दी। डूसू उपाध्यक्ष चुने गए एबीवीपी के भानु प्रताप सिंह ने एनएसयूआइ के यश नांदल को हराया। भानु को 24,166 वोट मिले, जबकि यश को 15,404 वोट ही मिल सके। सचिव पद पर कांटे की टक्कर रही। एबीवीपी की मित्रविंदा करनवाल को 50,874 मतों में से 16,703 वोट मिले। वहीं एनएसयूआइ की नम्रता जेफ मीणा को 15,236 वोट मिले। संयुक्त सचिव पद पर मुकाबला एकतरफा रहा। कुल 50,977 वोटों में से एनएसयूआइ के लोकेश चौधरी को 21,975 वोट मिले और एबीवीपी के अमन कपासिया को 15,249 वोट मिले। कोविड के तीन साल बाद 2023 में हुए चुनावों में एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत हासिल की थी। एनएसयूआइ को सिर्फ उपाध्यक्ष पद मिला था, लेकिन, एनएसयूआइ ने इस बार वापसी कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। पहली बार एसएफआइ और आइसा ने पैनल बनाया था, लेकिन सचिव और संयुक्त सचिव दो सीटों पर ही उन्हें अपेक्षित परिणाम मिले। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर उनके उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। नोटा भी खूब चला। नोटा को सर्वाधिक सचिव पद के मामले में 6,771 वोट मिले। संयुक्त सचिव पद 5,660, उपाध्यक्ष पर 4,411 और अध्यक्ष पर 3,906 छात्रों ने नोटा को चुना।

योजना

एलजी वीके सक्सेना के निर्देशों के बाद एएसआइ ने तैयार की कार्य योजना, बारापुला पुल पर थे लंबे समय से अवैध कब्जे, एएसआइ ने हटवाया

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा ऐतिहासिक बारापुला पुल

वी के शुक्ला ● जागरण

नई दिल्ली : ऐतिहासिक बारापुला पुल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके ऊपर से अतिक्रमण हटाने के बाद गेट लगाकर इसे अतिक्रमणकारियों से बचाया जा रहा है। कुछ माह पहले एलजी वीके सक्सेना के निर्देशों के बाद इस पुल पर वर्षों से चला आ रहा अतिक्रमण को हटाया जा सका है। अब यहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके इतिहास को बताने वाले सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। पुल के ऊपर दिल्ली के इतिहास और क्षेत्र में स्थित अन्य स्मारकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) इसके लिए एक योजना बना रहा है। इस ऐतिहासिक बारापुला के नाम पर एक नाले का नाम पड़ा और अब इसी नाम से सात किलोमीटर एलिवेटेड रोड बना है, जिसे अगले वर्ष 10 किलोमीटर किया जाना है। लोगों को इस ऐतिहासिक बारापुला पुल के बारे में जानकारी नहीं है। एएसआइ का यह प्रयास है कि इस पुल की पहचान लौटाई जा सके। एएसआइ की योजना के तहत सबसे पहले इस पुल का बड़े स्तर पर संरक्षण कार्य होगा। उपेक्षित पड़े इस पुल के नीचे के भाग में आ चुकीं दरारों को पहले भरा जाएगा। इसके ऊपर भी जरूरत के हिसाब से संरक्षण कार्य होगा। इसके बाद इसकी केमिकल क्लीनिंग कराई जाएगी, जिससे यह साफ सुथरा दिख सके। एएसआइ के दिल्ली मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद प्रवीण सिंह कहते हैं कि लंबे समय से इस पुल पर अवैध कब्जे थे, जिसे अब हटा दिया गया है। हमारा प्रयास अब इस पुल को उसकी पहचान दिलाना है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं कि बारापुला के नाम से कोई ऐतिहासिक पुल भी है। जल्द ही इसके लिए काम शुरू होगा।

उपेक्षित पड़े बारापुला पुल की चमकेगी किस्मत। जागरण आर्काइव

बारापुला का इतिहास

कुछ इतिहासकार इस पुल का निर्माण 1612 से लेकर 1621-22 के मध्य बताते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के कार्यकाल में 1612 से 1613 के बीच का बताते हैं। कहा जाता है कि बादशाह ने इस पुल का निर्माण हुमायूं का मकबरा और निजामुद्दीन दरगाह व आगरा की ओर आने-जाने वालों के लिए कराया था। आगरा से आवाजाही के लिए उस समय यह मुख्य मार्ग था। नाला पार करने के लिए यह पुल बनाया गया था, जो उस समय इस इलाके का इकलौता पुल था।

****

1,068 मामलों का समाधान किया है सरकार ने दिवालिया कानून के तहत इस साल सितंबर तक। साथ ही लेनदारों ने लगभग 3.55 लाख करोड़ रुपये वसूले हैं।

अदाणी मुद्दे पर चर्चा व जेपीसी पर अड़ा विपक्ष, संसद ठप

राज्यसभा में सभापति और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बीच हुई तीखी नोकझोंक

लोकसभा में विपक्ष ने अदाणी के साथ संभल की घटना पर भी सरकार को घेरा

- हंगामे पर भाजपा ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ, कहा-यह हार की निराशा है
- ओम बिरला ने कहा, सिर्फ विरोध के लिए संसद में हंगामा न करे विपक्ष

नई दिल्ली में सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच जारी नोकझोंक। एएनआइ

नई दिल्ली में सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा का दृश्य। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विपक्ष के तेवरों को देखते हुए जिस तरह से संसद के शीतकालीन सत्र में भी गतिरोध बने रहने की अटकलें लगाई जा रही थीं, सोमवार को वैसा ही हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी पार्टियों ने स्थगन प्रस्ताव देते हुए अदाणी और मणिपुर हिंसा पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। लोकसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई घटना को लेकर आवाज उठाई। सियासी गरमागरमी सदन में बढ़ने की आशंका और विपक्ष के अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं होने को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही पहले दोपहर एक बजे तक के लिए बाद में पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बीच विपक्ष को चेताया भी कि वह सिर्फ विरोध करने के लिए ही सदन में हंगामा न करे, बल्कि सदन को चलने दे। नियमों के तहत चर्चा की अनुमति दी जाएगी।

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही शुरू हुई, तो विपक्षी सदस्यों ने 'नेता विपक्ष को बोलने का मौका दो' जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। खरगे ने भी अपनी सीट से खड़े होकर अदाणी मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया। इस पर धनखड़ ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे बोले हुए अभी एक सेकेंड भी नहीं हुआ है और लोग चिल्लाने लगे। नेता विपक्ष की एक गरिमा है। संविधान लागू हुए 75 साल हो गए हैं, आपको कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए।

इस पर खरगे ने कहा कि इन 75 सालों में मेरा भी 54 साल का योगदान है। आप मुझे मत सिखाइए। धनखड़ ने कहा, मैं तो आपको इतना सम्मान दे रहा हूं और आप हैं कि मुझे ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी खरगे ने जब अदाणी मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो धनखड़ ने पहले मना किया और फिर उनकी बातों को रिकार्ड से बाहर करते हुए सदन एक बजे तक स्थगित कर दिया। जब सदन फिर से बैठा तो नेता प्रतिपक्ष खरगे ने स्थगन प्रस्ताव देते हुए नियम 267 के तहत अदाणी मुद्दे पर चर्चा और जेपीसी गठित करने की मांग रखी। जब उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली तो फिर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।

लोकसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही, जहां अदाणी और संभल की घटना दोनों मुद्दा गूंजा। कांग्रेस ने जहां अदाणी पर अमेरिका में लगे आरोपों के मामले में संसद में तुरंत चर्चा और जेपीसी गठित करने की मांग की, वहीं समाजवादी पार्टी ने संभल की घटना को सदन में रखा। इसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि अदाणी मुद्दे पर चर्चा से सरकार भाग रही है। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव रखते हुए अदाणी मुद्दे पर चर्चा की मांग की। भाजपा ने विपक्ष को इसको लेकर आड़े हाथों लिया और कहा कि संसद नहीं चलने देना विपक्ष की निराशा है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि यदि आप अपनी हार से निराश हैं, तो क्या संसद का काम रोककर प्रतिशोध लेंगे?

वक्फ पर गठित जेपीसी की बढ़ सकती है अवधि

वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी के कार्यकाल को और बढ़ाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। साथ ही कहा कि जेपीसी अध्यक्ष के रवैये के चलते अभी समिति अपना काम पूरा नहीं कर पाई है। कुछ और लोगों से चर्चा होनी है। ऐसे में समिति की अवधि को और बढ़ा दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों को भरोसा दिया कि वह इस पर विचार करेंगे। फिलहाल जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट देनी है।

आदर्श अलग हो सकते हैं, पर देश सर्वोपरि : बिरला

- लोकसभा अध्यक्ष ने कहा-संविधान को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं
- ओम बिरला बोले-कोई भी सरकार संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकती

ओम बिरला। फाइल

नई दिल्ली, एएनआइ : संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ऐन पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोगों के आदर्श और विचार अलग हो सकते हैं, पर देश हमेशा सर्वोपरि है। उन्होंने संविधान को राजनीति से दूर रखने की नसीहत देते हुए कहा, संविधान को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है उसे राजनीति से दूर रखना चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक दस्तावेज और सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का स्रोत है। किसी भी पार्टी या विचारधारा की कोई भी सरकार संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लोगों के अधिकारों व उनकी आकांक्षाएं पूरा करने को समय-समय पर संविधान में बदलाव किए गए हैं।

ओम बिरला ने सोमवार को एक साक्षात्कार में बताया कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग भी होते हैं पर विधानसभाओं में अर्थपूर्ण और सकारात्मक चर्चाएं होती हैं।'संविधान हमारी ताकत है। यह सामाजिक दस्तावेज है। इसी के कारण हम सामाजिक व आर्थिक बदलाव लाए हैं और समाज के वंचित, गरीब तथा पिछड़े लोगों को सम्मान दिया है। आज दुनिया में लोग भारत के संविधान को पढ़ते हैं, उसकी विचारधारा को समझते हैं। हमारे संविधान की मूल भावना हमें सबको जोड़ने और मिलकर काम करने की शक्ति देती है। इसलिए संविधान को राजनीति के दायरे में नहीं लाना चाहिए।' बिरला ने कहा, किसी भी पार्टी या विचारधारा की कोई भी सरकार संविधान की मूल भावना (या संरचना) के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। समय-समय पर संविधान में बदलाव सामाजिक परिवर्तन के लिए किए गए हैं। ध्यान रहे कि विपक्ष ने लोस चुनाव के दौरान आरोप लगाए थे कि सरकार संविधान में बदलाव करेगी। इन्हीं सब आरोपों का वह जवाब दे रहे थे। लोस अध्यक्ष ने कहा, 'मेरा मानना है कि हमारे सदन की गरिमा और उच्च स्तरीय परंपराओं को बनाए रखने के लिए सदस्यों के आचरण और व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर करता है।'

सरकार को घेरने पर विपक्ष का सुर एक, ताल अलग

- खरगे की बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुए तृणमूल नेता, शिवसेना यूबीटी भी रही नदारद
- आइएनडीआइए ने संयुक्त रणनीति में किया तय, जेपीसी की मांग से पीछे नहीं हटेगा विपक्ष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र की अप्रत्याशित हार के बाद भी अदाणी समूह से जुड़े विवादों को लेकर संसद में मोदी सरकार को घेरने की अपनी रणनीति से आइएनडीआइए पीछे नहीं हटेगा। संसद के शीतसत्र के पहले दिन विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में इस पर व्यापक सहमति बनी कि अदाणी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग के साथ-साथ मणिपुर में करीब डेढ़ साल से जारी हिंसा से जुड़े सवालों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। संसद में सरकार की घेरेबंदी के लिए विपक्षी खेमे के सुर बेशक एक सुनाई दिए, मगर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे की छाया आइएनडीआइए के आपसी रिश्तों में खिंचाव के रूप में भी दिखाई पड़ी। एक प्रमुख सहयोगी तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुई। वैसे शिवसेना यूबीटी भी पहली बैठक में शरीक नहीं हुई, मगर इसके पीछे किसी तरह के मंतव्य की आशंका से इन्कार किया।

खरगे की ओर से संसद में विपक्ष की संयुक्त रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक में नहीं जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने कोई टीका-टिप्पणी नहीं कि मगर मेघालय उपचुनाव में तृणमूल के कांग्रेस से आगे रहने के बहाने इशारों में ही कांग्रेस पर तंज कसने से गुरेज नहीं किया। मेघालय विधानसभा की एक सीट के उपचुनाव में राजग उम्मीदवार की जीत और तृणमूल प्रत्याशी के दूसरे नंबर पर रहने के पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के एक्स पोस्ट को साझा करते हुए राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओब्रायन ने यह निशाना साधा। डेरेक ने कहा कि तृणमूल उम्मीदवार मेघालय में दूसरे नंबर पर है पर तीसरे पर कौन, इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। हालांकि डेरेक के तंज के बीच तृणमूल की राज्यसभा सदस्य डोला सेन ने अदाणी पर जेपीसी की मांग का समर्थन करते हुए सदन स्थगित करने पर सरकार को घेरा।

वैसे तृणमूल और शिवसेना यूबीटी के अलावा साझा रणनीति संबंधी खरगे की बैठक में आइएनडीआइए के अन्य तमाम दलों के नेता शामिल हुए और निर्णय लिया गया कि अदाणी समूह में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा बेहद गंभीर है, जिस पर जेपीसी का गठन किया जाना जरूरी है। इसलिए विपक्ष सदन में जेपीसी की मांग करने के साथ मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने जैसे प्रस्तावों पर जोर देगा। इस बैठक में संविधान दिवस के मौके पर मंगलवार को संसद में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी के संबोधन की संभावना के मद्देनजर दोनों सदनों में नेता विपक्ष को भी बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए स्पीकर और सभापति को पत्र लिखने पर सहमति बनी।

आइएनडीआइए नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट में कहा भी कि संसद सत्र शुरू होने के साथ ही सरकार को सबसे पहले अदाणी प्रकरण पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो रही है। इस बैठक में द्रमुक नेता टीआर बालू, तिरुचि शिवा, राकांपा (शरद पवार) की सुप्रिया सुले, सपा के रामजी लाल सुमन, आप नेता राघव चड्ढा, माकपा नेता के. राधाकृष्णन, भाकपा के संदोष कुमार और आइयूएमएल के मोहम्मद बशीर, आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन, केरल कांग्रेस के फ्रांसिस जार्ज, राजद के अभय कुमार सिन्हा समेत कई अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए।

पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट

- फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए इसरो ने विकसित किए हैं प्रोटोकाल
- एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ऐसी घटनाओं में दर्ज की गई वृद्धि

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट आई है। 2022 में पराली जलाने के 48,489 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में पराली जलाने की 9,655 घटनाएं सामने आईं। हरियाणा में इसी अवधि के दौरान मामले 3,380 से गिरकर 1,118 हो गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ऐसी घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई। इस क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान पराली जलाने के मामले 72 से बढ़कर 192 हो गए। लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि इसरो ने फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए प्रोटोकाल विकसित किए हैं। इस पहल से पराली जलाने की घटनाओं के आकलन में एकरूपता आई है। आंकड़ों के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान के अवशेष जलाने की घटनाओं में साल-दर-साल काफी गिरावट देखी गई है।

130 शहरों में से 97 में वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोस में प्रश्न के उत्तर में बताया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) के तहत 2023-24 तक 130 शहरों में से 97 में 2017-18 की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार आया है, जबकि 55 शहरों में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। वाराणसी व धनबाद जैसे शहरों में पीएम 10 में क्रमश : 68 प्रतिशत और 56 प्रतिशत की कमी आई है। एनसीएपी का लक्ष्य 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) प्रदूषण को 40 प्रतिशत तक कम करना है। हालांकि, कोयला खनन क्षेत्रोंमें प्रदूषण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। एनसीएपी 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 130 शहरों को कवर करता है।

संसद प्रश्नोत्तर

श्रम सुधारों पर पांच राज्यों ने तैयार नहीं किए मसौदा नियम

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार कहा है कि पांच राज्यों ने श्रम सुधारों को लेकर मसौदा नियम अभी तक तैयार नहीं किए हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि पांच राज्यों ने औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर तीन संहिताओं के तहत मसौदा नियमों को अभी भी प्रकाशित नहीं किया है, वहीं चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने देश में श्रम सुधार लाने के लिए आवश्यक वेतन संहिता, पर मसौदा नियमों को प्रकाशित नहीं किया है।

मंत्री ने बताया कि 'श्रम' संविधान की समवर्ती सूची में है। इसके तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सौंपी गई है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों को प्रकाशित कर दिया है। श्रम सुधारों के तहत 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध किया गया है।

निष्क्रिय ईपीएफ खातों में हैं 8,505 करोड़ रुपये

कर्मचारियों भविष्य निधि (ईपीएफ) के निष्क्रिय खातों की राशि छह वर्षों में पांच गुना बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में निष्क्रिय ईपीएफ खातों में 1,638.37 करोड़ रुपये थे, जो 2023-24 में 8,505.23 करोड़ रुपये हो गए। लोकसभा में लिखित उत्तर में राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि ईपीएफओ निष्क्रिय खातों में मौजूद राशि संबंधित लाभार्थियों को लौटा देगा। 2023-24 में 2,632.29 करोड़ रुपये की राशि का निपटान किया गया।

गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए समिति का गठन

करंदलाजे ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए गाइडलाइन का सुझाव देने के लिए समिति गठित की है। संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स को परिभाषित किया गया है।

बेरोजगारी दर वैश्विक स्तर से कम

करंदलाजे ने लोस में बताया कि भारत में युवा बेरोजगारी दर वैश्विक स्तर से कम है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के मानव विकास संस्थान (आइएचडी) की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि 2021 में दुनियाभर में युवा बेरोजगारी दर 15.6 प्रतिशत थी। वहीं नवीनतम श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्ष 2023-24 में भारत में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 10.2 प्रतिशत थी।

केंद्रीय विद्यालयों में अनुबंध शिक्षकों को नियमित करने का प्रविधान नहीं

शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुबंध शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित योग्यता रखने वाले संविदा शिक्षकों को समय-समय पर अल्पकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है।

10 वर्षों में 853 आइआरएस अधिकारियों ने लिया वीआरएस

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि गत 10 वर्षों में 853 भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों ने वीआरएस लिया। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा,2019-20 से 31 अक्टूबर, 2024 तक सीमा शुल्क विभाग व डीआरआइ ने केरल के हवाईअड्डों पर 2,746.49 किलोग्राम सोना जब्त किया है।

अप्राकृतिक कारणों से 2021 से 71 बाघों की मौत

देश में 2021 से अवैध शिकार सहित अप्राकृतिक कारणों से 71 बाघों की मौत हो गई। लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में पर्यावरण, वन राज्य मंत्री, कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि 2021 के बाद से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 20 मौतें हुईं। उन्होंने कहा कि देश में बाघों की संख्या प्रति वर्ष छह प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

केंद्र ने उल्फा पर और पांच साल के लिए लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) पर और पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। असम को भारत से अलग करने की साजिश के तहत काम करना जारी रखने, जबरन वसूली और हिंसा के लिए अन्य उग्रवादी संगठनों संग संबंध बनाए रखने पर उल्फा के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। उल्फा को पहली बार 1990 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था। तब से प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है।

गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा,उल्फा अपने सभी गुटों, शाखाओं व अग्रणी संगठनों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो भारत की संप्रभुता व अखंडता के लिए हानिकारक हैं।

संगठन ने अवैध हथियार व गोला-बारूद जमा कर रखा है, 27 नवंबर, 2019 से एक जुलाई, 2024 के दौरान असम में विस्फोटों या विस्फोटक लगाने के कई मामलों सहित 16 आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है।

दुनियाभर के शोध पत्रों के लिए छात्रों को अब भटकना नहीं पड़ेगा

कैबिनेट के फैसले

- कैबिनेट ने वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन को दी मंजूरी, डेढ़ करोड़ से अधिक छात्रों को मिलेगा लाभ
- इनोवेशन की राह से हटेंगी भाषाई दिक्कतें, अटल इनोवेशन मिशन का नया चरण होगा शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने शोध और इनोवेशन को रफ्तार देने के लिए दो और नई घोषणाएं की हैं। इनमें पहला छात्रों-शिक्षकों तक दुनियाभर के शोध पत्रों और जर्नल की पहुंच को आसान बनाने के लिए वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है। इस योजना के लागू हो जाने के बाद छात्रों को दुनियाभर के शोध पत्रों और जर्नल की तलाश के लिए भटकना नहीं होगा, बल्कि उन्हें सारा कुछ एक जगह पर ही मिल जाएगा। इस स्कीम पर अगले तीन सालों में छह हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरा बड़ा एलान अटल इनोवेशन मिशन का नया चरण शुरू करने को लेकर है। इसके तहत 30 ऐसे नए इनोवेशन सेंटर स्थापित होंगे, जिनमें भाषा का कोई बंधन नहीं होगा। यानी कोई भी छात्र यहां स्थानीय भाषा में भी काम कर सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन दोनों पहलों से छात्रों और युवाओं को शोध व इनोवेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम से देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों को जोड़ा जाएगा। इस स्कीम के तहत उन्हें दुनियाभर के सभी शोध पत्र व जर्नल मुहैया कराए जाएंगे। इसमें कुल 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई-पत्रिकाएं अब 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों व केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए सुलभ होंगी।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन के नए चरण को भी शुरू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत देश में 30 नए ऐसे इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे, जहां किसी भी स्थानीय भाषा के छात्र आकर इनोवेशन से जुड़ा काम कर सकते हैं। इस मिशन पर सरकार 2,750 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर के राज्यों में भी करीब एक हजार नए इनोवेशन लैब स्थापित किए जाएंगे। इस मिशन के तहत इनोवेशन की ब्रांडिंग भी की जाएगी।

रेलवे के तीन रूटों पर नए ट्रैक बिछाने को केंद्र सरकार की मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने सोमवार को रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत व्यस्त रूटों पर नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। चार वर्षों में पूरी होने वाली इन परियोजनाओं से तीन राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। इन पर कुल 7,927 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनसे भारतीय रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 639 किलोमीटर की वृद्धि होगी। माल ढुलाई क्षमता भी बढ़ेगी। तीनों परियोजनाएं जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 किमी), भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किमी) एवं प्रयागराज (इरदतगंज)-मानिकपुर तीसरी लाइन (84 किमी) हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,मल्टी ट्रैकिंग से ट्रेनों का आवागमन आसान होगा। इन पर अतिरिक्त यात्री ट्रेनें चल सकेंगी। इस रूट की ट्रेनों में भीड़ कम होगी। नासिक (त्र्यंबकेश्वर), खंडवा (ओंकारेश्वर) और वाराणसी (काशी विश्वनाथ) में ज्योतिर्लिंगों के साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी की यात्रा करने वाले लोगों को आसानी होगी। इससे लगभग 38 लाख आबादी को सहूलियत होगी।

बड़ा आयोजन

वर्षभर चलेगा संविधान स्मरणोत्सव, आज राष्ट्रपति करेंगी शुभारंभ

संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संसद के केंद्रीय कक्ष में संयुक्त सभा, पुस्तकों, सिक्के का विमोचन, देशभर में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन

नई दिल्ली में सोमवार को 'मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान' यात्रा में हिस्सा लेते (बाएं तीसरे से) केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया और रक्षा खडसे। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत के संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने वर्ष भर संविधान स्मरणोत्सव आयोजित करने का निर्णय किया है। मंगलवार को संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त सभा को संबोधित करते हुए इसका शुभारंभ करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय संविधान की महिमा, इसके निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया जाएगा। 'भारत के संविधान का निर्माण : एक झलक', 'भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा', भारतीय संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका सहित भारतीय संविधान का संस्कृत और मैथिली भाषा में विमोचन किया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना का औपचारिक वाचन राष्ट्रपति के नेतृत्व में संसद में होगा। साथ ही देशभर में भी प्रस्तावना के सामूहिक वाचन की तैयारी की गई है।

सोमवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और विधि एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वार्षिक स्मरणोत्सव का ब्योरा दिया। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी है। सरकार का कहना है कि इस संविधान ने भारतीय इतिहास में नए युग की शुरुआत की। वह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। संविधान की विरासत से नागरिकों को परस्पर संवाद और गतिविधियों से जोड़ने के लिए एक विशेष वेबसाइट कांस्टीट्यूशन75 डाट काम बनाई गई है। इससे आम नागरिक संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए वीडियो रिकार्ड करके अभियान में भाग ले सकते हैं। वीडियो को अभियान की वेबसाइट पर अपलोड कर सकेंगे और भागीदारी का प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर संविधान का पूरा पाठ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। आम नागरिक संविधान निर्माण, उस समय हुई संविधान सभा की चर्चाएं, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, आधुनिक भारत को आकार देने वाले मूल्यों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट पर एक एआइ चैटबाक्स बनाया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति संविधान और उसके निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है।

संविधान दिवस पर प्रस्तावना का सामूहिक वाचन देशभर में किया जा रहा है। सरकार की तैयारी है कि पूरे देश में लाखों लोग एक साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ें। वर्ष भर जनभागीदारी बनाए रखने के लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से विशेष पखवाड़ा भी वर्ष 2025 में आयोजित किया जाएगा।

कह कर रहेंगे

माधव जोशी

****

221 हो गई है तृणमूल विधायकों की संख्या बंगाल विधानसभा में। इससे पहले विधानसभा में तृणमूल विधायकों की संख्या 215 थी। हाल ही में हुए उपचुनाव में सभी छह सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीत ली है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 26 नवंबर, 2024

अजीत गुट नहीं चाहता कि शिंदे बनें मुख्यमंत्री

दावेदारी ▸ पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे के समर्थक मुखर होकर उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाने की कर रहे मांग

ओमप्रकाश तिवारी ● जागरण

▸ शिंदे का चयन हुआ तो अजीत पवार समर्थक उनका नाम भी बढ़ाएंगे आगे

▸ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे हैं खामोश, जिद कर नहीं चाहते खेल बिगाड़ना

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की दावेदारी के बीच राकांपा नेता अजीत पवार की मांग को अनसुना नहीं कर पाएगा महायुति। फाइल

मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम आए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हो सकी है। एकनाथ शिंदे के समर्थक उन्हें फिर सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अजीत गुट नहीं चाहता कि शिंदे फिर कुर्सी संभालें। अजीत गुट सीएम पद पर देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहता है। इस बीच निर्दलियों समेत विभिन्न दलों के पांच विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। भाजपा के पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक 145 विधायकों में अब सिर्फ आठ की कमी रह गई है। राकांपा पहले ही फडणवीस को समर्थन दे चुकी है। राकांपा नेता छगन भुजबल ने कहा है कि यदि शिंदे को सीएम बनाया जाता है, तो उनकी पार्टी भी अजीत के नाम की दावेदारी पेश करेगी। भुजबल के बयान से संकेत मिलता है कि अजीत नहीं चाहते कि शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनें।

बिहार माडल की तर्ज पर शिंदे के लिए मुख्यमंत्री पद चाहती है शिवसेना: शिवसेना बिहार माडल की तर्ज पर शिंदे के लिए मुख्यमंत्री पद चाहती है। शिवसेना का कहना है कि महाराष्ट्र में भी बिहार की तर्ज पर छोटे सहयोगी दल को मुख्यमंत्री पद देकर सहृदयता दिखानी चाहिए। प्रेट्र के अनुसार शिवसेना प्रवक्ता नरेश म्हस्के ने बिहार माडल का हवाला देते हुए कहा कि शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ भाजपा नेता रावसाहेब दानवे पाटिल ने शिवसेना के इस तर्क को यह कहकर खारिज कर दिया है कि बिहार में भाजपा पहले ही घोषणा करके चुनाव लड़ी थी कि सीटें किसी की भी ज्यादा आएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे की ओर से कोई बयान नहीं आया है। शिंदे समझ रहे हैं कि भाजपा मजबूत स्थिति में है और जिद करके अपना खेल खराब नहीं करना चाहते।

गेंद पूरी तरह से मोदी और शाह के पाले में

गेंद पूरी तरह से पीएम मोदी और शाह के पाले में है कि वह शिंदे और फडणवीस में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं, या कोई नया समीकरण सामने ले आते हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से शिंदे की नजदीकी भी छुपी नहीं है। शिंदे अपने व्यवहार से मोदी और शाह का दिल जीतने का प्रयास करते रहे हैं।

महायुति ने एससी, एसटी के आरक्षित अधिकतर सीटें जीतीं

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संविधान में बदलाव का नैरेटिव नहीं चला। महायुति ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षित अधिकतर सीटें जीतकर विपक्ष के इस नैरेटिव की हवा निकाल दी। इन सीटों पर महायुति की शानदार जीत लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद हुई है जब संविधान में बदलाव के नैरेटिव के सहारे महाविकास आघाड़ी (मविआ) ने सफलता हासिल की थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी नेता कह रहे थे कि संविधान को बदलने और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। विधानसभा चुनाव में विपक्ष का नैरेटिव नहीं चल सका। महायुति ने एससी के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 21 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 24 सीटों में से 21 सीटें जीतीं। इन 21 सीटों में से 10 भाजपा ने, छह शिवसेना ने और पांच राकांपा को मिलीं। कांग्रेस एसटी-आरक्षित सीटों में से दो जीतने में सफल रही, जबकि एक सीट माकपा ने जीती। जिन 21 एससी सीटों पर महायुति को जीत मिली उनमें से नौ भाजपा, पांच शिवसेना और छह राकांपा को मिलीं। एक सीट जन सुराज्य पार्टी ने जीती।

झारखंड में हेमंत की ताजपोशी पर देश देखेगा आइएनडीआइए का मेगा शो

प्रदीप सिंह ● जागरण

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 नवंबर को राजधानी के मोरहाबादी मैदान में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही चार बार यह पद ग्रहण करने वाले राज्य के अकेले नेता का खिताब उनके हिस्से होगा। सामान्य तौर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में करने की परंपरा है, लेकिन इस बार सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की जीत बड़ी है और समर्थकों के साथ-साथ कैडरों का उत्साह भी बढ़ाने वाली है। यही कारण है कि इस मौके को खास बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है।

समारोह स्थल चारों ओर से खुला है और यह बड़े कार्यक्रम के लिहाज से सबसे बेहतर स्थान भी है। राज्य में सभी दिशाओं से लोग यहां सहजता से पहुंच सकते हैं। यह बड़ा अवसर इस मायने में भी खास होगा कि हेमंत सोरेन भाजपा विरोधी तमाम प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को जुटाकर अपना दमखम दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा का विजय रथ रोकने वाले हेमंत सोरेन इसे मेगा राजनीतिक शो में तब्दील करना चाहेंगे ताकि प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के जुटान से पूरे देश में एक संदेश जाए। इसके साथ-साथ झामुमो और सहयोगी दलों कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा-माले के समर्थकों का उत्साह भी बढ़ाया जा सके। यही वजह है कि गठबंधन के विधायकों की बैठक में सहमति बनी कि बड़े मैदान में आयोजन हो। यही वजह है कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए चार दिनों का समय लिया गया, ताकि तैयारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेताओं के आने की भी पूरी संभावना रहे।

रांची में सीएम हाउस में नवनिर्वाचित आइएनडीआइए विधायकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन। एएनआइ

कई राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत

समारोह में कई गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उन्हें न्योता भेजा जा रहा है। हेमंत सोरेन राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली भी जा सकते हैं। जिन बड़े नेताओं के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है, उनमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, द्रमुक के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदि शामिल हैं।

आसान नहीं महाराष्ट्र का सीएम तय करना

नीलू रंजन ● जागरण

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में बंपर सीटें जीतने के बाद भी भाजपा नेतृत्व के लिए मुख्यमंत्री की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं होगा। एक तरफ सियासी रणनीति में शरद पवार जैसे दिग्गज नेता को मात देने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं, तो ढाई साल के सुशासन और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का असली उत्तराधिकारी बनकर उभरे एकनाथ शिंदे के दावे को भी खारिज नहीं किया जा रहा है। यह सबकी सोच है कि इस बड़ी जीत के पीछे लाड़ली बहना योजना का हाथ है और राज्य में इसे शिंदे के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। खुद भाजपा के अंदर भी कई नेता हैं जो यह मानते हैं कि शिंदे का व्यक्तित्व असर भी रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा तय करने के साथ ही रोटेशन पर भी चर्चा होगी। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। लिहाजा कोई फैसला होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। यह मामला दो तीन दिन से लेकर एक सप्ताह तक खिंच सकता है। नई सरकार बनने तक एकनाथ शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। ढाई साल पहले शिवसेना टूटने के बाद ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे और उन्होंने इसका एलान भी कर दिया था, लेकिन एक रणनीति के तहत केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उपमुख्यमंत्री के लिए तैयार किया, ताकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना समर्थक एकजुट हो सकें। यह रणनीति सफल रही और उद्धव ठाकरे गुट हाशिये पर आ गया। भले ही चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे को अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आधिकारिक रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया हो लेकिन एकनाथ शिंदे के दावे को खारिज करने के लिए 2014 और 2019 का तर्क दिया जा रहा है। 2014 में शिवसेना और भाजपा अलग-अलग लड़ी थी और सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद शिवसेना देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में सहजता से स्वीकार कर लिया था। वहीं 2019 में भाजपा ने स्पष्ट रूप से देवेंद्र फडणवीस को अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया था। इसी आधार पर भाजपा ने उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की मांग को अनुचित ठहराते हुए नकार दिया था। वहीं 2024 में 240 सीटों के साथ भाजपा सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर है। जाहिर है महाराष्ट्र में भाजपा को सरकार बनाने के लिए भले ही शिंदे की जरूरत नहीं हो, लेकिन लोकसभा में उनके आठ सांसदों की अहमियत से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद खतरे में मनसे की मान्यता

मुंबई, प्रेट्र: विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राजठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और चुनाव चिह्न खोने का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में हुए चुनाव में मनसे एक भी सीट जीतने में विफल रही।

राज ठाकरे।

महाराष्ट्र विधानमंडल के पूर्व सचिव अनंत कालसे ने बताया कि मान्यता के लिए किसी पार्टी को कम से कम एक सीट जीतनी होगी व कुल वोट शेयर का आठ प्रतिशत हासिल करना होगा। अथवा छह प्रतिशत वोटों के साथ दो सीटें या तीन प्रतिशत वोटों के साथ तीन सीटें जीतनी होंगी।

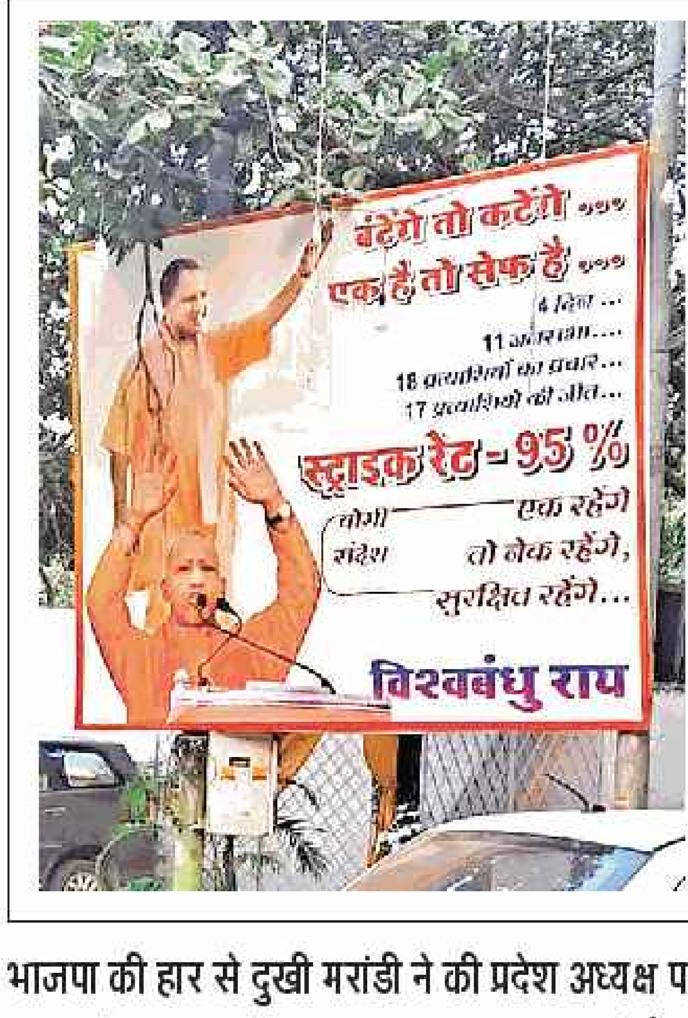

जीत के बाद मुंबई में लगे योगी के होर्डिंग

राज्य ब्यूरो, मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पोस्टर-होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। इनमें दर्शाया गया है कि योगी ने महाराष्ट्र में जहां-जहां सभाएं कीं, उनमें भाजपा की जीत का प्रतिशत 95 रहा है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 87 प्रतिशत है।

भाजपा की हार से दुखी मरांडी ने की प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। मरांडी ने पार्टी को मिली हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने का संदेश केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा राज्य की 81 में केवल 21 सीटें ही जीत पाई, जो पिछले विधानसभा चुनाव में मिली 25 सीटों से भी कम है। इस बार एनडीए गठबंधन को कुल 24 सीटें मिली हैं।

जदयू नेता सरयू के सुर बदले, कहा- हेमंत सरकार गिराने का प्रयास पड़ा भारी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

▸ बोले, झारखंड में भाजपा ने चरणबद्ध तरीके से की कई गलतियां

▸ सीएम के खिलाफ इतनी छोटी बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था

झारखंड में भाजपा की हार के बाद उसकी सहयोगी पार्टी जदयू के टिकट पर चुनाव जीते पूर्व मंत्री सरयू राय के भी सुर बदल गए हैं। सरयू राय ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा है कि उसे किसी स्वतंत्र एजेंसी के जरिए हार का आकलन करना चाहिए। लगे हाथ राय ने यह भी कहा है कि भाजपा को हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। यह विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की एक बड़ी वजह बनी, क्योंकि लोगों के बीच इससे गलत संदेश गया। भाजपा ने चरणबद्ध तरीके से कई गलतियां की।

सरयू राय के मुताबिक सबसे पहले जब माइंस आवंटन के लिए मई, 2022 में हेमंत सोरेन के विरुद्ध कार्रवाई हुई तो उन्होंने कहा था कि इससे हेमंत सोरेन को नुकसान नहीं होगा। सीएम के खिलाफ इतनी छोटी बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन भाजपा के लोगों ने उनकी सलाह को महत्व नहीं दिया। सरयू राय ने कहा कि उन्हें इसका अनुमान था कि हेमंत सोरेन सरकार बना सकते हैं, लेकिन इतना बहुमत आएगा और भाजपा को इतना अधिक नुकसान होगा, इसका आकलन नहीं किया था। उल्लेखनीय है कि झारखंड में भाजपा का निजी तौर पर प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। झामुमो से भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की सीट के अलावा कोई सीट नहीं जीत पाई है।

सरयू राय। जागरण आर्काइव

विस चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ेगी जन सुराज पार्टी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : बिहार विधानसभा की चार सीटों के उप चुनाव के परिणाम आने के बाद बाद प्रशांत किशोर (पीके) ने सोमवार को कहा कि हम अपने संकल्प एवं जन सुराज अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जन सुराज पार्टी (जसुपा) 2025 में सभी 243 सीटों पर अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी।

उन्होंने प्रेसवार्ता में कहा कि 23 नवंबर को तो परिणाम आया है, लेकिन पांच दिन पहले भी विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि चार से पांच प्रतिशत वोट जसुपा को आएगा। हम राजनीतिक विशेषज्ञों की टीका-टिप्पणी के आधार पर यह काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने संकल्प और जन सुराज के अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जनता को मनाने और समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है और भगवान ने जो शक्ति और बुद्धि दी है, उसे लगाएंगे। आगे भी यह प्रयास जारी रखेंगे।

तृणमूल कांग्रेस ने संसद में कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने के दिए संकेत

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

▸ अदाणी, वक्फ व संभल हिंसा जैसे मुद्दों पर साधी चुप्पी

▸ ममता की पार्टी ने की संसद सुचारू रूप से चलने की वकालत

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने संसद में कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने के संकेत दिए हैं। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जहां कांग्रेस ने लोकसभा व राज्यसभा में गौतम अदाणी, वक्फ संशोधन विधेयक व संभल हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई, वहीं तृणमूल ने इन मुद्दों पर चुप्पी साधते हुए कहा कि वह संसद सुचारु रूप से चलने के पक्ष में है। वह महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर में हिंसा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। पार्टी के इस बयान से साफ है कि वह संसद में कांग्रेस से किनारा करके चलेगी।

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से आइएनडीआइए सांसदों की बुलाई गई बैठक में भी तृणमूल का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। सोमवार को बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के कोलकाता के कालीघाट इलाके में स्थित निवास स्थल पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद वरिष्ठ महिला नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा-'हम चाहते हैं कि संसद सुचारु रूप से चले और मुद्दों पर चर्चा हो। प्रश्नोत्तर काल में हम महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर में हिंसा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।' अदाणी, वक्फ व संभल हिंसा जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख के बारे में पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सियासी विश्लेषक इसे हालिया संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन व बंगाल विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल के शानदार प्रदर्शन से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि ममता अब कांग्रेस को महत्व देने के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए संसद में भी अलग लाइन पर चलना चाहती हैं।

कल्याण बनर्जी। एएनआइ

कांग्रेस अहंकार छोड़ ममता को विपक्ष का नेता स्वीकार करे: कल्याण बनर्जी : कल्याण तृणमूल की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य व लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने मांग कि है कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़कर ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन की नेता स्वीकार कर लेनी चाहिए। कल्याण बनर्जी की इस मांग का पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं ने भी समर्थन किया है। कल्याण ने महाराष्ट्र में हार के लिए कांग्रेस की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को चुनौती देने के लिए एकजुट और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी के जमीनी जुड़ाव को विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे मुफीद बताया।

अभिषेक बनर्जी समेत छह बनाए गए राष्ट्रीय प्रवक्ता: तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी, लोकसभा सदस्य काकुली घोष दस्तीदार व कीर्ति आजाद, राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन, सुष्मिता देब व सागरिका घोष को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है।

बंगाल विस में घटी भाजपा की ताकत

राजीव कुमार झा ● जागरण

▸ उपचुनावों में अब तक सात सीटें हार चुकी हैं भाजपा, भाजपा विधायकों की संख्या 77 से घटकर 70 हुई

कोलकाता : बंगाल में वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन वह 77 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई थी। फिर भी 2016 में मात्र तीन सीटें जीतने वाली भाजपा ने 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीतकर पहली बार बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया लेकिन 2021 के चुनाव के बाद से राज्य में भाजपा की ताकत बढ़ने की बजाय बंगाल विधानसभा में पार्टी विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।

सिर्फ दल-बदल ही नहीं बल्कि उपचुनाव में भी भाजपा को एक के बाद एक करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। इस तालिका में नया नाम है अलीपुरदुआर जिले की मदारीहाट विधानसभा सीट का। 2021 के विधानसभा चुनाव में मदारीहाट सीट जीतने वाली भाजपा ने छह सीटों पर हुए उपचुनाव में करारी हार के साथ अपनी यह सीट भी गंवा दी। जिन छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के शनिवार को नतीजे आए, उनमें एकमात्र मदारीहाट सीट पर भाजपा ने 2021 में जीत हासिल की थी। बाकी पांच पर तृणमूल ने जीत हासिल की थी। इस बार तृणमूल ने सभी छह सीटों पर बंपर जीत दर्ज की है। भाजपा इससे पहले बागदा, रायगंज और धुपगुड़ी सीटें भी उपचुनावों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के हाथों हार चुकी है, जो पहले उसके पास थी। 2021 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भाजपा कूचबिहार और शांतिपुर सीट भी उपचुनाव में हार चुकी है। कुल मिलाकर, भाजपा ने पिछले तीन वर्षों में अपने कब्जे वाली सात विधानसभा सीटें खो दी हैं।

झारखंड में एसटी-एससी सीटें घटाई गईं तो ठीक नहीं होगा : झामुमो

राज्य ब्यूरो. जागरण ● रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को आशंका है कि राज्य में आदिवासी और अनुसूचित जाति की आरक्षित विधानसभा की सीटें घटाई जा सकती हैं। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करना सही नहीं होगा। पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में जनगणना प्रस्तावित है। उसके बाद परिसीमन भी होने वाला है। ऐसे में आशंका है कि साजिश के तहत आरक्षित सीटों पर इनका प्रहार होने जा रहा है, । भाजपा की कोशिश है कि झारखंड की आरक्षित सीटों की संख्या कम की जाए।

चम्पाई आवेदन दें तो विचार करेंगे

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो छोड़कर भाजपा में जाने वाले चम्पाई सोरेन अब अगर झामुमो में वापसी के लिए आवेदन देंगे तो इसपर पार्टी विचार करेगी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले जेएलकेएम (झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा) जयराम महतो की पार्टी के प्रति जनता ने विश्वास जताया है कि वह सरकार के साथ चलेंगे।

फैसला

अयोध्या के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उप्र हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने की वापस

मिल्कीपुर विस सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ

विधि संवाददाता ● जागरण

लखनऊ: अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मिल्कीपुर सीट से पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं वापस ले ली गईं। पूर्व विधायक व भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा व एक अन्य याची ने अपनी-अपनी याचिकाएं वापस लिए जाने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर करते हुए दोनों याचिकाओं को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने गोरखनाथ व शिव मूर्ति की ओर से दाखिल दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। पूर्व की सुनवाई में याचिका वापसी संबंधी अर्जी न्यायालय के समक्ष जब सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई थी तो प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए दलील दी कि अर्जी को तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर ही दाखिल कर दिया गया है। अर्जी की प्रति सभी प्रतिवादियों को उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही अर्जी का नियमानुसार आफिशियल गजट में प्रकाशन कराया गया है। न्यायालय ने इस दलील को सही पाते हुए याची के अधिवक्ता को आदेश दिया था कि वह अर्जी की प्रति सभी प्रतिवादियों को उपलब्ध कराएं तथा नोटिस के प्रकाशन के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे। नामांकन के दौरान अवधेश प्रसाद की ओर से दाखिल नोटरी को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उनके चुनाव को गोरखनाथ ने चुनौती दी थी। 26 अप्रैल 2022 को याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने याची के अंतरिम राहत संबंधी प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया था। इसी चुनाव को लेकर एक अन्य निर्वाचन याचिका भी शिव मूर्ति की ओर से दाखिल की गई थी। अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। इस कारण मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। मामला हाई कोर्ट में होने के कारण पिछले दिनों नौ सीटों के साथ यहां उपचुनाव नहीं हो सका था।

2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे

अवधेश प्रसाद। फाइल

****

मतदाता सूची में दोहराव रोकने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के दोहराव और उनमें कई प्रविष्टियों के आरोप की पड़ताल के लिए चुनाव आयोग और प्रदेश निर्वाचन निकायों को दिशा-निर्देश देने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि सर्वोच्च अदालत संपूर्ण प्रशासन के लिए दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकती है। खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता और पंजीकृत राजनीतिक संगठन राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ को अपनी मांगों और चिंताओं के साथ हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी है। ताकि वहां से वह उपयुक्त प्रशासन के खिलाफ अपनी याचिका दायर कर सकें। जनहित याचिका में मतदाताओं की प्रविष्टियों के दोहराव के खतरे का जिक्र किया गया है।

भरत सिंह सोलंकी की गुजरात कांग्रेस की राजनीति में वापसी की चर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● अहमदाबाद

पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी के गुजरात कांग्रेस की राजनीति में फिर सक्रिय होने की चर्चा जोरों पर है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर उनकी जन्मतिथि से पहले समर्थकों ने ''भरत सिंह कम बैक'' के पोस्टर - बैनर लगाए हैं। सोलंकी को पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाकर भेजा, लेकिन पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। भरत का राजनीतिक गढ़ गुजरात है। वह राज्य में फिर सक्रिय होना चाहते हैं। उनके समर्थकों ने उनकी जन्मतिथि से पहले पार्टी कार्यालय पर बधाई पोस्टर बैनर लगाए हैं, जिन पर लिखा है 'स्वर्ण युग कम बैक- भरत सोलंकी कमबैक'। सोलंकी की जन्मतिथि मंगलवार को है। सोलंकी ओबीसी समुदाय से आते हैं। गुजरात में इस समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से गुजरात में कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पा रही है।

भरत सिंह सोलंकी।

जन्मतिथि से पहले समर्थकों ने लगाए 'भरत सिंह कम बैक' के बैनर और पोस्टर

गुजरात भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं पाटिल : भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल आलाकमान के समक्ष दो बार अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जता चुके हैं। नए अध्यक्ष को अग्रिम बधाई देते हुए पाटिल ने कहा कि उपचुनाव में पार्टी की जीत ने फिर साबित कर दिया कि जनता सिर्फ विकास पसंद करती है, नकारात्मक राजनीति को नहीं।

22 नवंबर को एकल पीठ ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग के 18 में से नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की सशर्त इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि 31 मार्च तक होटल लाभ में नहीं आए तो आदेश का पुन: अवलोकन किया जाएगा।

संभल हिंसा पर राहुल-अखिलेश ने उप्र सरकार को घेरा, भाजपा बोली- ये अदालत पर हमला

विवाद ▶ राहुल ने कहा- फायरिंग के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार, संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट

उपचुनाव में गड़बड़ी छिपाने के लिए योगी सरकार ने संभल में दंगा कराया : अखिलेश

जेएनएन, नई दिल्ली

राहुल गांधी। फाइल

अखिलेश यादव। फाइल

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संभल में मस्जिद का सर्वे कराए जाने के विवाद में हुई हिंसा और फायरिंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उधर, भाजपा ने मुगलकालीन मस्जिद के निरीक्षण के लिए अदालत के आदेश को लेकर हुई हिंसा की निंदा की और मांग की कि अराजकता और अशांति फैलाने के लिए दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जगदंबिका पाल से लेकर मनोज तिवारी और रविशंकर प्रसाद से लेकर साक्षी महाराज तक तमाम भाजपा नेताओं ने 24 नवंबर को संभल जिले में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए इसे अदालत पर हमला बताया। संभल की फायरिंग और हिंसा पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि भाजपा का हिंदू-मुसलमान समुदाय के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए सत्ता का उपयोग करना न प्रदेश हित में है और न देश हित में। राहुल ने एक्स पोस्ट में उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- 'संभल में हालिया विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना। इसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़ कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े।' कांग्रेस नेतृत्व ने भी संभल मामले में राज्य सरकार के रवैये के खिलाफ जनता को जागरूक करते हुए प्रदेश में शांति कायम रखने के लिए अपनी उत्तर प्रदेश इकाई को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभल में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार के रवैये को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार प्रदेश और देश हित में नहीं।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में दंगा करवाया और मांग की कि मौतों के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के लोगों को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। यादव के अनुसार, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने उपचुनावों में गड़बड़ी की, वोट लूटे और इसे छिपाने के लिए संभल में उपद्रव करवाया। उधर, भाजपा ने अदालत के आदेश को लेकर हुई हिंसा की निंदा की और मांग की कि अराजकता और अशांति फैलाने के लिए दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा- "संभल में जो हुआ वह चिंताजनक है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर्वेक्षण दल न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहा था, फिर भी पत्थर फेंके गए। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की आवश्यकता है।"

देश में मंदिर-मस्जिद का विवाद वर्षों पुराना, इतिहास दे रहा गवाही

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

संभल में जामा मस्जिद और हरि हर मंदिर का विवाद वर्षों से चला आ रहा है। इसका इतिहास में भी उल्लेख है। इसी वर्ष प्रकाशित मंडलीय गजेटियर में बताया गया है कि अबुल फजल द्वारा रचित 'आइन-ए-अकबरी' में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख है।

संभल में पुराने शहर के मध्य में स्थित विशाल टीले, जिसे कोट अर्थात किला कहा जाता है, पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर होने का प्रमाण है। यहीं हरि हर मंदिर था। एचआर नेविल ने मुरादाबाद गजेटियर (1911) में लिखा है कि मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है। इसका स्थान एक मस्जिद ने ले लिया है। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जिसके अनुसार मस्जिद का निर्माण हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पर कराया था। हालांकि, मस्जिद बाबर के समय से पूर्व की प्रतीत होती है। मस्जिद के पश्चिमी छोर पर स्थित ढलानदार विशाल बुर्ज जौनपुर की इमारतों का स्मरण कराते हैं। भवन अत्यंत सादा एवं विशाल है। गजेटियर के मुताबिक मस्जिद के दक्षिणी प्रखंड में मौजूद अभिलेख के अनुसार रुस्तम खान दखिनी ने 1657 ई. में मस्जिद की मरम्मत करवाई। ऐसा ही अन्य अभिलेख उत्तरी प्रखंड में सैयद कुतुब (1626) के बारे में है। दो अभिलेख 1845 ई. के लगभग मस्जिद की मरम्मत का जिक्र करते हैं।

बाबर के सेनापति ने मंदिर को आंशिक रूप से कराया था ध्वस्त : 19 नवंबर, 2024 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर वाद में 26 बिंदुओं में संभल की भौगोलिक व ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बाबरनामा की डायरी का भी उल्लेख है। लिखा गया है कि बाबरनामा की डायरी के पेज संख्या 687 पर उल्लेख है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। बाबर के सेनापति ने उसके कहने पर श्री हरि हर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कराया, फिर उस पर कब्जा करके मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के अधीन है। वाद में कहा गया है कि एएसआइ ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, क्योंकि उक्त संपत्ति में जनता के प्रवेश के लिए कोई प्रविधान नहीं किया गया है। श्री हरि हर मंदिर भगवान कल्कि को समर्पित है। यह सदियों पुराना है। जिसे एक समिति, "जामी मस्जिद समिति संभल" द्वारा अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। इमारत को 22 दिसंबर, 1920 को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 3, उपधारा (3) के तहत अधिसूचित किया गया था।

▶ अबुल फजल द्वारा रचित 'आइन-ए-अकबरी' में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख

संभल स्थित शाही जामा मस्जिद। जागरण

इतिहासकार मीनाक्षी जैन का दावा, बाबर ने तुड़वाया था मंदिर

जासं, नई दिल्ली : प्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन ने भी दावा किया है कि विवादों में आई संभल की मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। इसके साक्ष्य मस्जिद से लेकर पुस्तक बाबरनामा तक में मौजूद है। मीनाक्षी जैन ने अपनी पुस्तक 'द बैटल आफ राम : केस आफ द टेंपल एट अयोध्या' में संभल में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद के निर्माण का विस्तार से जिक्र किया है। उनके अनुसार, कुछ वर्ष पूर्व तक मस्जिद में घंटी बंधी होती थी, जो हिंदू मंदिरों में होता है। इसी तरह मस्जिद के निर्माण में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ है, जिसे अब भी देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि बाबर ने भारत में कई मस्जिदें बनवाईं, जिसके लिए मंदिरों को तोड़ा गया। इनमें तीन मस्जिदें प्रमुख हैं। 1526 में उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया तो उसकी खुशी में वहां मस्जिद बनवाई, जो अब भी मौजूद है। दूसरी संभल में और तीसरी मस्जिद अयोध्या में बनवाई। बाबरनामा में भी इसका जिक्र है, जबकि मस्जिद में भी यह लिखा हुआ है।

19 नवंबर को कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का दिया था आदेश

प्रथम पृष्ठ से आगे

बीते 19 नवंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसी दिन सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था। 19 नवंबर को वीडियोग्राफी कराने के बाद टीम वापस आ गई थी। दूसरे चरण का सर्वे करने के लिए रविवार सुबह सात बजे एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव वादी व प्रतिवादी पक्ष के साथ मस्जिद पहुंचे और वीडियोग्राफी कराना शुरू की। इसी दौरान बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को रोका तो हिंसा भड़क गई। चार स्थानीय युवा नईम गाजी, बिलाल अंसारी, अयान अब्बासी और कैफ अल्वी की गोली लगने से मृत्यु हो गई। नोमान के स्वजन भी मृत्यु होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर, सीओ, एसपी के पीआरओ सहित दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

उपद्रवियों के पास थे दोधारी खंजर : बवाल करने वाले पूरी तैयारी से थे। उनके पास दोधारी खंजर भी थे। माना जा रहा है कि इसके लिए तैयारी कुछ दिन पहले ही की गई होगी। हिंसा के दौरान खदेड़े गए उपद्रवियों के जूते-चप्पल व अन्य सामान के साथ ही पुलिस को दोधारी खंजर जैसे हथियार मिले हैं। इसमें दोनों ओर चाकू की तरह तेज धार और बीच में पकड़ने के लिए मूठ बनाई गई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस कान्फ्रेंस में इसे दिखाया।

हिंसा करने वाले सरकार का बुलडोजर भी याद रखें : कश्यप : पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि कानून से खिलवाड़ की अनुमति किसी को नहीं है। जिन्होंने संभल में हिंसा की है या जो लोग इसके पीछे हैं, उन्हें सरकार का बुलडोजर भी याद रखना चाहिए। अधिकारी यह संदेश अपराधियों तक पहुंचा दें।

> ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बलवा करने वालों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
> -कृष्ण कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक, संभल

> अब संभल में शांति-व्यवस्था कायम है। पूरे मामले में साजिश समेत अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कराई जा रही है। संवेदनशील जिलों में खुफिया तंत्र को भी पूरी सक्रियता बरतने का निर्देश दिया गया है।
> -प्रशांत कुमार, डीजीपी

दादा की राह पर पोता भी, सांसद बोले-'अगर गोली चलेगी तो लोग पत्थर भी नहीं चलाएंगे'

जागरण संवाददाता, संभल

- सपा से सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने अपने खिलाफ केस के बाद दिया बयान
- पांच बार सांसद रहे दादा डा. शफीकुर्रहमान बर्क भी विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे थे
- संसद में वंदे मातरम का किया था विरोध,

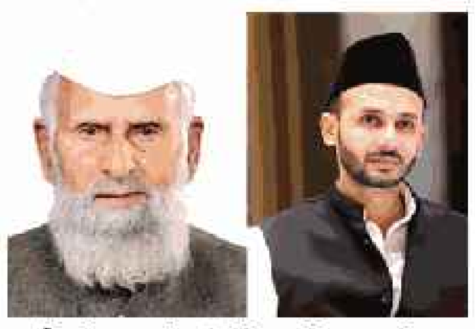
शफीकुर्रहमान बर्क और जियाउर्रहमान बर्क।

अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले डा. शफीकुर्रहमान बर्क की राह पर सपा से सांसद उनके पोते जियाउर्रहमान बर्क भी हैं। हिंसा भड़काने के आरोप में अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्होंने कहा है कि 'अगर एक तरफ से गोली चलेगी तो लोग पत्थर भी नहीं चलाएंगे?' उन्होंने कहा कि संभल की घटना के पीछे पुलिस प्रशासन का हाथ है। इसे योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की मदद नहीं कर सकूं, कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसके लिए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुझे अपने विरुद्ध दर्ज मामले से ज्यादा उन मासूमों की फिक्र है, जिनकी पुलिस प्रशासन ने हत्या की है। मुझे फिक्र है, उनकी जो दर्जनों की तादात में घायल हैं और जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है।

सांसद ने कहा कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के माध्यम से लोकसभा स्पीकर से मिले हैं और सदन में भी इस मामले को उठाएंगे। हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। जब एक सर्वे हो गया था तो दूसरा सर्वे करने की क्या आवश्यकता थी? इसके लिए समन्वय समिति बनानी चाहिए थी। इससे पूर्व कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को जामा मस्जिद में जियाउर्रहमान ने कहा था कि मैं कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हूं। ये मस्जिद है, मस्जिद ही कयामत तक रहेगी। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम इस देश के मालिक हैं, नौकर और गुलाम नहीं हैं। जियाउर्रहमान बर्क के दादा डा. शफीकुर्रहमान बर्क भी अपने जीवनकाल में विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने संसद में वंदे मातरम का विरोध किया और तालिबानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक बता दिया था। डा.शफीकुर्रहमान बर्क संभल और मुरादाबाद से पांच बार सांसद और चार बार विधायक रहे। इस वर्ष फरवरी में उनका निधन हो गया था। हिजाब का मामला सुर्खियों में आने पर डा. बर्क ने कहा था कि हिजाब हटने से लड़कियां आवारा हो जाएंगी। कोरोना की महामारी फैली तो इसे अल्लाह का कहर बताया। जनसंख्या वृद्धि पर कानून बनाए जाने की बात सामने आई तो बर्क ने बयान दे दिया कि बच्चे तो अल्लाह की रहमत हैं।

न्यूज गैलरी

डेरा प्रमुख की अपील पर हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

चंडीगढ़ : साध्वियों के यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा मुखी गुरमीत सिंह की सजा के खिलाफ अपील पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इसे 10 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआइ द्वारा समय मांगने पर फटकार भी लगाई। डेरे की दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में पंचकूला की सीबीआइ कोर्ट ने अगस्त 2017 में डेरा मुखी को दोषी करार देते हुए उसे 10-10 साल की सजा सुनाई थी और डेरा मुखी पर 30 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया था। (राब्यू)

कटारा से जुड़े मामले में आठ वकीलों पर एफआइआर

नई दिल्ली: नीतीश कटारा हत्याकांड के गवाह अजय कटारा को दुष्कर्म के फर्जी मामले में फंसाने के लिए जाली दस्तावेज के आधार पर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करने के लिए सीबीआइ ने आठ वकीलों, दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला व उसके पति के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कदम उठाया है। 17 फरवरी, 2002 को नीतीश कटारा की हत्या के लिए डीपी यादव के पुत्र और भतीजे को दोषी ठहराया गया था। शीर्ष कोर्ट में एसएलपी दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के पिता के नाम पर दाखिल की गई थी, लेकिन उन्होंने शीर्ष अदालत में कहा था कि गायब होने व 2013 में शादी करने के बाद से वह अपनी बेटी से नहीं मिले और अपनी बेटी से जुड़े मामले में वकालतनामे पर हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। बदायूं पुलिस ने भी अजय के विरुद्ध यह कहते हुए बंद कर दिया था कि कोई साक्ष्य नहीं मिला। अजय दिवंगत नीतीश के भाई हैं। (प्रेट्र)

कमजोर जनजातीय समूह के लिए 30 हजार घरों को मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीजीटी) के लिए 30 हजार से अधिक घरों को स्वीकृति प्रदान की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम-जनमन योजना के तहत लक्ष्य (4.9 लाख घर) को मार्च, 2026 तक हासिल किया जाना है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 297.18 किलोमीटर लंबाई की 76 सड़कों को भी स्वीकृति प्रदान की है। इन सड़कों की लागत 275.07 करोड़ रुपये है। (प्रेट्र)

बिहार में अल्पसंख्यकों पर ललन सिंह के बयान से गरमाई राजनीति

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

▶ विपक्ष बोला, ललन सिंह बोल रहे भाजपा और आरएसएस की भाषा

ललन सिंह। फाइल हरिभूषण बचौल। फाइल

केंद्रीय मंत्री व जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के अल्पसंख्यकों पर दिए बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है। बिहार विधान सभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को इस बयान पर सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने ललन सिंह के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यह सही नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय जदयू को वोट नहीं करता। नीतीश सरकार के मंत्री डा. अशोक चौधरी ने कहा कि ललन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं भाजपा के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि यह सच है कि मुसलमानों को विकास से कोई मतलब नहीं है। वह इस पर वोट नहीं करते हैं। वे 21वीं सदी में भी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर राजद नेता अख्तरूल इस्लाम शाहीन ने कहा कि ललन सिंह जदयू से अधिक भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा में भी उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था। एआइएमआइएम के अख्तरुल ईमान ने कहा कि किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना संविधान के खिलाफ है।

> **'नीतीश कुमार ने वोट के लिए समाज का काम नहीं किया'**
> केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सोमवार को दिल्ली में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोट के लिए कभी किसी समाज के काम को ध्यान में नहीं रखा। वह तो हर समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर में उनके संबोधन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक हमें वोट नहीं देते हैं।

कमजोर पकड़ी नक्सलियों की पकड़, माना- देशभर में 254 साथी मारे गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर : नक्सलियों ने भी मान लिया है कि सुरक्षा बलों की मजबूती से नक्सल तंत्र कमजोर पड़ा है। इस वर्ष देशभर में 254 नक्सलियों को जवानों ने मार गिया। इनमें सिर्फ बस्तर के 226 नक्सली शामिल हैं। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के स्थापना दिवस पर नक्सलियों ने पर्चा जारी कर नुकसान होना माना है। इसके मुताबिक, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी क्षेत्र के 226 नक्सली मारे गए हैं। इनमें 109 पुरुष व 81 महिलाएं हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में नये कैंपों की स्थापना से पुलिस फोर्स हावी रही है। इसकी वजह से नक्सल संगठन कमजोर पड़ा है और उन्हें अपने क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा है। इससे नक्सलियों की ओर से किए जाने वाले हमले कम हुए। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना का जिक्र किया है। बयान में लिखा है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद नए फारवर्ड आपरेशनल बेस कैंप स्थापित किए गए हैं। इन कैंपों के पांच किमी के दायरे में आने वाले गांवों को योजना में शामिल किया गया है।

हरियाणा सरकार ने 80 करोड़ में जर्मनी से खरीदा हेलीकाप्टर, कांग्रेस ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

▶ कांग्रेस ने राज्य पर चार लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज का दिया हवाला

भूपिंदर सिंह हुड्डा।

> भाजपा का पलटवार, क्या कांग्रेस राज में पहले इस तरह की सुविधा नहीं थी

हरियाणा सरकार ने करीब 80 करोड़ रुपये की कीमत का जर्मनी से नया हेलीकाप्टर खरीदा है। सोमवार को चंडीगढ़ में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से हिसार के लिए नये हेलीकाप्टर से उड़ान भरी। कांग्रेस ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पर चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्जा होने का आरोप लगाते हुए नए हेलीकाप्टर की खरीद पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने कहा है कि क्या इससे पहले यानी कांग्रेस के राज में ऐसी किसी सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

अंतरराज्यीय समझौते के तहत पंजाब और हरियाणा सरकार एक-दूसरे के हेलीकाप्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश में हेलीकाप्टर बदलने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। करीब दो साल पहले हेलीकाप्टर के पायलट और इंजीनियरों की टीम ने सरकार को नया हेलीकाप्टर खरीदने की सलाह दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान भी नया हेलीकाप्टर खरीदने को लेकर योजना बनाई गई थी लेकिन तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के सिर चढ़े कर्ज का हवाला देकर सरकार को घेर लिया था, जिसके बाद कुछ समय के लिए हेलीकाप्टर खरीद का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब जबकि भाजपा सरकार ने जर्मनी से नया हेलीकाप्टर खरीदा है तो हुड्डा ने फिर राज्य पर बढ़ा कर्ज होने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्ज कम करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए लेकिन लगातार कर्ज को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस बिना वजह मुद्दा बना रही है। वर्ष 2008 में हुड्डा सरकार के समय ही हेलीकाप्टर खरीदा गया था, जोकि पुराना होने की वजह से पिछले कुछ समय से दिक्कत कर रहा था।

सड़क पर आया उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद, पथराव में महिला घायल

संवाद सहयोगी, जागरण, उदयपुर : महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उदयपुर के पूर्व राजपरिवार के बीच विवाद सड़क पर आ गया है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक की रस्म के बाद वह धूणी के दर्शन के लिए सिटी पैलेस जा रहे थे। इस दौरान चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने उन्हें सिटी पैलेस में प्रवेश से रोकते हुए दरवाजे बंद कर दिए। अरविंद सिंह का परिवार महाराणा प्रताप का वंशज है और उन्होंने परंपरा निभाने से मना किया।

विश्वराज सिंह

विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थकों ने सिटी पैलेस के रास्ते पर लगे बैरिकेड हटा दिए और काफिले की छह गाड़ियां जगदीश चौक तक पहुंचीं, जहां पुलिस ने रास्ता रोक लिया। इस दौरान सिटी पैलेस के अंदर से पत्थरबाजी हुई और समर्थकों ने पुलिस का घेरा तोड़ दिया। पथराव में एक महिला घायल हो गई, जिसके सिर पर बोतल का प्रहार लगा था।

मनमुटाव

> हिमाचल प्रदेश सरकार के दो साल के काम को जनता के बीच पहुंचाएगा संगठन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बोर्ड व निगमों में ताजपोशी होनी चाहिए

हिमाचल सरकार के 'जन्मदिन' पर खटपट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● शिमला

कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर सह प्रभारियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करतीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। जागरण

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 11 दिसंबर को सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में करवाए जा रहे जश्न कार्यक्रम पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अभी उनके साथ इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार ने दो वर्ष में आपदा के बावजूद अच्छा काम किया है। पांच गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। महिलाओं को 1500 रुपये व पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। संगठन इसे जनता के बीच पहुंचाएगा। इससे पहले प्रतिभा सिंह के बेटे एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा था कि उन्हें सरकार के दो वर्ष के जश्न कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। उन्हें मीडिया से ही इसकी सूचना मिली है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बोर्ड व निगमों में रिक्त पदों पर ताजपोशी होनी चाहिए। प्रभारी भी इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद विभिन्न पदों पर तैनाती होगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। इसलिए ताजपोशी होनी चाहिए। सह प्रभारी संगठन के साथ सरकार के कामकाज का भी फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी नेता ब्लाक व जिला स्तर पर जाकर चर्चा करेंगे कि किस तरह के लोगों को आगे लाना है ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। फील्ड से फीडबैक लेने के बाद हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। संगठन में पद उन लोगों को ही मिलेगा, जो काम करेगा।

कांग्रेस को शंका, ईवीएम से होती है छेड़छाड़

ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव को लेकर पूछे प्रश्न के उत्तर में प्रतिभा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) की बैठकों में भी यह बात कई बार उठ चुकी है कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। उन्होंने कहा कि मतदान कैसे करवाना है, यह देखना चुनाव आयोग का काम है। कांग्रेस को शंका है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। ठोस साक्ष्य होंगे तो वह इस पर आगामी निर्णय लेगा।

****

एचपीटीडीसी को राहत, हिमाचल में बंद नहीं होंगे घाटे में चल रहे होटल

विधि संवाददाता, जागरण ● शिमला : हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के एकल पीठ के आदेश पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। एचपीटीडीसी को राहत देते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति लाभ में देरी से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। निगम ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि मृतक सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रितों को उनके तमाम सेवानिवृत्ति लाभ 10 दिन के भीतर व चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली राशि का 60 से 65 प्रतिशत लाभ एक माह के भीतर अदा कर दिया जाएगा। अगली सुनवाई तीन जनवरी 2025 को निर्धारित की है। एचपीटीडीसी ने हाई कोर्ट के नौ होटलों को बंद करने के आदेश को चुनौती दी है।

आरजी कर अस्पताल में एक्सपायर दवाओं की होती थी आपूर्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- एक्सपायरी हो चुकी दवाओं को खुदरा वितरकों को भेजा जाता
- तिथियां बदलकर दवाइयों की नई पैकिंग की जाती

संदीप घोष। फाइल

कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआइ को अस्पताल में एक्सपायर हो चुकी दवाओं की आपूर्ति के बारे में सुबूत मिले हैं। इस तरह के घातक अपराध का मास्टरमाइंड अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष था और पूरा घोटाला खुदरा वितरकों के एक वर्ग के जरिए किया जा रहा था। एक्सपायर हो चुकी दवाओं को नष्ट करने के बजाय खुदरा वितरकों को वापस भेज दिया जाता था, जिनका काम उन्हें नई एक्सपायरी तिथियों के साथ नई पैकिंग करना था। इसके बाद उन एक्सपायर हो चुकी दवाओं को अस्पताल को फिर से बेच दिया जाता था और घोष इस तरह के घातक जालसाजी को सुव्यवस्थित करने के लिए कमीशन के रूप में मोटी रकम कमाता था। सूत्रों ने बताया कि इस तरह की एक्सपायर दवाएं चेस्ट-मेडिसिन विभाग में भी आपूर्ति की जाती थीं। गवाहों ने जांच अधिकारियों को बताया है कि पीड़िता चेस्ट-मेडिसिन विभाग को आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता के बारे में सबसे मुखर थीं।

300 अशर्फियां और एक करोड़ रुपये नकद चोरी हुए हैं केरल के कन्नूर जिले के वालापट्टणम में। 19 नवंबर से बाहर रहे परिवार को रविवार रात घर लौटने पर पता चला।

न्यूज गैलरी

बिहार में पुलिस पर हमला, थानाध्यक्ष सहित चार चोटिल

दरभंगा : बिहार में दरभंगा जिले के नेहरा लुल्हवा चौक पर वाहन जांच के दौरान पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने लाठी-डंडे और रोड़ा से हमला कर दिया। इसमें नेहरा थानाध्यक्ष राजकिशोर राय, एसआइ रंजीत प्रसाद सिंह, सिपाही सानू कुमार और गृहरक्षक (होमगार्ड) छोटू कुमार चोटिल हो गए। 112 नंबर की पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो हमलावर भाग निकले इस दौरान दो लोगों को पुलिस ने दबोच लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि छह नामजद और 10- 15 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। इनमें गोविंद कुमार राय एवं नवीन कुमार राय को गिरफ्तार भी किया गया है। रविवार देर शाम वाहन चेकिंग अभियान के दौरान यह घटना हुई। वाहन को रोका गया और चालक से कागज दिखाने को कहा गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद पुलिस चालान काटने लगी तो गाड़ी में बैठे लोग बाहर निकले और पुलिस से ही भिड़ गए। (जासं)

नवी मुंबई में रह रहे चार बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

ठाणे : महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने एक बांग्लादेशी दंपती और उसके बेटे एवं बेटी को गिरफ्तार किया है। बेटे-बेटी की उम्र 20 और 22 वर्ष है। गुप्त सूचना पर नवी मुंबई पुलिस की मानव तस्करी विरोधी दस्ते ने जुहूगांव में एक आवास पर रविवार शाम छापेमारी की। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारत आने और यहां रहने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया। वाशी थाना अधिकारी ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग श्रमिक के रूप में काम करते थे और एक मछली बेचने का काम करता था। (प्रेट्र)

पाक की जेल में मृत मछुआरे का शव गुजरात लाया गया

पोरबंदर : पाकिस्तान की जेल में पिछले महीने जिस 31 वर्षीय मछुआरे हरिभाई सोसा की मौत हो गई थी उसका शव भारत लाया गया। गुजरात के जूनागढ़ के नानावाड़ा गांव में परिवार को हरिभाई का शव सौंप दिया गया। पोरबंदर निवासी हरिभाई को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 2021 में अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के समीप मछली पकड़ते हुए गिरफ्तार किया था। हरिभाई कराची जेल में तीन वर्ष जेल की सजा काट रहे थे। हृदय गति रुकने से 25 अक्टूबर को हरिभाई की मौत हो गई थी। (प्रेट्र)

भारत व पड़ोसी देशों में खपाने के लिए लाई जा रही थी मेथमफेटामाइन

प्रथम पृष्ठ से आगे

माना जाता है कि मेथमफेटामाइन भारत और उसके पड़ोसी देशों में तस्करी के लिए था। हमने संयुक्त पूछताछ के लिए अंडमान और निकोबार पुलिस को सूचित कर दिया है। यह पहली बार नहीं है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जलक्षेत्र में इस तरह की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई हो। 2019 और 2022 में भी विदेशी जहाजों से इसी तरह के नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे, जब वे भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे।

6.93 करोड़ मूल्य की नशीली याबा गोलियों की खेप जब्त

कोलकाता : बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक विशेष अभियान में मादक पदार्थों की बड़ी तस्करी को विफल कर दिया है। जवानों ने 6.93 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 69,347 नग प्रतिबंधित याबा गोलियों (एक प्रकार का ड्रग्स) की एक बड़ी खेप जब्त की है। बीएसएफ ने सोमवार को एक बयान में बताया कि एक पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर 102वीं बटालियन की सीमा चौकी (बीओपी) घोजाडांगा के जवानों ने इसे जब्त किया। तस्कर याबा गोलियों की खेप को सीमा पार कराकर भारत से बांग्लादेश में तस्करी की फिराक में थे। (राब्यू)

वैष्णो देवी में रोपवे परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ उग्र, तीन पुलिसकर्मी घायल

जिला प्रशासन के श्राइन बोर्ड से बात करने के आश्वासन के बाद 84 घंटे बाद हड़ताल स्थगित

थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल, सीआरपीएफ के वाहन को भी पहुंचा नुकसान

जागरण संवाददाता, कटड़ा

जम्मू स्थित कटरा में सोमवार को वैष्णो देवी की प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध कर रहे लोगों की पत्थरबाजी से बचने के लिए भागते पुलिसकर्मी। प्रेट्र

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की रोपवे योजना के विरोध में चल रहा प्रदर्शन सोमवार सुबह उग्र हो गया। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों मजदूर जुलूस की शक्ल में मजदूर यूनियन के प्रधान भूपेंद्र सिंह जम्वाल की अध्यक्षता में भवन मार्ग से होकर कटड़ा के मुख्य बस अड्डा पर पहुंचे और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सीआरपीएफ का एक वाहन वहां से निकलने लगा तो मजदूर आक्रोशित हो गए और पथराव करने लगे। इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पथराव में एसएचओ कटड़ा चमन गोरखा के साथ पुलिस के दो जवान अनवर खान तथा हरदीप सिंह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस बीच सीआरपीएफ तथा पुलिस ने स्थिति को काबू किया।

इस बीच प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर मुख्य बस अड्डा पर धरने पर बैठ गए। कुछ देर में रियासी के जिला उपायुक्त विशेषपाल महाजन, एसएसपी रियासी परमवीर सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे मजदूरों के नेताओं के साथ बातचीत की। दूसरी तरफ भवन मार्ग पर पंचायत पुराना दरूड व्यापार मंडल कमेटी ने डा. करण सिंह, सोहन सिंह के नेतृत्व में चौथे दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रहा। जिला उपायुक्त विशेष पाल महाजन ने बताया कि रोपवे को लेकर श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बातचीत कर उचित रास्ता निकाला जाएगा। मुआवजे जैसी मांगों पर दो से तीन दिन के भीतर चर्चा की जाएगी, ताकि मजदूरों और व्यापारियों को कोई नुकसान ना हो। जिला उपायुक्त के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित कर दी गई। शाम से श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर घोड़ा-पालकी की सेवाएं मिलने लगीं।

सभी के रोजगार का पूरा ध्यान रखा जाएगा : उपराज्यपाल

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ताराकोट मार्ग से सांझीछत के बीच 250 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना बना रहा है। बोर्ड का कहना है कि इससे यात्रा मार्ग पर करीब 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई से श्रद्धालुओं विशेषकर दिव्यांग व बुजुर्गों को राहत मिलेगी। वहीं इस मामले में श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि रोपवे परियोजना में सभी के रोजगार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जम्मू के मंडलायुक्त परियोजना को लेकर सहमति बनाने के लिए सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। अगर किसी की कोई जायज चिंता होगी, तो उसका निवारण अवश्य होगा, लेकिन विकास परियोजना से किसी तरह का समझौता नहीं होगा।

राजोआणा की दया याचिका संवेदनशील मामला : केंद्र

बेअंत हत्याकांड

- दया याचिका पर निर्णय में देरी का हवाला देते हुए सजा को आजीवन करावास में बदलने की मांग
- एएसजी ने कहा- सरकार मामले की समीक्षा कर रही, कोर्ट अब चार सप्ताह बाद करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 1995 में हुई पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे बलवंत सिंह राजोआणा की दया याचिका से संबंधित मामला संवेदनशील है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ राजोआणा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उसकी दया याचिका पर निर्णय में अत्यधिक देरी के कारण उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा- 'यह संवेदनशील मामला है। कुछ एजेंसियों से परामर्श करना होगा।' अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कहा कि सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि यह संवेदनशील मामला है, इसलिए इसमें कुछ और जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि वह चार सप्ताह बाद याचिका पर सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सचिव को निर्देश दिया गया था कि वह राजोआणा की दया याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष रखें।

पीठ ने 18 नवंबर की सुबह यह आदेश दिया था लेकिन सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से आग्रह किया था कि इस आदेश पर अमल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। मेहता ने पीठ को बताया था कि फाइल अभी गृह मंत्रालय के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राजोआणा को 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट मामले में दोषी पाया गया था। इस घटना में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 17 लोग मारे गए थे। जुलाई 2007 में विशेष अदालत ने राजोआणा को मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तीन मई को राजोआणा को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से इन्कार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सक्षम प्राधिकारी उसकी दया याचिका पर विचार कर सकते हैं।

मणिपुर में महिलाओं ने अफस्पा के विरोध में रैली निकाली

मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में हजारों महिलाओं ने सोमवार को अफस्पा के विरोध में रैली निकाली।

इंफाल, प्रेट्र : मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में कर्फ्यू आदेश को धता बताते हुए हजारों महिलाओं ने सोमवार को अफस्पा के विरोध में रैली निकाली। वे राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिनियम (अफस्पा) 1958 को हटाने की मांग कर रही हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य के छह थाना क्षेत्रों में अफस्पा लागू किया है। कोंग्बा बाजार से शुरू हुई महिलाओं की रैली को मुख्यमंत्री सचिवालय से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा बल के दस्ते ने रोक लिया। यहां से प्रदर्शनकारी महिलाएं सभा करने के लिए कोंग्बा लौट गईं। इसी जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (पांबेई गुट) के दो सक्रिय सदस्यों को फिरौती में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

सीजेआइ से झांसी मेडिकल कालेज अग्निकांड की जांच की अपील

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमित द्विवेदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कालेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में लगी आग की समयबद्ध जांच की मांग की है। इस अग्निकांड में 17 शिशुओं की मौत हो गई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले द्विवेदी ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लिखे पत्र में सरकारी अस्पताल के एनआइसीयू (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) में आग लगने की घटना की समयबद्ध जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक पैनल के गठन की मांग की। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में 15 नवंबर की रात को लगी भीषण आग से 39 नवजात शिशुओं को बचाया गया। आग की रात 10 शिशुओं की मौत हो गई, जबकि बाद में सात और शिशुओं ने दम तोड़ दिया था। पत्र में गंभीर लापरवाही की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया, जिसमें अग्निशमन यंत्रों का खराब होना भी शामिल है।

जुड़वां बच्चों व मां की एंबुलेंस में मौत, आक्सीजन नहीं मिलने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा

- छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का मामला, महिलाओं ने कराया प्रसव, स्थिति बिगड़ने पर गई सरकारी अस्पताल
- सीएमएचओ ने कहा- समय से पहले हुआ जन्म, आक्सीजन न होने से इन्कार

घर में प्रसव के बाद हालत बिगड़ने पर जुड़वां बच्चों के साथ मेडिकल कालेज लाई जा रही महिला और उसके नवजातों की एंबुलेंस में ही मौत हो गई। पति ने एंबुलेंस में आक्सीजन नहीं होने का आरोप लगाया है, जबकि मेडिकल कालेज प्रबंधन ने समय से पहले जन्म होने, प्लेसेंटा नहीं गिरने और अत्यधिक रक्त स्त्राव को मौत का कारण बताया है।

मामला कोरबा से 38 किलोमीटर दूर करतला विकासखंड के जोगीपाली का है। बिहारीलाल राठिया की पत्नी कांति राठिया को सोमवार सुबह प्रसव पीड़ा हुई। गांव की महिलाएं प्रसव करा रहीं थीं। प्रसव तो हो गया पर प्लेसेंटा बाहर नहीं आया। स्वजन प्रसूता और जन्म लेने वाले जुड़वां नवजात को लेकर करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां डेढ़ घंटे के प्रयास के बाद भी प्लेसेंटा बाहर नहीं आया। प्रसूता और बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने पर तीनों को सरकारी एंबुलेंस से मेडिकल कालेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही प्रसूता की सांस फूलने लगी। पति का आरोप है कि एंबुलेंस में आक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। आक्सीजन होती तो पत्नी और बच्चों की जान बच सकती थी।

कांति राठिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की जवाबदारी सौंपी है। कांति का प्रसव घर में कराया जाना सवालों के घेरे में है। सीएमएचओ डा. एसएन केसरी ने बताया कि जुड़वां बच्चों का जन्म समय से पहले हुआ। स्थिति जटिल थी। प्लेसेंटा भी बाहर नहीं आया था। सामुदायिक केंद्र में आपरेशन करने की व्यवस्था नहीं थी। मां और बच्चों को मेडिकल कालेज अस्पताल के लिए रेफर किया गया। तीनों को आक्सीजन के साथ एंबुलेंस से अस्पताल लाया गया।

गुजरात में किशोरी की हत्या में पकड़ा गया हरियाणा का सीरियल किलर

वलसाड, प्रेट्र : हरियाणा के रोहतक के रहने वाले राहुल जाट को कई राज्यों में हत्या के कई मामलों के बाद गुजरात के वलसाड जिले में एक 19 साल की लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह रेलवे स्टेशनों पर पटरियों के किनारे लोगों, खासकर महिलाओं को निशाना बनाता था।

पुलिस एसपी करनराज वघेला ने सोमवार को बताया कि विगत 14 नवंबर को आरोपित राहुल जाट को उडवाला रेलवे स्टेशन के पास एक 19 साल की लड़की का शव मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि शाम को लड़की जब ट्यूशन से घर लौटते समय रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही थी, तभी उस पर पीछे से हमला किया गया। उससे दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके शव वहीं पटरियों के किनारे फेंक दिया गया था। गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही राहुल जाट ने तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में एक महिला को लूटकर उसकी हत्या कर दी थी।

फेयरप्ले पोर्टल मामले में ईडी ने कुर्क की 219 करोड़ रुपये की संपत्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी ने एक वेबसाइट के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में करीब 219 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने सोमवार को बयान में कहा कि फेयरप्ले पोर्टल के खिलाफ पिछले सप्ताह मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अजमेर, कच्छ, दमन, ठाणे और मुंबई में स्थित भूखंडों, फ्लैट और वाणिज्यिक गोदामों जैसी अचल संपत्तियों और 'डीमैट खाता होल्डिंग' को कुर्क करने का आदेश दिया गया था। कुर्क संपत्तियों का मूल्य 219.66 करोड़ रुपये है।

फेयरप्ले पोर्टल 'क्रिकेट/आइपीएल मैचों के अवैध प्रसारण, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों सहित विभिन्न आनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था। ईडी ने इस मामले में पहले भी 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं। अब तक कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 331 करोड़ रुपये से अधिक है। मुंबई पुलिस साइबर सेल की प्राथमिकी के आधार पर मनी लांड्रिंग का यह मामला दर्ज किया गया था।

मुस्लिम पसर्नल ला बोर्ड का आरोप, वक्फ संपत्ति हड़पना चाहती है सरकार

- संयुक्त संसदीय समिति पर काम ईमानदारी से नहीं करने का भी आरोप
- भाजपा विधायक ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ पदयात्रा शुरू की

बेंगलुरु, प्रेट्र : आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (एआइएमपीएलबी) ने आरोप लगाया कि केंद्र का वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 देश भर में वक्फ संपत्तियों को "हड़पने" के लिए तैयार किया गया है। एआइएमपीएलबी के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) पर अपना काम ईमानदारी से नहीं करने का भी आरोप लगाया।

इलियास ने आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (एआइएमपीएलबी) के 29वें सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से कहा, "बोर्ड के सम्मेलन ने महसूस किया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देश भर में फैली वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए चतुराई से तैयार किया गया है।"

एआइएमपीएलबी के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा कि प्रस्तावित सभी 44 संशोधन और उनकी उप-धाराएं वक्फ संपत्तियों की स्थिति को "नष्ट करने और हेरफेर करने" के लिए तैयार की गई हैं।

उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि

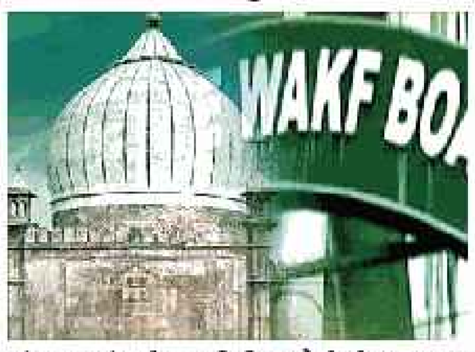

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है।"

इस बीच, विजयपुरा के भाजपा विधायक बासनगौड़ा पाटिल यतनमाल ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा शुरू कर दी है। बासनगौड़ा पाटिल यतनमाल ने कर्नाटक के किसानों की जमीनें हड़पने के नोटिस और मंदिरों पर दावा करने के वक्फ बोर्ड के नोटिसों के खिलाफ यह कदम उठाया है। यह यात्रा उत्तरी कर्नाटक से दक्षिणी कर्नाटक तक एक माह चलेगी।

वन्यजीव के हमले से मृत्यु पर दो किस्त में 25 लाख रुपये देगी मप्र सरकार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • भोपाल

- महाराष्ट्र सरकार की तरह ही वन्यजीव के हमले से मृत्यु पर मप्र में परिजन को मुआवजा राशि देने की तैयारी

मध्य प्रदेश में वन्य जीव के हमले से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आठ लाख रुपये के स्थान पर अब 25 लाख रुपये देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। वन विभाग मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार जंगलों में वन्यप्राणी के हमले में मरने वाले व्यक्तियों को 25 लाख रुपये हर्जाना देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें आर्थिक सहायता दो किस्त में दी जाएगी। वन्यप्राणी के हमले पर व्यक्ति की मृत्यु पर उसके स्वजन को तुरंत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। शेष 15 लाख रुपये की बैंक में एफडी की जाएगी। इसमें 10 लाख रुपये की एफडी पांच साल बाद और शेष पांच लाख रुपये की एफडी 10 साल बाद तोड़ी जाएगी। यह राशि मृतक के वारिसों को ब्याज सहित भुगतान की जाएगी। वर्तमान में वन विभाग के पास एक साल में जनहानि के करीब 40 मामले आते हैं, जिनमें मुआवजा देने के लिए करीब तीन करोड़ रुपयों का बजट रखा जाता है। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है।

वन्यजीव के हमले से पांच साल में 292 से अधिक लोगों की मौत : मध्य प्रदेश में बाघ-तेंदुआ सहित अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों के जंगल से बाहर निकलकर नजदीक की बस्ती में पहुंचने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे मानव-वन्यप्राणी द्वंद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले पांच साल में वन्यप्राणियों के हमले में 292 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वर्ष 2023-24 से अक्टूबर माह तक वन्यप्राणी के हमले से जनहानि, व्यक्ति के घायल होने और पशु हानि के प्रकरणों में 15 करोड़ तीन लाख रुपये की राशि पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की जा चुकी है।

मप्र से सटे राज्यों में अलग-अलग है मुआवजा राशि का प्रविधान

- **छत्तीसगढ़ :** जनहानि पर छह लाख व स्थाई अपंगता पर कुछ देय नहीं है।
- **उत्तर प्रदेश :** जनहानि पर पांच लाख रुपये, स्थाई अपगता पर चार लाख।
- **राजस्थान :** जनहानि पर पांच लाख रुपये, स्थाई अपंगता पर तीन लाख रुपये।
- **गुजरात :** जन्हानि पर पांच लाख रुपये, स्थाई अपंगता पर दो लाख रुपये।
- **महाराष्ट्र :** जनहानि पर 25 लाख रुपये एवं स्थाई अपंगता पर साढ़े सात लाख रुपये।

दिशा निर्देश

मेला प्राधिकरण की ओर से गाइडलाइन जारी, सुविधा पर्ची पर प्रिंट होंगे नियम व शर्तें, रात में 10 बजे से सुबह छह बजे तक नहीं बजाए जाएंगे लाउडस्पीकर, संस्थाओं के शिविरों में किसी प्रकार का नहीं किया जा सकेगा कारोबार

महाकुंभ में संस्थाओं को बोर्ड लगाना अनिवार्य

ज्ञानेंद्र सिंह • जागरण

प्रयागराज : संगम की रेती पर दिसंबर के अंत तक महाकुंभ नगर बस जाएगा। यहां आने वाली संस्थाओं के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से सोमवार को गाइडलाइन जारी की गई। इसके मुताबिक संस्थाओं को शिविर के गेट पर अपनी संस्था के नाम का बैनर, बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाना होगा, जिससे उसकी पहचान हो सके। संस्थाओं के शिविरों में आने वाले लोगों को फोटो आइडी रखनी होगी। ये नियम और शर्तें मेला प्रशासन की ओर से दी जाने वाली सुविधा पर्ची में भी प्रिंट कराई जा रही हैं। महाकुंभ में रात में 10 बजे के बाद से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर की ध्वनि का प्रभाव शिविर तक ही सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

9.5 हजार संस्थाओं को महाकुंभ मेला में दी जा रही जमीन और सुविधा

2700 के करीब नई संस्थाओं ने किया जमीन व सुविधा के लिए आवेदन

महाकुंभ मेला क्षेत्र में जमीन व सुविधा प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नियम व शर्तों के अनुसार ही संस्थाओं को अपने शिविर संचालित करने हैं। सभी नियम और शर्त सुविधा पर्ची पर अंकित कराए जा रहे हैं। शर्तों का उल्लंघन करने पर संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। **-विजयकिरन आनंद, महाकुंभ मेलाधिकारी**

महाकुंभ इस बार लगभग साढ़े नौ हजार संस्थाओं को जमीन व सुविधाएं दी जा रही है। 2700 नई संस्थाओं ने जमीन व सुविधा के लिए आवेदन किया है। नई संस्थाओं के लिए अलग से सेक्टर विकसित किया जा रहा है, जबकि पुरानी संस्थाओं को उनके स्थान पर ही जमीन देने की कोशिश हो रही है। अभी तक अखाड़ों, दंडी स्वामियों को जमीन आवंटित की जा चुकी है। आचार्य बाड़ा को भी जमीन दिखा दी गई है जिसके लिए मंगलवार को भूमि पूजन होगा। संस्थाओं को जमीन व सुविधा देने को लेकर मेला प्रशासन ने नियम व शर्तें भी लागू की है। कोई भी संस्था अपने शिविर में व्यवसाय नहीं कर सकती है। इसके अलावा शिविर में हीटर, ब्लोअर नहीं चलाए जाएंगे। प्रचलित धार्मिक मान्यताओं, विश्वासों, मर्यादाओं के खिलाफ कोई आचरण, प्रवचन व प्रसारण किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। संस्थाओं को मेला प्रशासन द्वारा प्रदत्त पंडाल मुख्य स्नान पर्वों पर आए श्रद्धालुओं के लिए खुला रखा जाएगा।

****

बिहार में शराब पीने से मना करने पर पत्थर से कूचकर पत्नी की हत्या

जासं, शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा जिले में एक युवक ने शराब पीने से मना करने पर पत्नी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी और शव व पांचों बच्चों समेत स्वयं को घर में अंदर से बंद कर लिया। हत्या के दौरान महिला और बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। आवाज लगाने पर भी अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया।

पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़वाया तो अंदर पांचों बच्चे बदहवास स्थिति में मां के शव से लिपटकर रोते मिले। जबकि आरोपित भाग निकला। शेखपुरा के करंडे थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव में हुई इस घटना में मृत महिला की पहचान 32 वर्षीया कुमकुम देवी के रूप में की गई, वहीं हत्या का आरोप पति देवन राम पर लगा है।

कश्मीर के शोपियां में मिले सात सौ वर्ष पुराने शिव मंदिर के अवशेष

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर

- पहाड़ी काटकर बनाए गए शिवलिंग की आकृतियां भी पाई गई
- जिला प्रशासन ने पुरातत्व विभाग से संरक्षण में मांगा सहयोग

दक्षिण कश्मीर में पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित शोपियां जिले के हीरपोरा में एक प्राचीन शिवमंदिर के अवशेष और पहाड़ी काटकर बनाए गए शिवलिंग की आकृतियां मिली हैं। यह मंदिर सात सौ वर्ष पुराना बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को इसके बारे में सूचित किया है। साथ ही ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर को लेकर जानकारी जुटाने और इसके संरक्षण में सहयोग के लिए कहा है।

राजौरी-पुंछ की तरफ से पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पार कर कश्मीर में दाखिल होते ही हीरपोरा शोपियां का पहला गांव है। समाजसेवी और ट्रैकर एजाज हुसैन ने बताया कि जिस जगह मंदिर के अवशेष और भगवान शिव को समर्पित शिवलिंग की आकृतियां मिली हैं, वह मुगल रोड से करीब तीन किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर एक जंगल के भीतर है। शिवलिंग की जो आकृतियां हैं वह एक बड़ी चट्टान के बीच में बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों कुछ स्थानीय युवक ट्रैकिंग के लिए इस इलाके में गए थे, उनके साथ कुछ इतिहास के छात्र भी थे। उन्होंने इसका पता लगाया है।

कश्मीर मामलों के जानकार डा. अजय च्रंगू ने कहा कि शोपियां के हीरपोरा में एक प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष और शिवलिंग की आकृतियां मिलना कश्मीर और सनातन संस्कृति के सदियों पुराने संबंध की पुष्टि करता है।

7.59 लाख रुपये मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के सिद्धार्थनगर के दो बैंक खातों में पहुंच गए। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की उदयपुर शाखा के दो खातों में रकम पहुंचने की जानकारी होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या ने खातों के संचालक पर रोक लगा दी।

ऐसे बना भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक

आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 24 प्रतिशत का योगदान देता है। किंतु एक समय भारत दूध की कमी वाला देश था। भारत के डेरी उद्योग को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। 26 नवंबर को 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' के अवसर पर आइए डालते हैं दूध उत्पादन में भारत की यात्रा पर एक नजर...

124 ग्राम प्रतिदिन थी 1950-51 में देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत

459 ग्राम प्रतिदिन हो गई 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता

श्वेत क्रांति के जरिये कुरियन ने बहाई दूध की नदिया

भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने में 1970 में डेरी इंजीनियर वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किए गए आपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आपरेशन में बिचौलियों को हटाकर यह सुनिश्चित किया गया कि उत्पादकों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत का बड़ा हिस्सा मिले। गुजरात के आणंद में डेरी किसानों की एक छोटी सी सहकारी संस्था, कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ को भारत के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक अमूल में बदलने वाले कुरियन के सहकारी माडल के आधार पर अन्य डेरी सहकारी समितियों का गठन किया जाने लगा। पूरे भारत में दूध उत्पादकों को 700 से अधिक कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया। इसके दो दशक के भीतर ही भारत का दूध उत्पादन दोगुने से भी अधिक हो गया और 1998 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया।

दूध उत्पादन में भारत की वर्तमान स्थिति

24.64% का योगदान दिया 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में

5.10% का योगदान देता है दूध उत्पादन देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में

30.01% तक की हिस्सेदारी पाने का लक्ष्य है 2030 तक वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में

23 करोड़ टन तक पहुंच गया वर्ष 2022-23 में भारत का दूध उत्पादन

तीन गुना से ज्यादा बढ़ी प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता

1950 और 1960 के दशक के दूध उत्पादन में भारत की स्थिति आज से पूरी तरह से अलग थी। भारत दूध पाउडर का आयात करता था और इसे तरल दूध में बदलकर मांगों को पूरा करता था। स्वतंत्रता के बाद पहले दशक के दौरान दूध उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 1.64 प्रतिशत थी, जो 1960 के दशक में घटकर 1.15 प्रतिशत रह गई। 1950-51 में देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत केवल 124 ग्राम प्रतिदिन थी। 1970 तक यह आंकड़ा घटकर 107 ग्राम प्रतिदिन रह गया, जो दुनिया में सबसे कम और न्यूनतम अनुशंसित पोषण मानकों से भी नीचे था। 2022-23 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन हो गई। इस वर्ष विश्व औसत 322 ग्राम प्रतिदिन था।

कूनो से फिर गूंजी किलकारी, 'निर्वा' ने जन्मे चार शावक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर

- कूनो में अब शावकों की संख्या 16, कुल 28 चीते हुए

मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से फिर अच्छी खबर आई है। यहां अफ्रीकी चीता निर्वा ने चार शावकों को जन्म दिया है। इसके बाद अब कूनो में शावकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। वयस्क 12 चीतों को मिलाकर यहां 28 चीते हो गए हैं। हालांकि कूनो प्रबंधन ने आधिकारिक रूप से इस बारे में अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की है। कूनो से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बड़े बाड़े नंबर छह में रखी गई निर्वा का प्रसव 22 नवंबर को हुआ। बता दें चीता का गर्भकाल 90 से 92 दिन होता है। निर्वा का गर्भकाल 19-20 नवंबर को पूरा हो रहा था।

उल्लेखनीय है कि देश में चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट के तहत 17 सितंबर, 2022 को नामीबिया से आठ चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं अपने जन्मदिन पर इन चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा था। दिसंबर, 2022 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते यहां लाए गए। चीता निर्वा इनमें से एक है।

न्यूज गैलरी

हिरासत में महिलाओं की प्रताड़ना की एसआइटी जांच हो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में दो महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले की एसआइटी जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमित रूप से सीबीआइ को जांच का जिम्मा सौंपने से न केवल केंद्रीय एजेंसी पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, बल्कि राज्य पुलिस के अधिकारियों का मनोबल भी गिरता है। एसआइटी को साप्ताहिक आधार पर हाई कोर्ट को जांच की प्रगति पर रिपोर्ट सौंपनी होगी। (प्रेट्र)

अंतिम दर्शन को रखा गया कृपालु महाराज की बेटी का शव

वृंदावन (मथुरा): जगद्गुरु कृपालु जी महाराज की बड़ी पुत्री और जगद्गुरु कृपालु परिषत की अध्यक्ष डा. विशाखा त्रिपाठी का पार्थिव शरीर सोमवार को वृंदावन पहुंचा तो अनुयायी बिलख पड़े। प्रेम मंदिर से सटे कृपालु धाम के प्रेम भवन में पार्थिव शरीर अनुयायियों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इस दौरान दिन भर अनेक अनुयायी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। दुर्घटना में घायल छोटी बहन डा. श्यामा त्रिपाठी भी एंबुलेंस से पहुंच गईं, जबकि दूसरी बहन कृष्णा का अभी दिल्ली में उपचार चल रहा है। (जासं)

महाराष्ट्र में ढाबे पर कहा-सुनी के बाद दो गुटों में संघर्ष

बुलढाणा : महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मेहकार कस्बे में सड़क किनारे ढाबे में दो लोगों के बीच कहा-सुनी होने के बाद दो गुटों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी। इस मामले में दोनों तरफ के 23 लोगों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक बाबूराव महामुनी ने सोमवार को बताया कि रविवार रात दो लोगों के बीच तीखी बहस हुई थी। इसके बाद मेहकार में दो गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। (प्रेट्र)

राजौरी में आतंकी मामले में चार जगहों पर छापेमारी

राजौरी : आतंक से जुड़े मामले पर सोमवार को पुलिस ने जिले में चार जगहों पर छापेमारी कर आपत्तिजनक सामग्री व दस्तावेज बरामद गए। इस संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार छापेमारी पुलिस स्टेशन थन्नामंडी में दर्ज केस एफआइआर संख्या 95/2013 और पुलिस स्टेशन राजौरी में दर्ज केस एफआइआर संख्या 447/2024 से जुड़ी जांच के हिस्से के रूप में की। दोनों मामले राजौरी में सक्रिय आतंकी नेटवर्क से संबंधित हैं, जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की मिलीभगत से जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों से जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार थन्नामंडी, दरहाल, कालाकोट व मंजाकोट में छापेमारी में आतंक से जुड़े दस्तावेज बरामदगी के दावे किए जा रहे हैं। (जासं)

सहकारिता के लिए वैश्विक वित्तीय संस्था बनाने की जरूरत : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया दिल्ली में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन

महिलाओं की तरक्की के लिए सहकारी समितियों को अहम बताया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में सोमवार को वैश्विक सहकारिता सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्मृति चिह्न भेंट करते केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनियाभर के सहकारिता प्रतिनिधियों से कहा कि सहकारी भावना ही तरक्की की प्राण-शक्ति है। दुनिया के लिए यह माडल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए संस्कृति का आधार और जीवनशैली है। मोदी ने सहकारिता क्षेत्र के संसाधनों के अनुरूप उपयोग वाले अर्थतंत्र (सर्कुलर इकोनमी) से जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन की जरूरत पर जोर दिया। मोदी दिल्ली के 'भारत मंडपम' में सोमवार को छह दिनों तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आइसीए) के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 की शुरुआत भी की। सहकारिता के शीर्ष संगठन आइसीए के 130 वर्षों के इतिहास में भारत में पहली बार आम सभा का आयोजन किया जा रहा है।

पीएम ने आइसीए को सुझाव दिया कि वैश्विक स्तर पर हमें ऐसी वित्तीय संस्था बनाने पर विचार करना चाहिए, जो पूरी दुनिया की सहकारी संस्थाओं की आर्थिक मदद कर सके। सहकारिता को अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। आइसीए ऐसा कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर चर्चा की जा सकती है।

पीएम ने कहा कि भारत अपने भविष्य के विकास में सहकारी समितियों की बड़ी भूमिका देखता है। पिछले 10 वर्षों में देश ने सहकारी समितियों से संबंधित परिवेश को बदलने के लिए काफी काम किया है। हमारा प्रयास सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय बनाना है। यह आवास क्षेत्र के साथ बैंकिंग में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। दो लाख आवासीय सहकारी समितियां सक्रिय हैं। बैंकिंग में भी व्यापक सुधार हुआ है। इनमें लगभग 12 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। अर्थव्यवस्था को तेजी से विस्तार मिल रहा है। हमारा लक्ष्य उच्च जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त कर गरीबों तक लाभ पहुंचाना है।

मोदी ने सहकारी संस्थाओं को दुनिया के लिए बड़ा अवसर बताया और कहा कि मानवता के सम्मान के लिए इन्हें आगे आने की जरूरत है। महिलाओं की तरक्की के लिए उन्होंने सहकारी समितियों को अहम बताया और कहा कि इनकी करीब 60 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं, जिनके दम पर सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ रहा है। देश में आठ लाख से ज्यादा सहकारी संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों में लगभग 10 करोड़ महिलाएं हैं। भारत का मानना है कि सहकारिता वैश्विक सहयोग को नई ऊर्जा दे सकती है। खासकर अफ्रीकी देशों को उस तरह की आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद कर सकती है, जिसकी उन्हें जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए गांवों में दो लाख अतिरिक्त बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं। ऐसे सारे गांवों में सहकारिता समितियों की स्थापना की जाएगी, जो अभी तक इससे वंचित हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सहकारिता की दिशा तय करेगा और दुनियाभर की सहकारिता संस्थाओं को नई ऊर्जा देगा।

इससे पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इफको, कृभको व अमूल की सराहना करते हुए कहा-तीनों संस्थाएं दुनिया की सहकारी संस्थाओं को प्रेरित करेंगी। भारत सहकारिता की पहुंच बढ़ाने को तैयार है। हम कुछ दिनों में ही सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम को भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोबगे व फिजी के डिप्टी पीएम मनोआ कामिकामिका ने संबोधित किया।

अधूरे पुल से तीन की मौत : चार इंजीनियर जिम्मेदार, गैरइरादतन हत्या में केस दर्ज

जागरण संवाददाता, बरेली

- बदायूं के नायब तहसीलदार ने कराई प्राथमिकी, गूगल मैप प्रबंधन की लापरवाही भी मानी

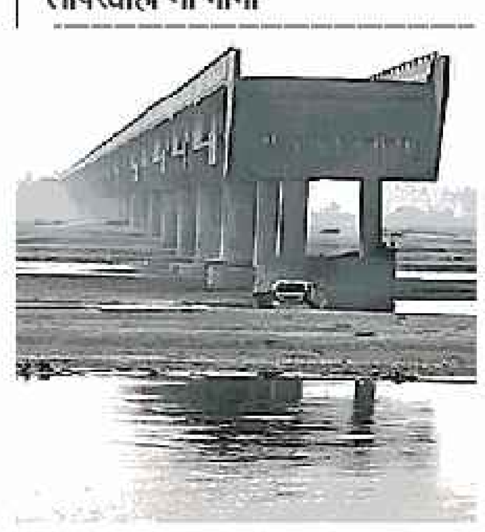

बरेली-बदायूं को जोड़ने के लिए रामगंगा पर अधूरा पुल। इससे गिरकर कार सवार तीन युवकों की मौत हुई थी। जागरण

बरेली में अधूरे पुल से गिरकर कार सवार तीन युवकों की मृत्यु में प्रथम दृष्टया लोक निर्माण विभाग के चार अभियंताओं को जिम्मेदार माना गया है। सोमवार को दातागंज (बदायूं) के नायब तहसीलदार छविराम सिंह ने सहायक अभियंता मोहम्मद आरिफ, अभिषेक और अवर अभियंता अजय गंगवार, महाराज सिंह व अज्ञात पर गैरइरादतन हत्या की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कराई। उन्होंने तहरीर में लिखा कि पुल बंद होने के बावजूद गूगल मैप पर रास्ता दिख रहा, इसलिए गूगल मैप के प्रबंधक पर भी कार्रवाई हो। इसपर दातागंज के इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई ने बताया कि गूगल के कार्यालय से ई-मेल के जरिये संवाद किया जाएगा। विवेचना में जो तथ्य मिलेंगे, उसी आधार पर अज्ञात के स्थान पर नाम बढ़ाए जाएंगे।

फरीदपुर (बरेली) और दातागंज (बदायूं) को जोड़ने के लिए रामगंगा नदी पर 46.10 करोड़ रुपये से वर्ष 2022 में पुल बनवाया गया था। इसके फरीदपुर छोर का 1600 मीटर का संपर्क मार्ग वर्ष 2022 की बाढ़ में आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन 2023 की बाढ़ में पूरी तरह बह गया। दूसरी ओर, दातागंज छोर से 700 मीटर का संपर्क मार्ग एवं 700 मीटर का पुल ठीक था। उस तरफ से कोई वाहन न आए, इसलिए अभियंताओं ने दो फीट की दीवार तो बनाई, लेकिन एक-एक कर उसकी ईंटें गायब होती गईं और जिम्मेदार आंख बंद किए रहे। वहां संकेतक भी नहीं लगे थे। शनिवार रात को गुरुग्राम से फरीदपुर जा रहे अजीत, उनके चचेरे भाई नितिन व दोस्त अमित को इसका आभास नहीं था। उनकी कार (किराए पर चलने वाली टैक्सी) दातागंज छोर से पुल पर चढ़ी और 22 फीट नीचे जा गिरी, इसमें तीनों की मृत्यु हो गई।

सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में जांच कर इसकी रिपोर्ट देने के आदेश दिए। इसके बाद स्थानीय मुख्य अभियंता अजय कुमार सक्रिय हुए। उन्होंने बदायूं-पीलीभीत के अधीक्षण अभियंता केके सिंह को जांच सौंपी।

जौनपुर में इमामबाड़ा व कब्रिस्तान के विवाद में 36 घंटे बाद दफन हुआ शव

जागरण संवाददाता, जौनपुर

- जिसने विवादित जमीन पर शव दफन न करने का समझौता किया था, उसके निधन के बाद विवाद
- शिया वर्ग के लोगों ने शव दफनाने की इजाजत नहीं दी

इमामबाड़ा व कब्रिस्तान की भूमि के विवाद में दो वर्ष पूर्व समझौता करने वाले वृद्ध का रविवार को निधन हो गया। इसके बाद मुस्लिमों के ही दो पक्षों के बीच फिर टकराव की नौबत आ गई। शिया मुसलमानों ने समझौते के अनुसार शव विवादित भूमि में दफन करने से रोक दिया। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के समझाने पर सोमवार को स्वजन गांव के सार्वजनिक कब्रिस्तान में शव दफनाने पर राजी हो गए। विवाद के चलते लगभग 36 घंटे बाद शव दफनाया जा सका।

लंबे समय से बीमार जौनपुर बाजार निवासी 80 वर्षीय नखड़ू मियां का रविवार सुबह 10 बजे निधन हो गया था। स्वजन शव उसी भूमि में दफनाना चाहते थे, जिसे शिया मुसलमान इमामबाड़ा की भूमि का हिस्सा बता रहे थे। शिया वर्ग के लोगों ने शव दफनाने की इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ नखड़ू के स्वजन का कहना था कि कई दशक से इसी निजी कब्रिस्तान में उनके परिवार के लोगों के शव दफनाए जाते रहे हैं। लगभग दो वर्ष पूर्व नखड़ू की पत्नी का शव भी काफी विवाद के बाद इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उस समय भी शिया पक्ष के लोग भूमि को इमामबाड़ा का हिस्सा बताते हुए रोक रहे थे। सोमवार को पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने नखड़ू मियां के स्वजन को समझाया कि जब उन्होंने खुद दो वर्ष पूर्व स्टांप पर लिखकर दे दिए थे कि भविष्य में शव उक्त विवादित स्थान पर दफन नहीं करेंगे तो जिद छोड़ दें। नखड़ू मियां के स्वजन जिलाधिकारी के यहां भी गए, लेकिन यही जवाब मिला। दोपहर में एसडीएम व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के प्रयास के बाद स्वजन ने गांव के सार्वजनिक कब्रिस्तान में शव दफन किया।

सूझ बूझ से हल किया विवाद : नायब तहसीलदार डोभी हुसैन अहमद एवं कानूनगो हनमत तिवारी व चौकी इंचार्ज मुफ्तीगंज युगल किशोर राय की सूझबूझ से 36 घंटे बाद विवाद हल किया गया। अन्य कब्रगाह पर स्थानांतरित करते हुए मृतक नखड़ू के शव को कब्रगाह उदीयासन मुफ्तीगंज रेलवे के समीप गड्ढा खुदवा कर उसमें दफन करने की बात तय हुई और दफन कर दिया गया और इसी के साथ विवाद का समापन हो गया।

फोन टैपिंग में राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत का ओएसडी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। घंटों पूछताछ के बाद उन्हें कार्यालय से ही जमानत पर छोड़ दिया गया।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मार्च, 2021 में दिल्ली पुलिस आयुक्त से लोकेश शर्मा के खिलाफ फोन टैपिंग की शिकायत की थी। क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मुकदमा दर्ज होते ही लोकेश दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। उनके आवेदन पर विचार कर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस रोक के हटने पर लोकेश ने दूसरी याचिका दायर कर केस को राजस्थान ट्रांसफर करने का आग्रह किया था। हालांकि बाद में उन्होंने याचिका वापस ले ली। सोमवार को क्राइम ब्रांच ने प्रशांत विहार स्थित अपने कार्यालय में घंटों पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने आरोप लगाया था कि लोकेश शर्मा सहित तत्कालीन कुछ भ्रष्ट पुलिस अफसरों ने उनका फोन टैप किया था। पूछताछ में लोकेश ने कहा कि फोन टैपिंग में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

भारत-पाक सीमा पर बदले हालात, तारबंदी के आगे धरती उगलेगी सोना

जागरण संवाददाता, कठुआ

- कठुआ में सीमा के पास की 300 एकड़ भूमि पर खेती शुरू करने की तैयारी
- वर्ष 2000 में पाकिस्तान की गोलाबारी के कारण किसानों ने पर बंद कर दी थी खेती

प्रतीकात्मक।

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फिजा बदली हुई है। दो दशक से अधिक समय बाद तारबंदी के आगे बंजर पड़ी जमीन पर गेहूं की फसल तैयार करने की तैयारी चल रही है। इसमें बीएसएफ भी स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहा है। वर्ष 2019 से पहले दो दशक से सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के कारण तारबंदी के आगे की जमीन बंजर हो चुकी थी। सब जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) हीरानगर राकेश शर्मा और मुख्य जिला कृषि अधिकारी संजीव राय गुप्ता ने सीमा चौकी मनियारी का दौरा किया। इसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों के किसानों को रबी सीजन 2024-25 के लिए अधिक भूमि पर गेहूं की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना और सीमा पर अप्रयुक्त भूमि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था। मनियारी, कड़ियाला और गुजनाल गांवों के किसानों से बातचीत की गई और बीएसएफ की तरफ से भी किसानों को सुरक्षा संबंधी आश्वासन दिए गए हैं।

पहली बार मनियारी सीमा चौकी में तारबंदी के आगे की गेहूं कि बिजाई की जाएगी, जिसमें लगभग 750 एकड़ अप्रयुक्त भूमि में से 300 एकड़ भूमि पर खेती की जाएगी। सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों की जमीन गेहूं की खेती के अंतर्गत लाई जाएगी। मुख्य कृषि अधिकारी संजीव राय ने कहा कि तारबंदी के पार जमीन के मालिकों की पहचान कर रहे हैं। खाली जमीन को खेती के अंतर्गत लाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीमा सुरक्षा बल के द्वितीय कमान अधिकारी रविंद्रन ने सहयोग देने का आश्वासन दिया। बता दें कि वर्ष 2000 में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी किए जाने से तनावपूर्ण माहौल के चलते किसानों ने तारबंदी के आगे की जमीनों पर खेती करना बंद कर दिया था।

बेटियों के नाम से जाना जाएगा पिथौरागढ़ के बड़ालू गांव का हर घर

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़ : बिटिया बाबुल की जान है। वह है तो घर चहकता है और जब ससुराल के लिए विदा होती है तो बाबुल रोता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ नारे से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का बड़ालू गांव एक नजीर बन रहा है। इस गांव के हर घर की पहचान अब बेटियों से होगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस घर में बेटियां हैं, उस घर के मुख्य द्वार पर उन्हीं के नाम की पट्टिका लगेगी। गांव में 160 लड़कियां हैं। 288 परिवारों में 988 लोग रहते हैं। जिस परिवार में एक से अधिक बेटियां हैं, वहां सबसे छोटी बेटी का नाम पट्टिका में दर्ज होगा। जिन परिवारों में बेटियां नहीं हैं, वह मातृछाया सदन बनेगा। यानी घर की मां का नाम पट्टिका पर अंकित होगा। बड़ालू के ग्राम प्रधान दिवाकर जोशी ने एक कोशिश की तो पूरे गांव का साथ मिला और लोग अपनी लाडली के नाम से घर को पहचान दिलाने के लिए तैयार हो गए।

अब तक 185 नामों की पट्टिका तैयार कराई जा चुकी है। इसे बनाने के लिए उत्तराखंड की लोकविधा ऐपण का सहारा लिया गया है। ऐपण उकेरने के बाद मध्य में बेटियों का नाम लिखा गया है। कुल परिवारों के आधार पर 288 पट्टिकाएं तैयार होनी हैं।

जागरण विशेष

मतांतरण रोक 20 हजार से अधिक का संरक्षित किया स्वतंत्रता का अधिकार

जनजाति कल्याण केंद्र मप्र के डिंडौरी में 29 वर्ष से चला रहा मुहिम, पांच लाख से अधिक लोगों का इलाज करा दिया स्वास्थ्य का अधिकार

आशीष शुक्ला • नईदुनिया

डिंडौरी: देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में दबाव डालकर मतांतरण के लिए मजबूर कर लोगों को इससे वंचित किया जा रहा था। ऐसे में जनजाति कल्याण केंद्र ने 29 वर्ष पहले आदिवासियों और संरक्षित जनजाति बैगा को ईसाई मिशनरियों के जाल से बचाकर इनके अधिकारों का संरक्षण शुरू किया। केंद्र अब तक 20 हजार से अधिक को इनके जाल से बचा चुका है। स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करते हुए पांच लाख से अधिक लोगों का निश्शुल्क इलाज करा चुका है।

जनजाति कल्याण केंद्र शिक्षा, जैविक कृषि, वाचनालय, स्वावलंबन, गोशाला, युवा आयाम, कौशल विकास, पर्यावरण व जल संरक्षण, कैरियर गाइडेंस, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा, अन्न और सिकल सेल जैसे प्रकल्प पर कार्य कर रहा है।

बात 1995 की है, जब क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता था, ऐसे में जनजाति कल्याण केंद्र की स्थापना की गई, जिसने दबाव डालकर कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने को स्वस्थ्य समाज की दिशा में कदम बढ़ाए। इसमें गरीब, जरूरतमंद और मजबूर लोगों का शिविर लगाकर इलाज किया गया। अब भी दिल्ली, नागपुर और हैदराबाद जैसे महानगरों से डाक्टरों की टीम प्रत्येक माह के एक रविवार को जिले में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविर में पहुंचती है। प्रतिवर्ष मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी होता है। इनका संचालन जनसहयोग और प्रशासन की मदद से होता है।

कई तरह की बीमारियों का निश्शुल्क इलाज: केंद्र से जुड़े डा. संतोष शुक्ला बताते हैं कि केंद्र से जुड़े डाक्टर अपनी पूरी टीम के साथ यहां जनसेवा करते हैं। केंद्र के सहयोग से सिकल सेल एनीमिया के अलावा कैंसर, टीबी, नेत्र रोग सहित कई तरह की बीमारियों का निश्शुल्क इलाज होता है। आवश्यक होने पर मरीज को महानगरों में केंद्र से जुड़े अस्पतालों में भेजकर आपरेशन भी कराया जाता है। पंजीकृत मरीजों का फालोअप भी किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की ओर से कराए जाने वाले इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं है। जन सहयोग से ही सभी कार्य होते हैं। मरीजों को दवाइयां भी मुहैया कराई जाती हैं। शिविर में आने वाले महानगरों के डाक्टर निश्शुल्क इलाज करते हैं। जनजाति कल्याण केंद्र का जब से दायित्व अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले द्वारा संभाला गया है, तब से इन कार्यों में और तेजी आई है।

सेवा देने वाले शिक्षक ने सर्जरी कराकर संवारा जीवन

जनजाति कल्याण केंद्र में शहपुरा जनपद के ग्राम दूबा रैयत निवासी 10 वर्षीय आदिवासी बालिका दसोदिया बाई खाना बनाते समय झुलस गई थी। शिविर में प्रारंभिक इलाज के बाद यहां सेवा देने वाले शिक्षक अश्वनी साहू द्वारा जबलपुर के निजी अस्पताल में ले जाकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई गई। इससे बच्ची को एक तरह से नया जीवन मिल गया।

सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष पहल

डिंडौरी में सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी वर्षों से बड़ी समस्या है। ऐसे में जनजाति कल्याण केंद्र द्वारा तीन लाख लोगों की स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहां नियमित गांव-गांव घूमकर स्क्रीनिंग की जा रही है। केंद्र में लगी मशीन से इनकी जांच होती है।

मध्य प्रदेश के डिंडौरी में अक्टूबर माह में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों से परामर्श लेते मरीज • सौजन्य जनजाति कल्याण केंद्र (फाइल)

> जनजाति कल्याण केंद्र महाकोशल बरगांव में 15 प्रकल्प चल रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विशेष पहल की जा रही है। जिले में जरूरतमंद अधिकांश लोग ऐसे भी हैं, जो संसाधनों के अभाव में विशेषज्ञ डाक्टरों से इलाज नहीं करा पाते। ऐसे लोगों को चिह्नित कर प्रतिवर्ष होने वाले मेगा स्वास्थ्य शिविर में लाभान्वित कराया जाता है। हर महीने भी विशेषज्ञ डाक्टर शिविर लगाकर लोगों की जांच के साथ इलाज कर स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित कर रहे हैं।
>
> **राजकुमार मटाले**, अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

माला से नोट खींचकर भागा गाड़ी चालक, दूल्हे ने दबोचा

जागरण संवाददाता, मेरठ : इंटरनेट मीडिया पर एक दूल्हे का वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें दूल्हा पिकअप गाड़ी की खिड़की पर लटका हुआ दिखता है। कुछ देर बाद खिड़की से अंदर घुस जाता है। गाड़ी रुकवाकर चालक की पिटाई करने लगता है। वीडियो दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित मेरठ का बताया जा रहा है। दूल्हा घुड़चढ़ी के बाद मंदिर जा रहा था। उसने नोटों की माला पहनी हुई थी। इसी दौरान पीछे से एक युवक दौड़ता हुआ आया और माला से नोट खींच लिए। इसके बाद वह महिंद्रा पिकअप लेकर भागने की कोशिश करता है। दूल्हा भी पीछा करता है और पिकअफ पर लटक जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वह खिड़की से अंदर घुस जाता है और गाड़ी रुकवाकर आरोपित की पिटाई करने लगता है।

****

दैनिक जागरण
अधिकारों के साथ कर्तव्य भी संलग्न होते हैं

पहली प्राथमिकता हंगामा

संसद का कोई भी सत्र हो, उसकी शुरुआत हंगामे से होना एक परंपरा का रूप ले चुका है। यह एक खराब परंपरा है, लेकिन यह इसके बाद भी जारी है कि इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता- उस विपक्ष को भी नहीं, जो हंगामा करता है। विडंबना यह है कि वह हंगामे को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत करता है। संसद में इस या उस मुद्दे के बहाने हंगामा करना एक राजनीतिक स्वभाव बन गया है। जब जो दल विपक्ष में होता है, वह हंगामा करना पसंद करता है और वह भी तब, जब वह सत्ता में रहते समय हंगामे से त्रस्त हो चुका होता है। इस पर हैरानी नहीं कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष को हंगामा मचाने की इतनी जल्दी थी कि दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के तुरंत बाद ही हंगामा किया जाने लगा। क्या इसलिए कि उसकी पहली प्राथमिकता हंगामा करना ही था? संसद के आने वाले दिन भी हंगामे भरे हों तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह इन-इन मुद्दों को संसद में उठाएगा। विपक्ष यदा-कदा अपने हिसाब से ज्वलंत मुद्दों को उठाता है, लेकिन उन पर सार्थक बहस करने और सरकार से जवाब मांगने के बजाय उसकी दिलचस्पी इसमें अधिक होती है कि संसद चलने न पाए।

आम तौर पर विपक्ष संसद में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों का चयन खुद नहीं करता। वह उन मुद्दों को लेकर आगे आ जाता है, जो संसद सत्र के पहले से ही चर्चा में आ गए होते हैं। यह पहले से तय था कि मणिपुर और अदाणी प्रकरण के साथ संभल का मामला भी विपक्ष की कार्यसूची में आ जाएगा। ऐसे मामले उसकी कार्यसूची में होने ही चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं कि वह अपने स्तर पर जनता से जुड़े कुछ मुद्दों का चयन करे और इसके लिए प्रयत्न करे कि सरकार उन पर जवाब दे? शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण समेत न जाने कितने ऐसे विषय हैं, जिन पर संसद में व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। पता नहीं क्यों विपक्ष इन विषयों पर संसद में चर्चा के लिए गंभीर नहीं दिखता? विपक्ष हंगामा कर संसद को बाधित करते रह सकता है, लेकिन वह ऐसा करके जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। जनता हंगामा नहीं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार का जवाब चाहती है। संसद में हंगामा करते रहने की अपनी आदत पर विपक्ष को तो विचार करना ही चाहिए, सत्तापक्ष को भी यह देखना चाहिए कि संसद सही ढंग से कैसे चले? इसके लिए उसे विपक्ष को भरोसे में लेने के साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर विचार-विमर्श के लिए माहौल बनाने के लिए आगे आना चाहिए। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कटुता दूर होनी चाहिए। यह तभी संभव है, जब दोनों पक्ष एक-दूसरे को आदर देंगे।

जिम्मेदार कौन?

उत्तर प्रदेश के बरेली में गूगल मैप के सहारे कार से यात्रा कर रहे तीन युवकों की अधूरे पुल से गिरकर मौत न सिर्फ हृदयविदारक घटना है, बल्कि सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग की उदासीनता और लापरवाही को भी उजागर करती है। कोई पुल यदि जर्जर है या फिर बीच से टूटा हुआ है या फिर उस पर से गुजरना अत्यंत खतरनाक है तो उसके निर्माण या अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार विभागों की यह जिम्मेदारी है कि उस पर से यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित करें। इसके लिए अवरोध बनाया जाए और संकेतक भी लगाए जाएं ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि ऐसा नहीं किया गया है और कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो आखिर इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? दातागंज (बदायूं) से फरीदपुर (बरेली) को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल पर पचास मीटर के आगे सड़क नहीं बनी थी और जो अवरोधक बनाया गया था वह भी दरक चुका था, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने उसे दोबारा नहीं बनवाया। इस तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, यह घटना इसका उदाहरण है जिसमें तीन युवक अपनी जान से हाथ धो बैठे। लोक निर्माण विभाग के 748 पुल ऐसे हैं, जो पचास साल से अधिक पुराने हैं। सरकार के निर्देश पर कुछ माह पहले ही इनकी जांच की गई थी जिसमें 83 पुलों को यातायात के लिए असुरक्षित पाया गया था। सर्वाधिक असुरक्षित 10 पुल कानपुर क्षेत्र में हैं। इनमें कई पुलों को गिराकर फिर से निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार जरूर कर लिया गया है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, वहां निरीक्षण कर जरूरी प्रतिबंध लगाए जाएं। हर व्यक्ति की जान कीमती है इसलिए यह घटना उन युवाओं के लिए भी सबक है तो तकनीकी पर पूरी तरह आश्रित हैं।

उत्तर प्रदेश के जर्जर हो चुके पुलों को चिह्नित किया जा चुका है। वहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए

जन-जन के मन का दस्तावेज है संविधान

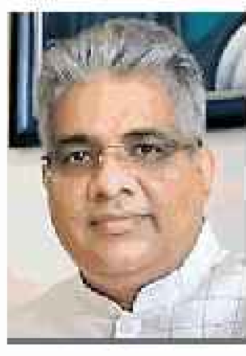

भूपेंद्र यादव

भारत का संविधान कोई न्यायिक या वैधानिक दस्तावेज मात्र नहीं है। वह भारत की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि है

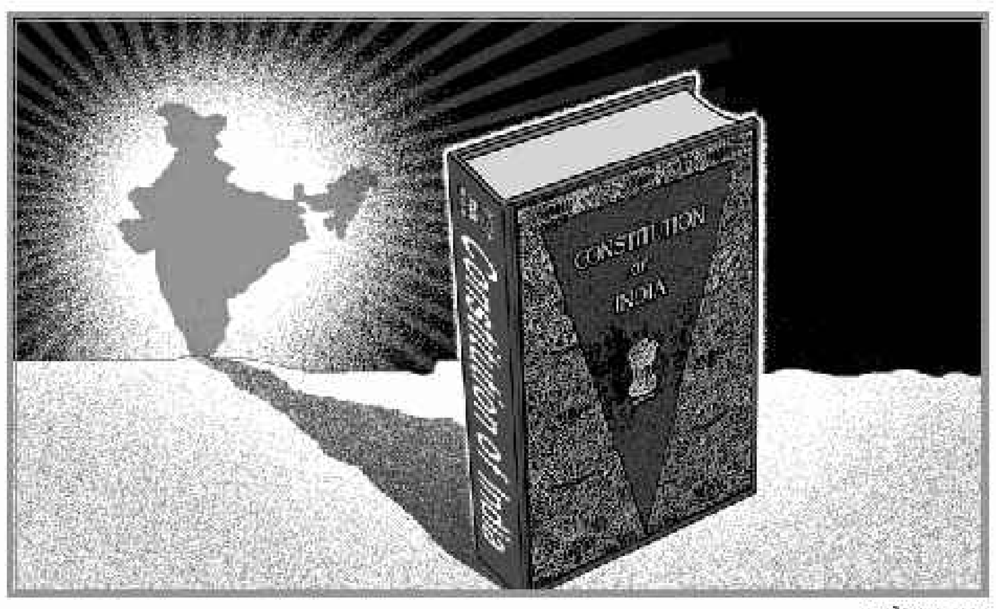

अवधेश राजपूत

भारतीय संविधान भारत के लोकतंत्र का मूल आधार है। आज भारत का आधुनिक लोकतंत्र 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इस 75 वर्षीय यात्रा के केंद्र में हमारा संविधान प्रतिष्ठित रहा है। ध्यातव्य है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना में भारतीय जीवन मूल्यों की मान्यताओं, आधुनिक शासन और भविष्य की आशाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति को केंद्र में रखा था। इन लक्ष्यों की सिद्धि करने वाले दस्तावेज के रूप में हमारा संविधान 26 नवंबर, 1949 को देश की जनता को समर्पित किया गया था। इस दृष्टि से 26 नवंबर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पश्चात दशकों तक केंद्रीय सत्ता में रही कांग्रेस के विचार में 26 नवंबर का ऐतिहासिक महत्व कभी नहीं आया। वास्तव में, कांग्रेस नेतृत्व सत्ता पर प्रभुत्व एवं नियंत्रण स्थापित रखने को ही लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य मानता था। वे स्वाधीनता दिवस (15 अगस्त) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) तो मनाते रहे, पर 'संविधान दिवस' जैसे महत्वपूर्ण अवसर, जब देश ने संविधान को अंगीकार किया था, को मात्र न्यायपालिका तक सीमित कर दिया। संविधान केवल न्यायिक या वैधानिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह भारत की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस अर्थ में यह देश के जन-जन के मन का दस्तावेज है।

'संविधान दिवस' की उपेक्षा तो एक विषय है। अन्यथा कांग्रेस का रवैया हर प्रकार से संविधान विरोधी ही रहा है। संविधान को कमजोर करने वाले अनेक प्रयास कांग्रेस समय-समय पर करती आई है। कांग्रेस द्वारा अपने शासनकाल में इस पर संशोधन लाने का प्रयास किया गया कि सरकार संविधान में क्या-क्या परिवर्तन कर सकती है? उल्लेखनीय होगा कि इसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती मामले की ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना था कि 'संशोधन करने की शक्ति में संविधान की मूल संरचना या रूपरेखा को बदलने की शक्ति शामिल नहीं है, जिससे कि इसका मूल ही बदल जाए।' तब जस्टिस सीकरी ने सुनवाई में कहा था कि, 'संविधान में संशोधन' शब्द संसद को मौलिक अधिकारों को निरस्त करने, छीनने या संविधान की मौलिक विशेषताओं को पूरी तरह से बदलने में सक्षम नहीं बनाता है, जिससे इसकी पहचान ही नष्ट हो जाए। बल्कि, इन सीमाओं के भीतर ही संसद हर अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है।' स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा संशोधन को लेकर मर्यादा निर्धारित की गई है। अन्यथा अतीत की कांग्रेस सरकारों की मंशा तो संविधान में मनमाने परिवर्तन की ही थी। आपातकाल के काले दौर में कांग्रेस द्वारा ऐसा किया भी गया, जब इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना ही बदल डाली। स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए हमारा संविधान केवल सत्ता को साधने का एक उपकरण मात्र रहा है, संविधान के प्रति सम्मान की भावना कांग्रेस के चरित्र में नहीं है।

वर्ष 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की मंशा से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सत्ता में आने के अगले ही वर्ष यानी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों से उपेक्षित 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत कर दी। यह दर्शाता है कि उनमें भारतीय संविधान के प्रति कितनी गहरी सम्मान भावना है।

केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करते हुए एक बेहतर तालमेल और संवाद से युक्त व्यवस्था का निर्माण कर संविधान में निहित संघीय ढांचे को मजबूती देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर के सम्मान में उनसे संबंधित स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा किया गया है। यह सभी कार्य भारतीय संविधान के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्मान और प्रतिबद्धता को ही प्रकट करते हैं।

गणतंत्र, पंथनिरपेक्षता, सशक्त निर्वाचन पद्धति, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, मूलभूत कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय संविधान के ऐसे कीर्तिमान हैं, जिसे पूरा करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। ये कोई शासन का आदेश नहीं, बल्कि भारत की संप्रभु जनता का किसी भी चुनी हुई सरकार को दिया गया जनादेश है। इसलिए, प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान इतना स्पष्ट है तो क्या संविधान की मूल भावना पर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहस खड़ी करना स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है? संविधान भारत में सभी नागरिकों के लिए दिग्दर्शक तत्व है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पवित्र ग्रंथ पर भी विपक्ष द्वारा अत्यंत निकृष्ट राजनीति की जा रही है। जो कांग्रेस शासन में रहते हुए कभी संविधान का सम्मान नहीं कर सकी, वह आज विपक्ष में बैठकर यह भ्रम फैलाने में लगी है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर देगी। ऐसा असत्य और भ्रम फैलाना क्या लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है?

सच तो यह है कि कांग्रेस जैसे दल आज अपने मूल राजनीतिक विचार को खो बैठे हैं और उनके पास यह कहने की क्षमता नहीं बची है कि 'संविधान के अंतर्गत आखिर वो कैसे भारत का शासन चलाएंगे?' कांग्रेस अपने गांधीवादी विचार और समाजवादी पार्टी जैसे दल समाजवाद और राम मनोहर लोहिया जी के मूलभूत विचारों को भूल चुके हैं। अब इनका लक्ष्य केवल किसी भी तरह सत्ता हथियाना ही रह गया है, लेकिन भारत की जनता बहुत विवेकवान है। वह विपक्ष के इन राजनीतिक प्रपंचों को बखूबी समझ भी रही है और समय-समय पर अपने मत की शक्ति से इनके प्रपंचों का समुचित उत्तर भी देती रहती है।

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं)

response@jagran.com

मेडिकल टूरिज्म का गढ़ बनता भारत

आरके सिन्हा

आधुनिक चिकित्सा के साथ ही आयुर्वेद एवं अन्य परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का और अधिक प्रचार किया जाना चाहिए

भरोसेमंद बनतीं देश की मेडिकल सुविधाएं। फाइल

हाल में यूजीसी नेट में आयुर्वेद बायोलाजी को एक विषय के तौर पर शामिल करने का फैसला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पीएम जन आरोग्य योजना में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी शामिल करने की मांग, इससे यही पता चलता है कि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की महत्ता बढ़ रही है। इसका प्रमाण तब भी मिला था, जब यह खबर आई थी कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स बेंगलुरु के पास एक आधुनिक आरोग्यशाला में पत्नी कैमिला समेत स्वास्थ्य लाभ के लिए आए। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से सस्ते और सफल इलाज के साथ ही विदेशियों में भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों जैसे-आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार विज्ञान जैसे उपचार लोकप्रिय हो रहे हैं। योग तो पहले से ही दुनिया भर में लोकप्रिय है। इस संदर्भ में यह भी स्मरण किया जाना चाहिए कि केरल के एर्नाकुलम स्थित श्रीधरीयम आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा के चलते केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा की पुत्री की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। यह किसी चमत्कार से कम न था। इसके बाद अफ्रीकी देशों से बड़ी तादाद में रोगी आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए भारत आने लगे।

मैं अक्सर देहरादून जाता रहता हूं। हर बार मुझे वहां अनेक विदेशी मिल जाते हैं। उनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि अधिकांश हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या आसपास की आरोग्यशालाओं में आए होते हैं। कुछ तो महीनों के लिए आते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोरोना काल में दुनिया का आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ा। इसके चलते विश्व के कई देशों में आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बढ़ी है। आज करीब सौ देशों में भारत के हर्बल उत्पाद पहुंच रहे हैं। आयुर्वेद की महत्ता को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया है। यह सही समय है कि आयुर्वेद के साथ अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शोध को बढ़ावा दिया जाए। अब यह सिद्ध होता जा रहा है कि खानपान के जरिये भी सेहत का ध्यान रखा जा सकता है। इनमें मोटे और छोटे अनाज की महती भूमिका है। मिलेट्समैन कहे जाने वाले पद्मश्री डा. खादरवली का दावा है कि मिलेट्स से अनेक रोगों का इलाज संभव है। उनका कहना है कि छह हफ्ते से लेकर छह महीने तक सिर्फ मिलेट्स के प्रयोग से कई बीमारियों के निदान में सफलता मिलती है।

भारत में बीते कुछ वर्षों से हृदय रोग, अस्थि रोग, किडनी एवं लिवर ट्रांसप्लांट और दिल की तमाम बीमारियों के सफल इलाज के लिए दक्षिण एशियाई देशों के अलावा अफ्रीका, मध्य एशिया और खाड़ी के देशों से लेकर पश्चिमी देशों से भी हर साल लाखों रोगी आ रहे हैं। कुछ वर्षों से दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़ आदि के आधुनिक अस्पतालों में इलाज कराने के लिए भारी संख्या में विदेशी आने लगे हैं। दुनिया भर में बसे भारतवंशी भी स्वदेश में अपना इलाज कराना पसंद कर रहे हैं। इससे भारत मेडिकल टूरिज्म का गढ़ बन रहा है। देश के नामी प्लास्टिक सर्जन बताते हैं कि उनके पास हर महीने विदेशी बर्न इंजरी के इलाज से लेकर हेयर ट्रांसप्लांट और अपनी ढीली पड़ती त्वचा को ठीक कराने के लिए आते हैं। हमें ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक विदेशी रोगी इलाज के लिए भारत आएं। उनके भारत आने से देश को अमूल्य विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। जब भी एक रोगी भारत आता है तो उसके साथ दो-तीन तीमारदार भी आते हैं। वे महीनों यहां रहते हैं। भारत में विदेश से रोगी इसलिए भी आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मरीजों को सर्वश्रेष्ठ प्री और पोस्ट-सर्जरी सुविधाएं यूरोप या अमेरिका की तुलना में बहुत कम कीमत पर मिल जाती हैं।

भारत के पास योग्य चिकित्सा पेशेवर और अत्याधुनिक उपकरण हैं। इसके अलावा भारत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में कम खर्चीला उपचार विकल्प प्रदान करता है। भारत में इलाज का खर्च अमेरिका के मुकाबले करीब एक चौथाई है। यदि हम इस मोर्चे पर संभल कर चले तो फिर विदेशी इलाज के लिए थाइलैंड, सिंगापुर और जापान जैसे देशों के बजाय भारत का ही रुख करने लगेंगे।

मेडिकल टूरिज्म अरबों डालर का सालाना कारोबार है। इस पर भारत को अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। इस क्षेत्र में भारत के सामने तमाम संभावनाएं हैं, क्योंकि सारी दुनिया के लोग बेहतर इलाज के लिए अपने देशों की सरहद लांघने लगे हैं। गोवा में आयोजित जी-20 से जुड़े एक कार्यक्रम में बताया गया था कि 2022 में 14 लाख विदेशी इलाज के लिए भारत आए। यह आंकड़ा ही साबित करता है कि भारत की मेडिकल सुविधाओं को लेकर दुनिया में भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन हमें 2030 तक अपने यहां हर साल एक करोड़ तक विदेशी रोगियों को इलाज के लिए बुलाने के उपाय करने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अस्पतालों और क्लीनिकों का निर्माण करके गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार को मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, जिसमें उचित नियम-विनियमन और प्रोत्साहन शामिल हो। भारत को अपने मेडिकल टूरिज्म का प्रचार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग अभियान भी चलाना चाहिए। टेलीमेडिसिन, ई-परामर्श और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाकर भी भारत मेडिकल टूरिज्म को गति दे सकता है। भारत को आधुनिक चिकित्सा के साथ ही आयुर्वेद एवं अपनी अन्य परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार-प्रसार पर और ध्यान देना होगा। इसका एक बड़ा लाभ यह होगा कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेंगे।

(लेखक पूर्व सांसद और पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सुख और आनंद

प्रायः लोग सुख को ही आनंद समझने की भ्रांतिपूर्ण मान्यता रखकर बहुत भारी भूल कर बैठते हैं। सुख और आनंद दो अलग-अलग चीजें हैं। दोनों का शब्दार्थ अलग-अलग है। सुख भौतिक होता है और आनंद आध्यात्मिक होता है। सुख संसार में मिलता है। आनंद प्रभु के चरणों में मिलता है। सांसारिक वस्तुओं से सुख मिल सकता है, किंतु आनंद नहीं। जो भौतिक वस्तुएं हैं, वे व्यक्ति को सुख दे सकती हैं, किंतु आनंद नहीं। सुख तो क्षणिक होता है, पर आनंद क्षणिक नहीं, बल्कि स्थायी है। आनंद जब जीवन में आता है तो जीवन परमानंद हो जाता है। सुख बाहर ढूंढ़ने का विषय है। आनंद भीतर का विषय है, क्योंकि जब अपने आप में खो जाएंगे, तब आनंद की अनुभूति होगी। सुख का तो दुख हो सकता है, किंतु आनंद का विलोम है ही नहीं। आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता। आनंद का कुछ होगा तो परमानंद ही होगा। व्यक्ति एसी रूम में रहते हैं। डनलप के गद्दों पर सोते हैं। बढ़िया-बढ़िया काजू-बादाम खाते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे सभी व्यक्ति आनंद में भी होंगे। डनलप के गद्दों पर सोना और बढ़िया एसी कमरे में रहने का सुख क्षणिक है। आज है कल नहीं।

आनंद तब होगा जब ईश्वर से प्रीति हो जाएगी। जब ईश्वर के नाम की मस्ती में डूब जाएंगे। असली आनंद तो एक संत को, एक फकीर को है। जो दो जोड़ी वस्त्र पहनकर कहता है वाह-वाह रे मौज फकीरा की। पैसों से सुख तो खरीदा जा सकता है, लेकिन आनंद नहीं। एक व्यक्ति है, जिसके पास भौतिक सुख नहीं है। केवल दो जोड़ी वस्त्र हैं। उसे दो वक्त की रोटी भगवान दे देते हैं। फिर भी वह बिना किसी लोभ, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिंता के जीवन व्यतीत करता है। यह है असली आनंद। जो भगवान के चरणों में जुड़ गए, उनके जीवन में आनंद है। जो संसार में फंसे हैं, उनके जीवन में सुख है, लेकिन आनंद नहीं।

मुकेश ऋषि

पर्यावरण संरक्षण की पहल

डा. मोनिका शर्मा

हाल में चुनाव आयोग ने मुंबई के दो विधानसभा क्षेत्रों में ग्रीन इलेक्शन की संकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया

दमघोंटू हवा और चरम मौसमी हालात से जूझने के दौर में चुनाव प्रक्रिया में पर्यावरण को पहुंचने वाली हानि को रोकना भी आवश्यक है। हाल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की पर्यावरण सहेजने से जुड़ी एक पहल चर्चा का विषय बनी, जिसमें मुंबई के दो विधानसभा क्षेत्रों में ग्रीन इलेक्शन की संकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया। आमजन और प्रत्याशियों से पर्यावरण सहेजनेवाली इस मुहिम से जुड़ने को कहा गया था। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए दो तरह की कोशिशें की गईं। एक ओर प्रत्याशियों से पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली प्रचार सामग्री से दूरी बनाने को कहा गया तो दूसरी ओर मतदाताओं से एक वोट के साथ एक पौधा लगाने की अपील की गई। चुनाव प्रचार की सामग्री का प्लास्टिक फ्री और इको फ्रेंडली होना प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए अहम कदम है। वहीं मतदाताओं को अपने फ्लैट या घर में एक पौधा लगाने की अपील हरियाली को पोसने का प्रयास।

वस्तुतः भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को काफी समय से बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले भी चुनावों में राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इनमें ई-बुक्स एवं ई-डाक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने और डबल-साइड प्रिंटिंग को बढ़ावा देने जैसे निर्देश शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद ग्रीन इलेक्शन की अवधारणा को पंजाब में हुए चुनावों में भी आजमाया जा चुका है। शुरुआती तौर पर रोपड़ में इस साझी मुहिम से 50 हजार से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी हालिया उपचुनावों में ग्रीन इलेक्शन की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। वहां इको फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन बनाए गए। पोलिंग स्टेशनों पर कागज और बांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही पौधे लगाने और इको फ्रेंडली सेल्फी प्वाइंट बनाने जैसी कोशिशें भी की गईं।

आज दूषित होते हवा-पानी और खत्म होती हरियाली से पर्यावरण असंतुलन की गंभीर स्थितियां हमारे सामने हैं। दुखद है कि राजधानी दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची का हिस्सा हैं। नतीजतन बीमारियों का बढ़ता घेरा जीवन को मुश्किल में डाल रहा है। देश का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। पर्यावरण सहेजने हेतु देश का आंगन हो या घर-परिवार का परिवेश, हर स्तर पर प्रयास जरूरी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विचार का शामिल होना भी एक सार्थक मुहिम है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

ग्रामीण सशक्तीकरण का नया युग

'सहकार से समृद्धि का भारतीय दर्शन' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अमित शाह ने सहकारिता को भारतीय समृद्धि का आधार बताते हुए इसे ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तीकरण और सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रभावी साधन बनाने की दिशा में सरकार के नए प्रयासों का अवलोकन और मूल्यांकन किया है। सहकारिता भारतीय समाज के मूल में रची-बसी अवधारणा है, जो सामूहिक प्रयासों से समृद्धि की नींव रखती है। वर्तमान सरकार द्वारा सहकारी समितियों को संगठित और प्रभावी ढांचे में लाने का प्रयास न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। सहकारी संस्थाएं स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके समाज के हाशिये पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने का साधन बन सकती हैं। गुजरात का 'अमूल माडल' इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन और विपणन में क्रांति लाने में सफल रहा। अमूल ने न केवल किसानों को सशक्त बनाया, बल्कि भारत को दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी बनाया। यह इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा में किया गया सहकारी प्रयास आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। हालांकि सहकारिता के क्षेत्र में असफलताएं भी मिली हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में कई सहकारी समितियां भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर प्रबंधन का शिकार हुईं। इन समितियों में पारदर्शिता की कमी और धन का दुरुपयोग उनके पतन का मुख्य कारण बना। इन विफलताओं ने स्पष्ट किया कि सहकारी संस्थाएं तभी सफल हो सकती हैं, जब वे भ्रष्टाचार से मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह हों। वर्तमान सरकार का सहकारी समितियों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने का निर्णय इस दिशा में सही कदम है। यह न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, बल्कि धन और संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी करेगा। साथ ही सहकारी समितियों के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को शामिल करने से उनकी विश्वसनीयता और स्थिरता बढ़ेगी।

amarjeet360conscience@gmail.com

विकास में सहकार का योगदान

'सहकार से समृद्धि का भारतीय दर्शन' शीर्षक से लिखे आलेख में अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र के विस्तार में मौजूदा सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया है। वास्तव में सहकार का मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में अहम योगदान है। बिना सहकार के परिवार और कृषि व्यवस्था का विकास असंभव था। हां, यह अलग बात है कि सहकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विभिन्न नाम से जाना गया। श्रेणी और गिल्ड जैसे संगठन सहकार पर ही आधारित होते थे और भी अन्य अनेक उदाहरण हैं। आधुनिक भारत में सहकारिता का बेहतरीन उदाहरण आणंद है। बकायदा सहकारिता के महत्व को दर्शाने वाली फिल्म (श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म 'मंथन' 1976) भी बनी थी जिससे पता चलता है कि सहकार से समृद्धि के द्वार तो खुलेंगे ही, ग्रामीण समाज में जात-पात के नाम पर जो भेदभाव नजर आते हैं, उसे भी पाटने में मदद मिल सकती है। इन दिनों बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है। इसके चलते गांव में गहमा-गहमी का माहौल है। यहां पैक्स ने अच्छा काम किया है। मगर इधर कुछ सालों में गंवई राजनीति पैक्स पर हावी होती जा रही है। जिसका मूल कारण भ्रष्टाचार है। लिहाजा सहकारी समितियां को भ्रष्टाचार से दूर रखना आवश्यक है। गांव की वर्चस्ववादी मानसिकता से सहकारी समितियां दूर रहेंगी तब ये अपने मूल उद्देश्य को पाने में सफल होंगे। गांव से गरीबी दूर होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, पलायन और अशिक्षा जैसी समस्याएं मिटेंगी। फिर यही प्रयास देश को समृद्ध करने में मददगार साबित होंगे। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने सहकारिता आंदोलन के महत्व को समझा। सहकारिता को स्वायत्त मंत्रालय बनाने का निर्णय किया।

mukeshkr.m7542@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

6 प्रमुख यूरोपीय देशों- इटली, फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक गणराज्य में राष्ट्रवादी सरकारें हैं, जबकि कई अन्य देशों में राष्ट्रवादी पार्टियां शक्तिशाली हो रही हैं। वहीं, स्वीडन और नीदरलैंड में राष्ट्रवादी दल महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।

ट्रंप की जीत का प्रभाव

अमेरिका की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां

आतंकवाद, वैश्वीकरण, युद्ध एवं आर्थिक उथल-पुथल के कारण आज लगभग पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद उभार पर है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम भी उसी तर्ज पर माने जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने चुनाव से पहले और उसके बाद भी बार बार यह कहा था कि वह चीनी वस्तुओं के अंधाधुंध आयात को रोकने का प्रयास करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से समूचे विश्व में अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में बदलाव की चर्चा है, जिसका असर भारत पर भी हो सकता है

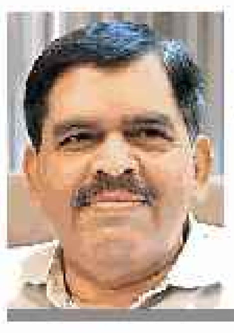

डा. अश्विनी महाजन
पूर्व प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इसके बाद से दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में किस तरह के बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछली बार भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने नीतियों में बड़े फेरबदल किए थे। वस्तुतः डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की अप्रवासी नीतियों में भी आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, ताकि अमेरिकावासियों के रोजगार की रक्षा हो सके। उनका इस बात पर जोर रहा था कि अमेरिका को दूरदराज के देशों में सशस्त्र दखल रोकना है, ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। अमेरिका फर्स्ट ट्रंप का मंत्र रहा है। ट्रंप के राष्ट्रवाद का जादू सर चढ़कर बोल रहा है।

यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उभार : उधर यूरोप में भी राष्ट्रवाद पुनः उभार ले रहा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोपीय देशों में पहले उदारवाद और बाद में भूमंडलीकरण और यहां तक कि खुली अप्रवासी नीति भी अपनाई जाने लगी थी। लेकिन आज यूरोपीय देश राष्ट्रवाद पर सवार हो कर अपनी अर्थव्यवस्था और समाज की चिंता कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट के माध्यम से स्वयं को यूरोपीय समुदाय से अलग किया। हालांकि ब्रिटेन के अलावा यूरोपीय समुदाय के सभी देश भी समुदाय में बने हुए हैं, लेकिन सभी देशों में जहां पूर्व में उदारवादी सरकारों का बोलबाला था, अब राष्ट्रवाद का ज्वार बढ़ता दिख रहा है। छह प्रमुख यूरोपीय देशों इटली, फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक गणराज्य में तो राष्ट्रवादी सरकारें पहले से ही स्थापित हो चुकी हैं, कई अन्य देशों में राष्ट्रवादी पार्टियां काफी ताकतवर हो रही हैं। स्वीडन में सरकार का अस्तित्व राष्ट्रवादी दल नेशनलिस्ट स्वीडेन डेमोक्रेट के समर्थन पर टिका है। नीदरलैंड में इस्लाम विरोधी ग्रीट वाइल्डर का दल सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका में है।

जर्मनी और फ्रांस में भी राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों का प्रभाव अभूतपूर्ण रूप से बढ़ रहा है और वह सत्ता के काफी नजदीक पहुंच रहे हैं। पंथनिरपेक्षता के नाम पर जैसे जैसे अल्पसंख्यक समुदायों का तुष्टीकरण बढ़ा और तुष्टीकरण के साथ ही साथ अतिवाद भी बढ़ा। साथ ही, हाल ही में फ्रांस और इंग्लैंड में इस अतिवाद के भयानक दृश्य भी सामने आए। इन सब घटनाओं से भी यूरोप और अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में जनमानस का मूड बदला है।

हिंदुओं की प्रशंसा : चाहे यूरोप हो या अमेरिका, राष्ट्रवाद की जीत के कई निहितार्थ हैं। सबसे पहले समझना होगा कि यह अतिवादी ताकतों की एक बड़ी हार है। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में हिंदुओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है और अमेरिका में उनकी भूमिका को सराहा है। यहां तक कि स्वयं को हिंदुओं का बड़ा प्रशंसक तक बताया है। इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। उधर हालांकि ट्रंप मुस्लिमों के विरुद्ध तो नहीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो मुस्लिम अप्रवासी हमास का समर्थन करेंगे, वे उन्हें अमेरिका से बाहर कर देंगे। यानी ट्रंप किसी भी प्रकार के अतिवाद के विरोधी हैं। गौरतलब है कि बाइडन प्रशासन ने अतिवादी ताकतों का समर्थन करने वाली कनाडा सरकार का समर्थन किया था, आने वाला ट्रंप प्रशासन ऐसा नहीं करेगा।

जहां अतिवादी, वामपंथी, वोक, समलैंगिक मानवाधिकार समर्थक एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं, ट्रंप ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी राष्ट्रवाद (अमेरिका प्रथम) का जो नारा दिया और जीत हासिल की वह इस बात का प्रमाण है कि ट्रंप की जीत, एक प्रकार से अतिवादी, वामपंथी आदि ताकतों की भी हार है। हम समझते हैं कि यह चुनाव आर्थिक मुद्दों के अलावा अतिवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सेंसरशिप के मुद्दों पर लड़ा गया था, जहां ट्रंप घरेलू व्यवसायों की रक्षा और बढ़ावा देकर, अप्रवास को प्रतिबंधित करके और अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को निर्वासित करके, अमेरिकावासियों के लिए नौकरियों की रक्षा के लिए अमेरिका में काम करके अमेरिका को फिर से महान बनाने की अपने संकल्प को दोहरा रहे थे।

लेकिन ट्रंप की जीत का भारत के लिए क्या मतलब है, यह एक बड़ा सवाल है। अमेरिका-चीन तनाव को देखते हुए, जिसके बढ़ने की आशंका है, ट्रंप के सत्ता में आने पर विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देखते हैं। इससे भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से अपने घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

हालांकि ट्रंप के संरक्षणवादी रुख और टैरिफ बढ़ाने के कारण भारत को अमेरिका को निर्यात में नुकसान होने की भी चिंता हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर व्यक्तियों और व्यवसायों पर करों में संभावित कमी से अमेरिका के विकास में सुधार हो सकता है, जिससे भारत के निर्यात को लाभ होगा। अमेरिका एच1बी वीजा को सख्त कर सकता है, जिससे भारतीय प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे में उनके संचालन की लागत बढ़ सकती है। कुछ आलोचक जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रुख से भी चिंतित हैं, जिससे 'नेट जीरो' लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है। लेकिन हमें भू-राजनीति के बड़े सवाल और दो मजबूत मित्रों (कूटनीतिक रूप से) अमेरिका और रूस के साथ दुनिया में भारत की स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि नए भू-राजनीतिक परिदृश्य से दुनिया में लंबे समय तक शांति स्थापित होगी जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं सुविधाजनक हो सकती हैं। इसके साथ ही ट्रंप के सत्ता में आने से उग्रवाद और आतंकवाद भी हतोत्साहित होगा।

हालिया संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा सर्वाधिक हावी दिखा है। फाइल

अमेरिकी राजनीति में महिलाओं का संघर्ष

गजेंद्र सिंह
सामाजिक चिंतक

अमेरिका में अब तक एक विचित्र विरोधाभास बना हुआ है। एक ऐसा देश जो समानता का समर्थक है, लेकिन जिसने कभी महिला राष्ट्रपति को नहीं देखा। जिस देश में महिलाएं कारपोरेट जगत में शीर्ष पदों पर पहुंच रही हैं, खेल में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, प्रमुख मीडिया संस्थानों का नेतृत्व कर रही हैं, यहां तक कि उपराष्ट्रपति भी बन रही हैं, वहीं राष्ट्रपति का पद अभी भी उनकी पहुंच से दूर है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, अमेरिका के 248 वर्षों के इतिहास में केवल दो महिलाएं प्रमुख दलों से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनीं। वर्ष 2016 में हिलेरी क्लिंटन और इस बार कमला हैरिस। दुर्भाग्यवश, दोनों का सामना डोनाल्ड ट्रंप से हुआ, जो अदृश्य अवरोध तोड़ने के बजाय परंपरागत राजनीतिक नियमों को तोड़ने में अधिक रुचि रखते थे।

वैसे विश्व का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। भारत में इंदिरा गांधी दशकों पहले प्रधानमंत्री बनीं और लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो ने दो बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली। बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना ने बारी-बारी से सत्ता संभाली। श्रीलंका में सिरिमावो भंडारनायके ने विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। हां, इनमें से कई को परिवार का नाम और राजनीतिक विरासत मिली, परंतु कम से कम उन्होंने शीर्ष पद संभाला और सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।

वहीं महिला उम्मीदवारों को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें न केवल अपनी नीतियों और योजनाओं को लेकर, बल्कि अपनी व्यक्तिगत छवि, पहनावे, बोलने के लहजे और यहां तक कि पारिवारिक जीवन को लेकर भी निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ता है। मीडिया कवरेज में अक्सर उनके व्यक्तित्व पर नीतिगत मुद्दों से अधिक ध्यान दिया जाता है। परंतु अमेरिका में स्थिति जटिल है। यहां की राजनीति में महिला उम्मीदवारों से विरोधाभासी अपेक्षाएं की जाती हैं। वे सक्षम हों, पर बहुत अधिक नहीं, ताकि पुरुष मतदाताओं को असहज न करें। मुखर हों, पर आक्रामक नहीं, ताकि 'अतिआत्मविश्वासी' न लगें। अनुभवी हों, पर बहुत अधिक नहीं, ताकि 'स्थापित व्यवस्था' का हिस्सा न मानी जाएं। यह एक जटिल संतुलन है, जिसे बनाए रखना लगभग असंभव है। युवा पीढ़ी में बदलाव की आशा दिखाई देती है। नए मतदाताओं में लैंगिक समानता को लेकर अधिक जागरूकता है। वे नेतृत्व क्षमता को लिंग के बजाय योग्यता से आंकते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि जेन-जेड में महिला राष्ट्रपति की स्वीकार्यता अधिक है।

वैसे मनोरंजन जगत में अमेरिका महिला राष्ट्रपतियों की कल्पना करने में माहिर है। वहां के अनेक टीवी शो इसके उदाहरण हैं। इन कार्यक्रमों में दिखाया जाता है कि कैसे एक महिला राष्ट्रपति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करती है। लेकिन वास्तविक जीवन में मतदाता अभी भी इस विचार से संकोच करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दलों को चाहिए कि वे महिला नेताओं को अधिक अवसर दें, उनके लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएं और फंडिंग में समानता सुनिश्चित करें। इस लिहाज से कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि अमेरिका धीरे-धीरे बदल रहा है। कहा जा सकता है कि अमेरिका जो स्वयं को समानता और लोकतंत्र का प्रतीक मानता है, वह महिला राष्ट्रपति के मामले में विश्व से पीछे है। परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी है, लेकिन आशा की किरणें दिखाई देती हैं। नई पीढ़ी के सोच, बढ़ती जागरूकता और संस्थागत प्रयासों से यह अदृश्य अवरोध एक दिन अवश्य टूटेगा। तब तक यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम प्रगति की दिशा में निरंतर कदम बढ़ाते रहें।

खरी-खरी

मौके लपकने के उस्ताद

रेखा शाह आरबी

आजकल पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम और सभ्य होते जा रहे हैं या असभ्य होते जा रहे हैं। हम विकास में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं। आज की दुनिया में यदि लोगों को इंसान कहा जाता है तो आदिम युग के लोगों को तो भगवान कहा जाना चाहिए। कम से कम उनके पास इतनी तमीज थी कि कहां पर रोना है, कहां पर हंसना है, कहां पर कैसा व्यवहार करना है। पहले के लोग अगर किसी का दुख देख लेते थे तो स्वयं भी दुखी होकर उस पर संवेदना व्यक्त करते थे। आजकल वीडियो बनाते हैं।

संवेदना और ढांढस पाकर इंसान अपने दुख से बाहर तो नहीं आ पाता था, लेकिन कम से कम उस समय उसे अपना दुख रोने के लिए कंधा मिल जाता था। अब तो लगता है सुख-दुख पर सहारा देना और दिल से संवेदना व्यक्त करना इंसानी आदत नहीं, केवल जानवरों की आदत रह गई है। हम इंसान तो किसी के दुख में केवल फोटो खींचना जानते हैं।

वैसे आज के समय में कोई दुख से दब जाए तो हम यह सोचते हैं कि इतना कम दुख क्यों है। कुछ और यूनिक किस्म का दुख इसके ऊपर आना चाहिए, ताकि उसके दुख पर बना वीडियो वायरल हो जाए। मतलब हर जगह अपने स्वार्थ की जीभ लपलपाते रहते हैं। इंसान इतना विकसित हो चुका है कि किसी अन्य जीव से उसकी तुलना करने पर डर लगता है कि उस जीव का आत्मा बुरा मान जाएगा।

आजकल तो हालात यह है कि यदि हमारा कोई सैनिक सीमा पर बलिदान भी होता है, तो लोग उसके परिवार से सहानुभूति जताने के बजाय रील बनाने में जुट जाते हैं। परिवार के लिए यह एक घोर दुख का कारण होता है। नेताओं के मामले में तो यह और भी दुखद है। वे तो मौके को लपक ही लेते हैं, पहुंच जाते हैं चेक लेकर फोटो खिंचवाने के लिए। मौका पहचानने की इनकी कला को दाद देनी चाहिए। यूं ही थोड़े न मंत्री बन जाते हैं। अपना जमीर साइड में रख बहुत सारे ऐसे मौके को वे पहचान लेते हैं और उसे अपने पक्ष में भुनाने पहुंच जाते हैं।

पोस्ट

महाराष्ट्र में महायुति को लाडकी बहिन योजना का फायदा हुआ, वहीं मंइयां सम्मान योजना का फायदा हेमंत सोरेन को मिला। महाराष्ट्र में योगी जी का नारा काम आया, तो झारखंड ने ध्रुवीकरण के नारों को नकार दिया।
आदेश रावल@AadeshRawal

दिल्ली की लड़ाई के लिए कांग्रेस को खुद को तैयार करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कमजोर रणनीति और आप के साथ गठबंधन को लेकर दुविधा वाली पुरानी कमजोरियों से ही जूझती रहेगी। यह उस पार्टी की स्थिति है, जिसने दिल्ली को उसकी सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री दी।
पल्लवी घोष@_pallavighosh

रनों के अंतर को किनारे रख भी दिया जाए तो याद नहीं आता कि अपनी धरती पर आस्ट्रेलियाई टीम को टेस्ट मैच में कब इतनी निर्ममता से कुचला गया जैसा पर्थ में भारतीय टीम ने किया।
निखिल नाज@NikhilNaz

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अश्विन, जडेजा और शमी की अनुपस्थिति के बावजूद भारत ने आस्ट्रेलिया की दमदार टीम को पर्थ में हरा दिया। यह भारत की सबसे महान विजय में से एक या उससे भी बढ़कर भारतीय क्रिकेट की बड़ी जीत है।
संजय मांजरेकर@sanjaymanjrekar

जागरण जनमत कल का परिणाम

भारतीय टीम के आस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने की संभावनाएं बढ़ गई हैं?

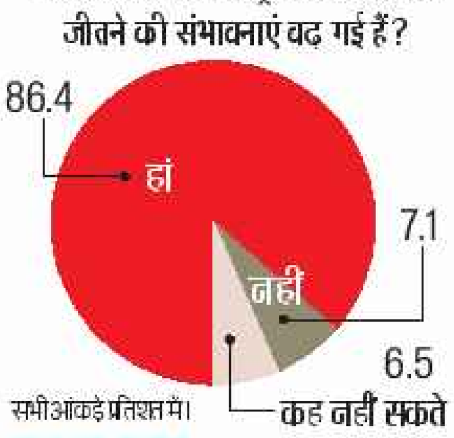

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या महाराष्ट्र में भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

हारें जब वे वोट से भड़काएं तब आग,
चालू होता हर जगह संभल जैसा राग।
संभल जैसा राग लोग जाते हैं मारे,
नेता करता मौज चहे जीते या हारे।
खुराफात कर लोग रूप पीड़ित का धारें,
खुद भी मारे जायं पुलिस को जब वे मारें।
- ओमप्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

मुस्लिम-लाभार्थी जोड़ से मजबूत हुईं ममता

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या कांड को लेकर ढाई माह से अधिक समय तक जनांदोलन हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से जिला मुख्यालयों से लेकर तमाम छोटे कस्बों तक से स्वतःस्फूर्त प्रस्फुटित हुआ था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 13 वर्षों के शासनकाल में उनके विरुद्ध पहली बार ऐसा जनाक्रोश दिखा था, लेकिन इसका बंगाल की छह विधानसभा सीटों के उपचुनावों पर प्रभाव नहीं दिखा। सभी छह सीटें भारी मतों के अंतर से तृणमूल कांग्रेस जीत गई। दो सीटें तो ऐसी रहीं, जहां किसी भी प्रतिद्वंद्वी दल की जमानत तक नहीं बची। शिक्षक भर्ती, नगरपालिकाओं में नियुक्ति और राशन घोटाले के बावजूद यह जीत काफी कुछ कह रही है।

उत्तर 24 परगना जिले की हारोआ में तो तृणमूल प्रत्याशी ने 1.31 लाख से अधिक और कूचबिहार की सिताई सीट पर 1.3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। इस चुनाव परिणाम के बाद प्रश्न उठ रहा है कि 75 दिनों से अधिक समय तक जो जनाक्रोश सड़कों पर दिखा था, उसका असर उपचुनावों में ईवीएम में क्यों नहीं दिखा? इसका सरल और सीधा जवाब है कि मुस्लिम और नकदी पाने वाले लाभार्थियों के जोड़ ने ममता को अजेय बना दिया है। यही वजह है कि वह हर चुनाव और उपचुनाव आसानी से जीत जा रही हैं। जिन दो सीटों पर तृणमूल ने 1.3 लाख से अधिक वोट के अंतर जीत दर्ज की, उनमें से हारोआ में 80 प्रतिशत से अधिक और सिताई में 40 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, जिन्होंने ममता के पक्ष में एकतरफा मतदान किया है। वहीं लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक हजार रुपये और एससी, एसटी महिलाओं को 1,200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। कन्याश्री में लड़कियों को 750 रुपये प्रति वर्ष और 18-19 वर्ष के बीच एकमुश्त 25 हजार रुपये दिए जाते हैं। रूपश्री योजना में बेटी की शादी के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को एकमुश्त 25 हजार रुपये दिए जाते हैं। वहीं कक्षा 11 व 12 के छात्र-छात्राओं को दस-दस हजार रुपये टैबलेट व मोबाइल खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ ही, हजारों क्लबों को दो-दो लाख, दुर्गापूजा का आयोजन करने वाले 43 हजार से अधिक क्लबों व समितियों को 85-85 हजार रुपये नकद और बिजली बिल में 75 प्रतिशत की छूट के अलावा सरकार की होर्डिंग लगाने के लिए भी रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों को भत्ता भी दिए जाते हैं। ऐसी नकदी देने वाली योजनाएं और मुसलमानों का एकतरफा वोट ममता की जीत का अहम हथियार बन चुका है।

उपचुनाव में जीत के बाद अबीर-गुलाल उड़ाती तृणमूल की महिला कार्यकर्ता और समर्थक। फाइल

इस लाभार्थी वर्ग और मुस्लिम वोटरों का गठजोड़ ऐसा है कि जिन छह निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं, उनमें से नैहाटी और मेदिनीपुर दो शहरी सीटें थीं। नैहाटी कोलकाता से अधिक दूर नहीं है। इतना ही नहीं, नैहाटी आरजी कर कांड में मृत महिला डाक्टर के घर से 15 किलोमीटर के दायरे में है। विपक्ष यहां भी टिक नहीं सका। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीट वार विश्लेषण में नैहाटी में जो अंतर था, उससे अधिक वोटों के अंतर से तृणमूल ने उपचुनाव जीता है। 2021 में मेदिनीपुर सीट पर तृणमूल प्रत्याशी ने 24 हजार से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन वहां लोकसभा चुनाव में तृणमूल की बढ़त महज दो हजार से कुछ ज्यादा रही थी, परंतु उपचुनाव में यह अंतर बढ़कर 33 हजार हो गया।

आरजी कर कांड को लेकर वामदलों के नेता अधिक सक्रिय थे, लेकिन देखा गया कि उपचुनाव में वामपंथियों की सभी सीटों पर जमानत भी नहीं बची। इस आंदोलन का विपक्षियों को उपचुनाव में कोई लाभ नहीं मिला। इसे लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल का दावा है कि भाजपा और माकपा द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ किए गए झूठे प्रचार को बंगाल के मतदाताओं ने नकार दिया है। भाजपा सहित विपक्षी दलों ने भी माना है कि ये नतीजे विभिन्न मुद्दों पर तृणमूल के खिलाफ 'बढ़ते जन असंतोष' को नहीं दर्शा रहे हैं। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'आगामी चुनावों में लोगों के असंतोष को वोटों में बदलने के लिए भाजपा को अपने संगठनात्मक आधार को और मजबूत करने की जरूरत है।'

माकपा नेता सृजन भट्टाचार्य के अनुसार, उपचुनाव में लोग विभिन्न समीकरणों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। इस चुनाव में वोट देने से सरकार नहीं बदलती है, इसलिए अभी आरजी कर आंदोलन के प्रभाव को मापना सही नहीं होगा। यह भी सच है कि बंगाल में आम तौर पर उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल की जीत होती रही है।

संविधान

नागरिक अधिकारों का संरक्षक

आज हमारे देश में हर जगह 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की बात जोर-शोर से हो रही है। इसके पीछे संविधान की अपनी शक्ति का विशेष योगदान है

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
चेयर प्रोफेसर, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। हमारे देश का संविधान 75 वर्ष का हो चुका है। आजादी के बाद संविधान स्वीकृति एक अभूतपूर्व घटना थी। आज जब भारत के लोग 21वीं सदी में संविधान की ताकत के साथ जी रहे हैं तो वे इस बारे में जागरूक हैं कि यह संविधान हमारे जीवन का रखवाला है, हमारे अधिकारों का संरक्षक है और हमारी गरिमा इससे सुरक्षित रहेगी।

संविधान की इस विश्वसनीयता में भारतीय प्राच्य परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय केवल संविधान से नहीं जीते हैं। वे जीते हैं अपने आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक मूल्यों को भी जो हमारे संविधान में वर्णित मूल्यों को सुरक्षित करने और उसे संवर्धित करने में सहयोगी साबित हुए हैं। यह भारत का सौभाग्य है कि हम अपने उन मूल्यों को जोड़कर अपने जीवन-धर्म तय करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक परंपरा में यही मूल्य ही श्रेयष्कर साबित हुए हैं जिससे हम विश्व के समक्ष गर्व के साथ खड़े होते हैं।

भारत की महान परंपरा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कह चुके हैं कि हमारा संविधान केवल अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, यह सहस्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। हमारे लिए संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान के प्रति हमारा आदर पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। यह हमलोगों का दायित्व है। इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह संविधान के प्रकाश में है। हर वर्ष संविधान दिवस मनाकर हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए।

संविधान को उत्सव के रूप में मनाने के साथ ही अब इसके प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। सहज जीवन जीने वाले लोग अभी भी इस पुस्तक के बारे में नहीं जानते। वे पुलिस, कोर्ट, वकील, जज आदि को ही अपने जीवन का रक्षक मानते हैं। वास्तव में ये लोग भारत के संविधान नहीं हैं, ये इस संविधान के दायरे में भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निर्वाहकर्ता हैं। संविधान में निहित शक्तियों को समझकर आमजन के हितों की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। मोदी सरकार आने के बाद इस ओर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन केवल एक आंकड़ा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ही हम लें कि इस आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर कितने मामले दर्ज किए तो भी हम यह कहने के योग्य नहीं हैं कि देश में सभी लोग समान गरिमा के साथ जी रहे हैं। न्यायालयों में लंबित मामले की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है और समाज में हाशिये पर रहने वाले लोग अपने अधिकारों को इस संविधान के माध्यम से कैसे सुरक्षित करेंगे, यह उन्हें पता नहीं है। भारतीय सभ्यता के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।

ऐसे में संविधान के उत्सव के साथ देश के प्रत्येक नागरिक के हित-उत्सव के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। निस्संदेह वर्तमान सरकार द्वारा पीएम आवास योजना, स्टैंडअप इंडिया योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया योजना, मुद्रा योजना आदि के माध्यम से देश की जनता को सुरक्षित व गरिमामय बनाने का संकल्प दोहराया गया है। सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मानों को सुरक्षित किया जिसमें ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। ऐसी अनेक योजनाओं के साथ भारतीय संविधान के आलोक में सरकार ने कल्याणकारी होने के प्रयत्न किए हैं और 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम के माध्यम से संविधान के साथ संवाद करने की भी कोशिश की है। इससे हमारे लोकतंत्र को बहुत बल मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे न्याय की सुगमता हो और संविधान की भूमिका को धरातल स्तर तक ले जाया जाए, जिससे लोग जागरूक हों और भारत की 75 वर्षों की रोमांचकारी यात्रा को विशिष्ट बनाएं।

अमृत पर्व : जागरूक समाज ही सशक्त भारत बना सकता है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए इस 75वीं वर्षगांठ पर संपूर्ण भारत से यह अपेक्षा है कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सजग हों जिससे भारत की वैश्विक छवि और अच्छी बन सके। भारत का सच में संविधान उत्सव हो तो अपने पद का दुरुपयोग करने वाले लोग कम से कम अपनी सीमाओं में ही संविधान के मूल्यों के साथ भारतीय जनमानस को उनके न्याय दिलाएंगे तो निस्संदेह हमारे देश की सशक्त लीडरशिप को भी मदद मिलेगी। इससे देश भी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ सकेगा। यह संविधान लागू होने का अमृत पर्व है, इसलिए भारत को अमृत देश बनाने के लिए अपने अमृत मूल्यों के साथ जीना होगा।

भारतीय संविधान के समक्ष नतमस्तक होकर उसके प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते पीएम नरेन्द्र मोदी। फाइल

****

इटली की वीएलएफ ने पेश किए इलेक्ट्रिक स्कूटर

नई दिल्ली: इटली की कंपनी वीएलएफ ने केएडब्ल्यू वेलोस मोटर्स के साथ मिलकर भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर टेनिस पेश किया है। इसका एक्स शोरूम मूल्य 1.30 लाख रुपये है। इसके अलावा केडब्ल्यू वेलोस मोटर्स ने आस्ट्रिया की ब्रिक्सटन की क्रासफायर और क्रोमवेल सीरीज की मोटरसाइकिल भी भारतीय बाजार में पेश की हैं। इनका एक्स शोरूम मूल्य 4.74 लाख से 9.10 लाख रुपये तक है। (एएनआइ)

मौजूदा खाद्य महंगाई एक "अल्पकालिक झटका" है। उम्मीद है कि आने वाले दो तिमाहियों में खाद्य महंगाई में कमी के साथ उपभोक्ता मांग में सुधार होगा।
— सुनील डिसूजा, सीईओ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डालर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
80,109.85 ▲ 992.74	24,221.90 ▲ 314.65	₹ 80,000 ▼ ₹1,000	₹ 91,700 ▼ ₹1,600	₹ 84.29 ▼ ₹0.12	$ 74.87

एक नजर में

अक्टूबर में 1.36 करोड़ लोगों ने किया घरेलू हवाई सफर

मुंबई: अक्टूबर के दौरान 1.36 करोड़ लोगों ने घरेलू हवाई सफर किया है और इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.3 प्रतिशत की वृद्धि रही है। नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार, अक्टूबर 2023 में 1.26 करोड़ लोगों ने घरेलू हवाई सफर किया था। इस वर्ष अक्टूबर में 86.40 लाख यात्रियों के साथ इंडिगो पहले और 26.48 लाख यात्रियों के साथ टाटा समूह की एअर इंडिया दूसरे स्थान पर रही है। (प्रेट्र)

कमोडिटी वायदा ट्रेडिंग पर लगी रोक हटाए सरकार

नई दिल्ली: खाद्य तेल उद्योग संगठन एसईए ने सोमवार को सरकार से कच्चे पाम तेल और सोयाबीन तेल जैसे प्रमुख कृषि कमोडिटी उत्पादों की वायदा ट्रेडिंग पर लगी रोक हटाने की मांग की। सरकार ने सात कृषि उत्पादों की वायदा ट्रेडिंग पर पहली बार दिसंबर 2021 में रोक लगाई थी। अभी 20 दिसंबर 2024 तक इन उत्पादों की वायदा ट्रेडिंग पर रोक है। (प्रेट्र)

आइसक्रीम कारोबार अलग करने को एचयूएल बोर्ड राजी

नई दिल्ली: दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड (एचयूएल) के बोर्ड ने आइसक्रीम कारोबार को अलग करके नई सूचीबद्ध इकाई बनाने की मंजूरी दे दी है। एचयूएल क्वालिटी वाल्स, कारनेटो और मैग्नम ब्रांड से आइसक्रीम की बिक्री करती है। एचयूएल ने एक बयान में कहा कि मौजूदा शेयरधारकों को इसी अनुपात में नई इकाई के शेयर मिलेंगे। (प्रेट्र)

2028-29 तक 5.09 अरब टन सीमेंट का उत्पादन

नई दिल्ली: इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2028-29 तक भारत का सीमेंट उत्पादन बढ़कर 5.09 अरब टन पर पहुंच जाएगा। 2024 से 2029 के दौरान सीमेंट के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 4.9 प्रतिशत की वृद्धि रहेगी। 2022-23 में सीमेंट उत्पादन 3.82 अरब टन रहा है। उत्पादन बढ़ने में इन्फ्रा पर सरकारी खर्च का प्रमुख योगदान रहेगा। (आइएएनएस)

महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर उछले शेयर बाजार

992 अंक बढ़कर फिर 80 हजार के पार बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी 314 अंक बढ़कर 24,221 पर

जेएनएन, नई दिल्ली: देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 13 प्रतिशत से अधिक का योगदान रखने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति की जीत का बाजार ने खुलकर स्वागत किया। सोमवार को सेंसेक्स 992.74 अंक की बढ़त के साथ 80109.85 पर पहुंच गया। यह पिछले 19 दिनों का उच्चतम स्तर है। निफ्टी में भी 314.65 अंक की बढ़त दर्ज की गई और यह 24,221.90 पर बंद हुआ। महाराष्ट्र चुनाव के अलावा अदाणी कंपनियों के शेयर भाव में बढ़त से भी बाजार को समर्थन मिला। पिछले एक माह से भी अधिक समय से बाजार में उथल-पुथल का दौर जारी है।

जानकारों का कहना है कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जीत मिलने से निवेशकों का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा और इसकी बानगी सोमवार को देखने को मिली। महायुति की जीत से महाराष्ट्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की पुरानी परियोजनाएं जारी रहेंगी और पूर्ण बहुमत से सरकार के गठन से विकास की नई परियोजनाओं को शुरू करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूंजीगत खर्च में लक्ष्य के मुकाबले खर्च में कमी की भरपाई सरकार दूसरी छमाही में करेगी। इससे निजी सेक्टर के खर्च में भी तेजी आएगी। इन सब रुझान से बाजार में तेजी दिखी। जियोजित फाइनेंशिएल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में महायुति के पक्ष में चुनाव नतीजों के आने के बाद पूंजीगत खर्च में तेजी की संभावना बढ़ गई है।

दो कंपनियों को मिली आइपीओ की मंजूरी

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दो और कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है। इनमें रियल एस्टेट फर्म कल्पतरु लिमिटेड और यूनीमेक एयरोस्पेस एंड मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड शामिल हैं। दोनों कंपनियां क्रमशः आइपीओ के जरिये 1,590 करोड़ और 500 करोड़ रुपये जुटाना चाहती हैं। वहीं, एनविरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के आइपीओ को दूसरे दिन तक 12.51 गुना आवेदन मिले हैं। कंपनी ने बिक्री के लिए 3,07,93,600 शेयर पेश किए हैं।

- महाराष्ट्र में जीत मिलने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा

- चुनाव नतीजों के बाद पूंजीगत खर्च में तेजी की संभावना बढ़ी

बढ़ने वाले शेयर: लार्सन एंड टुब्रो, भारतीय स्टेट बैंक, अदाणी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक

दो सत्रों में 14.20 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की संपत्ति

घरेलू शेयर बाजारों में बीते दो सत्रों से जारी तेजी की बदौलत निवेशकों की संपत्ति में 14.20 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण बढ़कर 439.58 लाख करोड़ रुपये या 5.22 ट्रिलियन डालर हो गया है।

कमजोर वैश्विक संकेतों से एक हजार रुपये लुढ़का सोना

कमजोर वैश्विक संकेतों से सोमवार को घरेलू बाजार में सोना और चांदी के मूल्य में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में सोने के मूल्य में एक हजार रुपये घटकर 79,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,600 रुपये घटकर 91,700 रुपये प्रति किलो हो गई है।

सेंसेक्स में अदाणी की कंपनियों का हाल

गिरावट वाले शेयर	
अदाणी ग्रीन एनर्जी	8.05%
अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस	3.78%
अदाणी पावर	3.02%
एनडीटीवी	2.07%
अदाणी टोटल गैस	1.43%
बढ़त वाले शेयर	
अदाणी पोर्ट्स	2.55%
एसीसी	2.54%
अदाणी एंटरप्राइजेज	1.26%
अदाणी विल्मर	1.81%
अंबुजा सीमेंट्स	0.88%

आने वाले महीनों में भारत का आर्थिक परिदृश्य आशावादी

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले महीनों में भारत का आर्थिक परिदृश्य सतर्क रूप से आशावादी है। वित्त मंत्रालय की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून की अनुकूल स्थिति, बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खेती में इस्तेमाल होने वाले माल की पर्याप्त आपूर्ति से कृषि क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है।

आर्थिक मामलों के विभाग ने सोमवार को जारी मासिक आर्थिक समीक्षा के अक्टूबर संस्करण में कहा, 'बेहतर कृषि उपज की संभावनाओं ने चुनिंदा खाद्य वस्तुओं में मौजूदा मूल्य दबावों के बावजूद मुद्रास्फीति के परिदृश्य को नरम बना दिया है।' रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर की शुरुआत के रुझानों ने प्रमुख खाद्य कीमतों में नरमी का संकेत दिया है। हालांकि, भू-राजनीतिक कारक घरेलू मुद्रास्फीति और सप्लाई चेन को प्रभावित करना जारी रख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, खरीफ की बंपर फसल से आने वाले महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति के कम होने की उम्मीद है। इसके मुताबिक, धुंधली वैश्विक पृष्ठभूमि के बीच भारत में आर्थिक गतिविधियों के कई उच्च आवृत्ति संकेतकों ने अक्टूबर में वापसी दिखाई है।

कार्यबल का हो रहा विस्तार

रिपोर्ट में कहा गया है कि औपचारिक कार्यबल का विस्तार हो रहा है और मैन्यूफैक्चरिंग नौकरियों में उल्लेखनीय वृद्धि और संगठित क्षेत्रों में युवाओं का मजबूत प्रवाह है। विकसित बाजारों में मांग में नरमी के चलते भारत के निर्यात क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सर्विस सेक्टर में गति जारी रहने की उम्मीद जताई गई है।

बीते पांच वर्षों के दौरान 6.82 लाख करोड़ रुपये के एनपीए की वसूली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वर्ष 2017-18 में जब भारतीय बैंकिंग सेक्टर में फंसे कर्ज (एनपीए) का स्तर 10 प्रतिशत (बैंकों की तरफ से वितरित कुल कर्ज के अनुपात में) हो गया था तब कई घरेलू और विदेशी वित्तीय एजेंसियों ने भारतीय बैंकिंग को लेकर तरह-तरह के सवाल खड़े किए थे। हालांकि अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। देश के सभी बड़े बैंकों का शुद्ध एनपीए का स्तर एक प्रतिशत से नीचे आ चुका है। सरकार की तरफ से जो आंकड़ें सोमवार को सदन में पेश किए गए, उससे भी संकेत मिलते हैं कि कर्ज वसूली का सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों में 6,82,286 करोड़ रुपये की राशि की वसूली बकायेदारों से की जा चुकी है, जिसने एनपीए के स्तर को नीचे लाने में अहम भूमिका निभाई है।

5,53,057 करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टे खाते में डाला तीन वर्षों में विभिन्न बैंकों ने

विभिन्न बैंकों का दूसरी तिमाही के बाद एनपीए स्तर	
एसबीआइ	0.58%
पीएनबी	0.48%
एचडीएफसी बैंक	0.41%
आइसीआइसीआइ	0.42%

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया है, 'पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय बैंकों ने कुल 1,70,107 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाला है। जबकि पिछले तीन वित्त वर्षों की बात करें तो यह राशि 5,53,057 करोड़ रुपये है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि सरकार के स्तर पर बैंकों के बकाए कर्ज की राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला जाता बल्कि यह कदम बैंकों के स्तर पर उठाया जाता है। साथ ही बट्टे खाते में डालने का मतलब यह नहीं है कि उक्त खाताधारकों से फिर उस कर्ज की वसूली नहीं की जाएगी। बैंक आगे भी कर्ज वसूली की प्रक्रिया जारी रखते हैं।'' सनद रहे कि बैंक जितनी बकाए कर्ज की राशि बट्टे खाते में डाल देते हैं उसका बहुत ही कम हिस्सा फिर वसूल हो पाता है। बीते मानसून सत्र में ही वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में बताया गया था कि विगत पांच वर्षों में जितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई है उसमें से सिर्फ 18.70 प्रतिशत हिस्सा ही बाद में वसूलने में सफलता मिली है।

एसएंडपी ने अगले दो वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान घटाया

नई दिल्ली, प्रेट्र: रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले दो वित्त वर्षों के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को कम कर दिया है। इसका प्रमुख कारण ऊंची ब्याज दर से शहरी मांग में कमी आना है।

एशिया-प्रशांत के लिए अपने आर्थिक पूर्वानुमान को अपडेट करते हुए रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 6.7 प्रतिशत और उसके अगले वित्त 2026-27 में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह पिछले अनुमानों क्रमशः 6.9 और सात प्रतिशत से कम है। रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एसएंडपी ने चीन के लिए 2024 में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा, लेकिन अगले वर्ष के लिए पूर्वानुमान को पहले के 4.3 प्रतिशत से घटाकर 4.1 प्रतिशत कर दिया है।

पहले सात महीनों में 10 अरब डालर के आइफोन का उत्पादन

नई दिल्ली, आइएएनएस: अमेरिका की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एपल ने चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों यानी अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान भारत में 10 अरब डालर से ज्यादा के आइफोन का उत्पादन किया है। इसमें से सात अरब डालर के आइफोन का निर्यात किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने भारत में 14 अरब डालर के आइफोन का उत्पादन किया था। इसमें से 10 अरब डालर से ज्यादा के आइफोन का निर्यात किया था।

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को एक्स पोस्ट में कहा कि स्मार्टफोन की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना के लिए यह एक और मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि बीते चार वर्षों में एपल के इकोसिस्टम ने देश में 1.75 लाख नई नौकरियां सृजित की हैं। इसमें 72 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। उद्योग के डाटा के अनुसार, एपल हर महीने करीब एक अरब डालर के आइफोन का निर्यात कर रही है।

- अप्रैल-अक्टूबर में सात अरब डालर के आइफोन का निर्यात

14 अरब डालर के आइफोन का उत्पादन हुआ था पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान

जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के दौरान भारत में एपल का राजस्व सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा था। तब कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा था कि हम भारत के आंकड़ों से काफी उत्साहित हैं। यह एपल में इनोवेशन का एक असाधारण वर्ष रहा है। 2023-24 में एपल का भारत में संचालन राजस्व 36 प्रतिशत बढ़कर 66,700 करोड़ रुपये और लाभ 2,746 करोड़ रुपये रहा था।

मांग बढ़ाने के लिए होम लोन के ब्याज पर मिले शत-प्रतिशत कर छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र: क्रेडाई ने सोमवार को सरकार से किफायती और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए घरों की मांग को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम के तहत होम लोन पर भुगतान जाने वाले ब्याज पर शत-प्रतिशत कर छूट का लाभ देने को कहा है।

रियल एस्सेट कंपनियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई के प्रेसिडेंट बोमन ईरानी ने संगठन के 25वें स्थापना दिवस पर यह भी सुझाव दिया कि सरकार को किफायती और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की मांग को बढ़ावा देने के लिए 75-80 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माणाधीन मकानों पर एक प्रतिशत जीएसटी लगाना चाहिए। अभी 45 लाख रुपये तक के निर्माणाधीन किफायती घरों पर एक प्रतिशत जीएसटी है। वहीं 45 लाख रुपये से अधिक लागत वाले निर्माणाधीन घरों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है।

राष्ट्रीय फलक

टोटलएनर्जीज ने अदाणी समूह में निवेश रोका

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका में रिश्वत का मामला दर्ज होने के बाद अदाणी समूह को लगातार कारोबारी झटके लग रहे हैं। केन्या की ओर से दो समझौते रद करने और बांग्लादेश की तरफ से बिजली खरीद समझौते की समीक्षा करने के एलान के बाद अब फ्रांस की टोटलएनर्जीज ने निवेश रोकने की बात कही है। फ्रांस की दिग्गज ऊर्जा कंपनी टोटलएनर्जीज एसई ने सोमवार को कहा है कि वह अदाणी समूह की कंपनियों में तब तक कोई नया निवेश नहीं करेगी जब तक समूह के संस्थापक रिश्वत देने के आरोपों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसे कथित भ्रष्टाचार की जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं जीक्यूजी पार्टनर्स अदाणी समूह में आगे भी निवेश की बात दोहराई है। जीक्यूजी पार्टनर्स का अदाणी की विभिन्न कंपनियों में 8.1 अरब डालर का निवेश है।

टोटलएनर्जीज गौतम अदाणी की कंपनियों में निवेश करने वाले सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। टोटलएनर्जीज ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) और सिटी गैस इकाई अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल) में हिस्सेदारी ले रखी है। कंपनी के चेयरमैन गौतम अदाणी और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी अदालत में सौर ऊर्जा ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है।

- फ्रांस की कंपनी ने कहा, रिश्वत के आरोपों से मुक्त होने तक नहीं करेंगे नया निवेश

टोटलएनर्जीज एसई। फाइल

बाहरी कर्ज पर निर्भरता के बिना भी वृद्धि मुमकिन

नई दिल्ली, प्रेट्र : अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी के समूह ने सोमवार को निवेशकों के सामने अपनी विभिन्न कंपनियों के वित्तीय और कर्ज से जुड़े विवरण पेश किए। इसमें कंपनी के मजबूत मुनाफे और नकदी प्रवाह के बारे में बताया गया, जिसके अनुसार बाहरी कर्ज पर निर्भरता के बिना भी वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है।

समूह ने पिछले छह महीनों में करीब 75,227 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि कुल कर्ज में केवल 16,882 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। समूह ने कहा, 'अदाणी समूह की कंपनियों के पास कम से कम 12 महीनों के लिए सभी कर्ज से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है।

30 सितंबर, 2024 तक अदाणी की कंपनियों के पास 53,024 करोड़ रुपये की नकदी थी, जो इसके कुल सकल कर्ज बकाया का 21 प्रतिशत के करीब है।' समूह ने अगले 10 वर्षों में कंपनियों में आठ लाख करोड़ रुपये (100 अरब डालर) से अधिक निवेश का एलान किया है। पिछले 12 महीनों में परिचालन से नकदी प्रवाह (एफएफओ) या नकद लाभ 58,908 करोड़ रुपये रहा और पिछले पांच वर्षों से इसमें 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है।

- अदाणी समूह ने निवेशकों के सामने विभिन्न कंपनियों के वित्तीय और कर्ज से जुड़े विवरण किए पेश

गौतम अदाणी। फाइल

तेलंगाना सरकार ने अदाणी का 100 करोड़ का दान ठुकराया

हैदराबाद, प्रेट्र : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार यहां स्थापित की जा रही यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी द्वारा दिए जाने वाले 100 करोड़ रुपये के दान को स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब अदाणी समूह के अध्यक्ष पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाया गया है।

रेड्डी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार अदाणी समूह पर लगे आरोपों के बीच खुद को किसी भी अनचाहे विवाद में शामिल नहीं होने देना चाहती है। अभी तक तेलंगाना सरकार ने अदाणी समूह सहित किसी भी संगठन से अपने खाते में एक भी रुपया स्वीकार नहीं किया है। मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी ऐसी अनावश्यक चर्चाओं और स्थितियों में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जिससे राज्य सरकार या मेरी छवि को नुकसान पहुंचे।

- यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अदाणी ने किया था दान देने का एलान
- सीएम ने कहा, अनचाहे विवाद में शामिल नहीं होना चाहती सरकार

राज्य के विशेष मुख्य सचिव (उद्योग) जयेश रंजन ने अदाणी फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रीति अदाणी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा धन नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने कौशल विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये का दान देने संबंधी घोषणा के लिए प्रीति अदाणी का धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अब तक किसी भी दानदाता से धन का हस्तांतरण करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80-जी के तहत आयकर छूट नहीं मिली है। विश्वविद्यालय को हालांकि हाल ही में आयकर छूट का आदेश मिल गया है।

ईएजी समूह के देशों ने भारत की एफएटीएफ रैंकिंग का किया समर्थन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: यूरेशियन समूह (ईएजी) के सभी सदस्य देशों ने मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना की है। साथ ही, वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा भारत को दी गई फालोअप रैंकिंग का समर्थन भी किया है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारत की साख बढ़ेगी। सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर नियंत्रण के लिए भारत अपना दबाव बढ़ा सकेगा।

इंदौर में सोमवार से शुरू हुई ईएजी की 41वीं प्लेनरी और कार्यकारी समूह की पांच दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका, जापान, यूएई, आर्मेनिया सहित 16 देशों और 13 संगठनों के 175 प्रतिनिधि पहुंचे हैं। उद्घाटन सत्र में एफएटीएफ की पारस्परिक मूल्यांकन की रिपोर्ट को ईएजी के कार्य समूह में पेश किया गया और उस पर चर्चा की गई।

आरबीआइ की सख्ती के बाद कर्ज देने के नियम एमएफआइएन ने किए कड़े

मुंबई, प्रेट्र : छोटी राशि के कर्ज देने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों के नेटवर्क (एमएफआइएन) ने सोमवार को समाज में वंचित तबकों को अधिक जिम्मेदार तरह से कर्ज देने के लिए कुछ बदलावों का एलान किया। उद्योग की गतिविधियों पर आरबीआइ की बार-बार सख्ती के बाद यह कदम उठाया गया है। एमएफआइएन ने कहा कि एक जनवरी से, स्व-नियामक संगठन के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि एक सूक्ष्म वित्त संस्थान के ग्राहक का कर्ज वर्तमान में चार के मुकाबले तीन एमएफआइ तक सीमित हो। साथ ही एमएफआइ और असुरक्षित माने जाने वाले खुदरा कर्ज सहित एक उधारकर्ता की कुल कर्ज देनदारी दो लाख रुपये तक सीमित हो। संस्था के मुख्य कार्यकारी और निदेशक आलोक मिश्रा ने उम्मीद जताई कि नए उपायों से यह क्षेत्र 'अधिक लचीला' बन जाएगा।

एमएफआइएन दिशानिर्देशों के अनुसार, इन वित्तीय संस्थानों ने कर्जदाताओं को ऐसे ग्राहक को ऋण देने के नियम भी कड़े कर दिए हैं, जो गैर-निष्पादित परिसंपत्ति श्रेणी में आ गए हैं। गड़बड़ी करने वाले ऐसे किसी ग्राहक को कोई कर्ज नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 60 दिन से अधिक समय से 3,000 रुपये से अधिक का बकाया नहीं चुकाया है। वर्तमान में यह समयसीमा 90 दिन है। आरबीआइ ने पिछले कुछ महीनों में एमएफआइ की कई गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। आरबीआइ ने 21 अक्टूबर को नवी फिनसर्व, डीएमआइ फाइनेंस, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस सहित चार इकाइयों को अनुचित गतिविधियों के कारण नए कर्जों को मंजूरी देने और वितरित करने से मना किया।

- 60 दिन से अधिक समय से 3,000 रुपये से अधिक का बकाया नहीं चुकाने वाले ग्राहकों नहीं मिलेगा कर्ज

उप्र में कमिश्नर, डीएम पर निवेश लाने की जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने के लिए योगी सरकार ने अनूठी पहल की है। अब राज्य में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) में निवेश आकर्षण और सीडी रेशियो (ऋण जमा अनुपात) वृद्धि को भी शामिल किया जाएगा। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सीडी रेशियो बैंकों द्वारा जिलों में दिए गए ऋण और उनके द्वारा जमा की गई धनराशि का अनुपात है। यह आर्थिक गतिविधियों के स्तर और वित्तीय संसाधनों के उपयोग का एक प्रमुख संकेतक है। जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों के प्रदर्शन का आकलन उनके जिलों में सीडी रेशियो में की गई प्रगति के आधार पर भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य जिलों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, निवेश बढ़ाना और बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना है।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में सीडी रेशियो वृद्धि के साथ-साथ निवेशकों की सुरक्षा, सुविधाएं और सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए किए गए प्रयासों का भी मूल्यांकन होगा। इसके तहत उद्यमियों के लिए समयबद्ध तरीके से जमीन आवंटन, सब्सिडी, भू उपयोग परिवर्तन, लैंड क्लीयरेंस समेत लैंड बैंक को तैयार कर उसकी निगरानी और नियमित अपडेशन किए जाने का भी मूल्यांकन किया जाएगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि जिलों में निवेश लाने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारी अपनी भूमिका को जिम्मेदारी से निभाएं। इससे ईज आफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव के अनुसार, राज्य सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक 65 प्रतिशत के सीडी रेशियो के लक्ष्य को तय करके आगे बढ़ रही है।

इस रेशियो का बढ़ना राज्य में आर्थिक स्थिरता और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का संकेत है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने जिलों में निवेश को मापने और बढ़ावा देने के लिए सीडी रेशियो को प्राथमिकता दी है। यह नीति न केवल आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी, बल्कि सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी।

योगी सरकार का फैसला

- अधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (एसीआर) में दर्ज होगा निवेश बढ़ाने के क्या प्रयास किए
- निवेशकों की सुरक्षा, सुविधाओं और सहूलियतों के लिए किए गए प्रयासों का भी होगा मूल्यांकन
- शासनादेश जारी, ईज आफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली को छोड़ पूरे देश में दो रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई सीएनजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुंबई के साथ-साथ देश के कई अन्य शहरों में सीएनजी की कीमत में दो रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन चुनावी राज्य दिल्ली में उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे छूट दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में सीएनजी और खाना पकाने के लिए घरों में पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस पहुंचाने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) ने सप्ताहांत में सीएनजी की कीमत में दो रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अन्य शहरों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन दिल्ली को इससे छूट दी गई है, जहां कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एमजीएल की वेबसाइट के अनुसार, चुनाव समाप्त होने के साथ ही मुंबई में गैस की खुदरा बिक्री करने वाली महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमतों में दो रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। एमजीएल और अदाणी टोटल गैस लिमिटेड जैसे अन्य गैस वितरकों ने कच्चे माल की लागत में 20 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद पिछले दो महीनों से खुदरा कीमतों को यथावत रखा था। मुंबई में विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही एमजीएल ने 23 नवंबर से सीएनजी की कीमतें दो रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 77 रुपये कर दी।

आइजीएल की वेबसाइट के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कीमतें दो रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर 81.70 रुपये और गुरुग्राम में 82.12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तब आइजीएल ने दिल्ली में सीएनजी कीमतों में बदलाव किया था।

- विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ सकते हैं सीएनजी के दाम

****

1200 1,200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बना लिए गए सात अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले में। तब से अब तक हमास और इजरायल में युद्ध जारी है।

लेबनान के साथ युद्धविराम के करीब पहुंचा इजरायल

चर्चा के लिए इजरायली कैबिनेट की बैठक आज

इजरायल-हिजबुल्ला संघर्ष समाप्त करने के लिए शर्तों पर सहमत होने का दावा

बेरूत के दक्षिणी इलाके में सोमवार को इजरायली हवाई हमले के बाद उठता धुएं का गुबार। एएफपी

यरुशलम, रायटर : एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि लेबनान युद्धविराम समझौते को मंजूरी देने के लिए इजरायली कैबिनेट मंगलवार को बैठक करेगी, जिसे आने वाले दिनों में पुख्ता किया जा सकता है। एक लेबनानी अधिकारी ने कहा कि बेरूत को वाशिंगटन ने बताया था कि समझौते की घोषणा कुछ घंटों के भीतर की जा सकती है। इजरायली अधिकारियों ने पहले कहा था कि युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता के करीब पहुंच चुके है, हालांकि अब भी कुछ मुद्दों को हल किया जाना बाकी है, जबकि दो वरिष्ठ लेबनानी अधिकारियों ने इजरायली हमलों के बावजूद समझौते को लेकर आशा जताई थी। अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने कहा कि इजरायल-हिजबुल्ला के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए इजरायल और लेबनान एक समझौते की शर्तों पर सहमत हुए थे। उम्मीद है कि इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट मंगलवार को इस सौदे को मंजूरी दे देगी। हालांकि इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उसे रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहना है।

इस बीच हमले भी जारी हैं। बेरूत में इजरायली हवाई हमलों ने सोमवार को हिजबुल्ला नियंत्रित दक्षिणी उपनगरों के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया गया। इससे पहले सप्ताहांत में इजरायल ने बेरूत में 29 लोग मार गिराए थे। वहीं हिजबुल्ला ने रविवार को अपने सबसे बड़े राकेट हमलों में से एक लांच किया था, जिसमें 250 मिसाइलें दागी गई थीं। एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूह ने सोमवार को कहा कि 25 अक्टूबर को लेबनान में इजरायली हवाई हमले में तीन पत्रकारों की मौत हो गई थी और अन्य घायल हो गए थे। संभवतः यह नागरिकों पर जानबूझकर किया गया हमला और स्पष्ट युद्ध अपराध था।

बता दें, सात अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बना लिए गए। इससे गाजा में इजरायली सैन्य आक्रमण शुरू हो गया।

इजरायल और ईरान के संपर्क में है भारत : जयशंकर

- विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिम एशिया में शीघ्र शांति का आह्वान किया
- कहा-भारत दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक, फलस्तीन समस्या का हल हो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत ने एक बार फिर यूक्रेन-रूस के हालात के साथ ही पश्चिम एशिया की तनावपूर्ण स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और सभी संबंधित देशों व दूसरे प्रमुख देशों से आह्वान किया है कि वह इसे हल करने में शीघ्रता दिखाएं। दीर्घकालिक समाधान के लिए फलस्तीन समस्या का समाधान होना चाहिए। भारत दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रोम मेडिटेरिनियन डायलाग-2024 में पश्चिम एशिया की स्थिति को सीधे तौर पर भारत के हितों से जोड़ते हुए कहा कि इन देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं। खाड़ी के देशों के साथ भारत का सालाना कारोबार 160-180 अरब डालर का है। यहां के एनर्जी, प्रौद्योगिकी व औद्योगिकी परियोजनाओं में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। इस क्षेत्र के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सुरक्षा के लिहाज से गहरा जुड़ाव है। इस चर्चा का आयोजन दुनिया के सबसे अमीर सात देशों के संगठन जी-7 की तरफ से किया गया है जिसमें समूचे भूमध्य सागर की मौजूदा भौगोलिक व रणनीतिक हालात पर चर्चा की गई है।

पश्चिम एशिया की स्थिति को खास तौर पर चिंताजनक बताते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत इजरायल और ईरान दोनों के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बना कर रखे हुए हैं, ताकि संयम बरता जाए और संवाद कायम रहे। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, अभी तक वहां जो हुआ है उसके लिए भी और जो हो सकता है उस नजरिए से भी।

जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद और बंधक समस्या दोनों की निंदा करता है। हमें तत्काल इस क्षेत्र में सीजफायर लागू करना चाहिए। हमारी चिंता इस संकट के विस्तार को लेकर भी है। इसके समाधान के लिए भारत अपनी पूरी मदद करने को तैयार है। इसके साथ ही अमेरिका, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत को मिला कर गठित संगठन आइ2यू2 के संदर्भ में जयशंकर ने कहा कि यह आने वाले दिनों में और ज्यादा सक्रिय होगा।

कनाडा में हिंदू छात्र नेताओं को साथ लाने को मिलन सत्र आयोजित

टोरंटो, एएनआइ : हिंदू छात्र परिषद (एचएससी) कनाडा ने ओसीएडी विश्वविद्यालय टोरंटो में एक मिलन और अभिवादन सत्र की मेजबानी की। विभिन्न परिसरों से हिंदू छात्र नेताओं को अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा करने के लिए साथ लाया गया। एचएससी के सदस्य रविवार शाम गठबंधन आफ हिंदूज आफ नार्थ अमेरिका (सीओएचएनए) और हिंदू फोरम आफ कनाडा के हिंदू छात्र नेताओं के साथ एकत्र हुए। छात्रों ने हिंदुओं के प्रति बढ़ती हिंसा के संदर्भ में चुनौतियों को साझा किया और शिक्षा जगत में उचित स्थान स्थापित करने में संघर्षों और उपलब्धियों को साझा किया।

हिंदू छात्र नेताओं ने भी भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण बनी नकारात्मक माहौल के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम के बाद छात्रों ने अपने पूजा कक्ष में जय श्री राम का नारा लगाया। कार्यक्रम के बाद एक छात्र ने कहा कि हिंदू छात्र परिषद उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा अखिल हिंदू युवा संगठन है और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिंदुओं को अपने धर्म को व्यक्त करने और परिसरों में सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। एक अन्य छात्र ने कहा कि मेरा मानना है कि परिषद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल युवाओं को बल्कि हर किसी को हिंदू धर्म और हमारी संस्कृति के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने से लाभ होगा।

कनाडा व बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में सिलिकान वैली में रैली

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों ने कनाडा और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर विरोध जताया। भारतवंशियों ने उनके समर्थन में सिलिकान वैली में एकजुटता रैली निकाली। मिल्पिटास सिटी हाल में बड़ी संख्या में भारतवंशी जुटे। उन्होंने हमलों का जिक्र करते हुए अमेरिकी नेताओं से खुलेआम हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा करने और कनाडा और बांग्लादेश सरकार को हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की। भारतवंशियों ने कनाडा के ब्रैम्पटन स्थित मंदिर में खालिस्तान समर्थकों की ओर से किए गए हमलों से ठीक ढंग से न निपटने पर निराशा व्यक्त की। रैली में मौजूद लोग खालिस्तानी आतंकवाद रोको और कनाडा में हिंदुओं की सुरक्षा, इस्लामिक आतंकवाद रोको और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के नारे लगाए। भारतवंशियों का कहना था कि हमने वीडियो देखे हैं, जिनमें खालिस्तानी आतंकी मंदिर परिसर में प्रवेश करते और महिला, पुरुष और बच्चों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। दीपावली का त्योहार मनाने गए हिंदुओं को उन गुंडों द्वारा प्रताड़ित होते देखना भयानक था। हमने देखा कि पुलिस खालिस्तान समर्थकों के समर्थन में खड़ी थी और हिंदू भक्तों की पिटाई कर रही थी। कनाडा में हिंसा की आजादी को अभिव्यक्ति की आजादी का जामा पहनाया जा रहा है।

न्यूज गैलरी

खैबर पख्तूनख्वा में कबीलों के बीच सात दिन का संघर्ष विराम

पेशावर : एक वाहन पर हमले में 50 के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम में शिया और सुन्नी कबीलों के बीच जारी खूनी संघर्ष थम गई है। कबीलों के बीच सात दिन के संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। बदले की कार्रवाई को लेकर शुरू हुए शिया-सुन्नी कबीलों के बीच संघर्ष में पिछले सप्ताह 64 लोगों की जान जा चुकी है। (एएनआइ)

रब्बी की हत्या के आरोप में यूएई में तीन उज्बेकी गिरफ्तार

दुबई : संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि इजरायली-मोल्डोवन रब्बी की हत्या के आरोप में पुलिस ने सोमवार को उज्बेकिस्तान के तीन नागरिकों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्रालय के एक बयान में रब्बी जवी कोगन की गला रेतकर हुई हत्या का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है।। (एपी)

पृथ्वी पर गिरे चीनी राकेट के मलबे का अधिकांश भाग जला

बीजिंग : हाल ही में प्रक्षेपित चीन के लांग मार्च-7 वाई 9 कैरियर राकेट का मलबा रविवार रात पृथ्वी पर गिर। मलबे का अधिकांश भाग जल गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि राकेट का मलबा अटलांटिक महासागर में गिरा। (आइएएनएस)

इस्लामाबाद की ओर बढ़े इमरान समर्थक, एक पुलिसकर्मी की मौत

- भारी मशीन से लैस पीटीआइ कार्यकर्ताओं ने अवरोध हटाए
- कई को पीटीआइ ने बंधक बनाया
- खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने कहा, इमरान की रिहाई तक पीछे नहीं हटेंगे

सोमवार को इस्लामाबाद में तैनात सुरक्षा बल के जवान। रायटर

इस्लामाबाद, प्रेट्र : जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के कार्यकर्ता और समर्थक लगातार इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के विभिन्न भागों में पीटीआइ समर्थकों के साथ संघर्ष में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए। कई पुलिसकर्मी बंधक बना लिए गए हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में प्रवेश करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पीटीआइ समर्थकों को रोकने में पुलिस विफल रही। 1:33 बजे हसनबादल पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने स्वाबी में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि इमरान की रिहाई तक हम वापस नहीं लौटेंगे। उनके साथ चल रही इमरान की पत्नी बुशरा ने भी अपने पति को रिहा करने की मांग की।

रास्ते में लगाए गए अवरोधों को हटाने के बाद पीटीआइ कार्यकर्ता सोमवार को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ गए। पीटीआइ कार्यकर्ता इस बार बुलडोजर और भारी मशीनें साथ लेकर चल रहे हैं। कई स्थानों पर रविवार को पीटीआइ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बावजूद 60 से ज्यादा स्थानों पर पार्टी ने प्रदर्शन किया। इमरान ने लोगों से 24 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। पीटीआइ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और पार्टी के विभिन्न नेताओं ने रावलपिंडी के समीप अदियाला जेल में इमरान से मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान पीटीआइ के प्रदर्शन से असहज स्थिति का सामना कर चुके इस्लामाबाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर रखी है। बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

अमेरिका जाकर प्रशांत किशोर ने बिहार को विफल राज्य बताया

वाशिंगटन, प्रेट्र : प्रशांत किशोर ने अमेरिका में बिहार को एक विफल राज्य बताया। उन्होंने कहा कि वह गहरे संकट में है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए जबरदस्त प्रयासों की जरूरत है। जन सुराज के अमेरिकी चैप्टर के लांच के बाद अमेरिका में रहने वाले बिहार के लोगों के साथ एक वर्चुअल बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जीतेगी। जीतने के बाद एक घंटे में वह शराब पर प्रतिबंध हटा देंगे और राजस्व का इस्तेमाल स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए करेंगे। हाल में बिहार में हुए उपचुनाव में चार सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी पर हार का सामना करना पड़ा।

प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने जनसंख्या के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। बिहार की स्थिति में सुधार को लेकर समाज निराश हो गया है। विफल राज्य की विशेषताएं यहां की जनसंख्या में दिखाई देती हैं।

यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले ब्रिटिश नागरिक को रूसी सेना ने पकड़ा

- यूक्रेन के लिए लड़ते हुए रूसी धरती पर पकड़े गए किसी पश्चिमी नागरिक का पहला मामला
- ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि अपने नागरिक को हरसंभव सहायता देने का प्रयास करेंगे

मास्को, एपी : रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों की ओर से लड़ रहे एक ब्रिटिश नागरिक को पकड़ा है। यह जानकारी रूसी समाचार एजेंसी ने सूत्रों का हवाला दी है। एजेंसी ने उस व्यक्ति की पहचान जेम्स स्काट राइस एंडरसन के रूप में की है। रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन अगर पुष्टि होती है तो यह यूक्रेन के लिए लड़ते हुए रूसी धरती पर पकड़े गए किसी पश्चिमी नागरिक का पहला सार्वजनिक रूप से ज्ञात मामला हो सकता है।

स्काट ने चार साल तक ब्रिटिश सेना में सिग्नलमैन के रूप में काम किया था। बाद में वह इंटरनेशनल लीजन आफ यूक्रेन में शामिल हो गया, जिसका गठन रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत में हुआ था। एंडरसन यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित कर रहा था। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कुर्स्क क्षेत्र में तैनात किया गया था।

उसका एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह कहता नजर आ रहा है कि वह यहां नहीं रहना चाहता। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा, "मुझे घटनाक्रम के बारे में अपडेट किया गया है। हम ब्रिटिश नागरिक को हरसंभव सहायता देने का प्रयास करेंगे।" वहीं, रूसी सेना ने यूक्रेन के मायकोलाइव में ऊर्जा ढांचे और जोपोरीजिया में औद्योगिक सुविधा केंद्र पर हमला बोला है। इसके कारण कई इलाकों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ा।

ब्रिटेन ने रूस के शैडो फ्लीट पर लगाया प्रतिबंध

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने सोमवार को कहा कि रूस के शैडो फ्लीट के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें 30 जहाजों को लक्षित किया गया है। रूसी तेल पर पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए उपयोग होने वाले जहाजों के बेड़े को शैडो फ्लीट कहा जाता है। ब्रिटेन के नए प्रतिबंध के बाद प्रतिबंधित तेल टैंकरों की संख्या 73 हो जाएगी। वहीं, एएनआइ के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के बैंकिंग क्षेत्र पर हाल में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध की प्रशंसा की है। अमेरिका ने 21 नवंबर को रूस के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के उपयोग को कम करने के लिए ये प्रतिबंध लगाए थे।

30 अक्टूबर को चिन्मय सहित 19 पर दर्ज हुआ था मुकदमा

प्रथम पृष्ठ से आगे

सनातनी जोत के प्रमुख आयोजक गौरांग दास ब्रह्मचारी के हवाले से एक न्यूज पोर्टल ने कहा कि चिन्मय को ढाका से हवाई मार्ग से चटगांव जाना था। 30 अक्टूबर को हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान चटग्राम के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए चटग्राम के कोतवाली पुलिस स्टेशन में चिन्मय सहित 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस बीच, चिन्मय की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग बंदरगाह शहर के चेरागी पहाड़ चौराहे पर सड़कों पर उतर आए। वहीं, राजधानी में हिंदू समुदाय के लोगों ने गिरफ्तारी के विरोध में देर शाम शाहबाग चौराहे पर जाम लगा दिया।

यह पहली बार नहीं जब लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं

प्रथम पृष्ठ से आगे

वैसे देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोग पाक सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। पिछले साल अक्टूबर में भी गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोग पाकिस्तान से आजादी के लिए सड़कों पर आ गए थे। असल में वहां के लोग पाकिस्तान सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि वहां की जनता पाकिस्तान सरकार के दोहरे रवैये, सेना की बर्बरता से बेहद तंग आ चुकी है और मुक्ति चाहती है। वहां के लोग खुद को भारत में शामिल करने की मांग करते रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में यह मांग और बलवती हुई है।

केंद्र की राजग सरकार ने दिया था गुलाम जम्मू-कश्मीर नाम : 2015 में केंद्र में सत्तारूढ़ राजग सरकार के किसी आधिकारिक दस्तावेज में गुलाम कश्मीर को गुलाम जम्मू-कश्मीर के रूप में संदर्भित किया था। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एकीकृत कश्मीर पर भाजपा के वादे के अनुरूप था। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में भी इसका जिक्र किया था। यह संदर्भ गृह मंत्रालय (एमएचए) की 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में था, जिसे संसद में पेश किया गया था। उप-शीर्षक "जम्मू और कश्मीर और गुलाम जम्मू-कश्मीर के बीच क्रास एलओसी व्यापार" के तहत जारी उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2015 दिसंबर तक 45,486 ट्रक गुलाम जम्मू-कश्मीर में गए हैं और 28,891 ट्रक दो मार्गों श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट के माध्यम से भारत की ओर आए हैं।

पिछले वर्ष रोज 140 महिलाओं की साथी या रिश्तेदारों ने ली जान

- संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आई तस्वीर
- अफ्रीका में इसकी दर सबसे ज्यादा, यूरोप में सबसे कम

संयुक्त राष्ट्र, एपी : महिलाओं के लिए घर ही सबसे घातक जगह बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों ने सोमवार को बताया कि पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन 140 महिलाओं एवं लड़कियों की हत्या उनके घरों में ही अंतरंग साथी (इंटीमेट पार्टनर) या परिवार के सदस्य द्वारा की गई। यूएन वूमेन और यूएन आफिस आफ ड्रग्स एंड क्राइम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर 2023 के दौरान लगभग 51,100 महिलाओं और लड़कियों की मौत के लिए उनका अंतरंग साथी या परिवार का सदस्य जिम्मेदार रहा। 2022 में यह आंकड़ा अनुमानित तौर पर 48,800 था। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि हत्याओं में बढ़ोतरी के कारण नहीं, बल्कि मुख्य रूप से विभिन्न देशों से अधिक आंकड़े उपलब्ध होने के कारण है। दोनों एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया कि हर जगह महिलाएं और लड़कियां लिंग आधारित हिंसा के इस चरम रूप से प्रभावित हो रही हैं और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। घर महिलाओं और लड़कियों के लिए सबसे खतरनाक जगह हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अंतरंग साथी और परिवार के सदस्यों द्वारा की गई हत्याओं के सबसे अधिक मामले अफ्रीका में थे, जहां 2023 में लगभग 21,700 महिलाएं पीड़ित थीं। पीड़ितों की संख्या में अफ्रीका सबसे आगे रहा, यहां प्रति एक लाख लोगों पर 2.9 पीड़ित थीं। पिछले वर्ष अमेरिका में भी यह दर काफी अधिक थी, जहां प्रति एक लाख में 1.6 महिलाएं पीड़ित थीं, जबकि ओशिनिया (प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश) में यह दर प्रति एक लाख में 1.5 थी। एशिया में यह दर काफी कम थी, जहां प्रति एक लाख पर 0.8 पीड़ित थीं, जबकि यूरोप में यह दर प्रति एक लाख में 0.6 रही।

यूरोप व अमेरिका में महिलाओं की जानबूझकर हत्या मुख्यतः उनके अंतरंग साथियों द्वारा की जाती है। इसके विपरीत, पुरुषों की हत्या की अधिकांश घटनाएं बाहर होती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 'हालांकि हत्या के शिकार अधिकतर पुरुष व लड़के होते हैं, लेकिन फिर भी निजी स्थानों पर घातक हिंसा से महिलाएं व लड़कियां ही प्रभावित होती हैं।'

अनूठा विरोध प्रदर्शन : हर दिन किसी महिला को उसका साथी मारता है या मारने की कोशिश करता है और यह हमारे समाज का बेहद नकारात्मक पहलू है। इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस की शुरुआत की गई। इस मौके पर सोमवार को जर्मनी के कोलोन में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नारंगी रंग के चप्पल-जूते रखकर हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को याद किया। यह एक बेहद मार्मिक दृश्य है जो हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दुखद प्रभाव और इस मुद्दे के प्रति जागरूक रहने के साथ पीड़ितों का साथ देने की याद दिलाता है। एपी

राष्ट्रीय फलक

झारखंड के चक्रधरपुर में उग्रवादियों ने दो को मार डाला

- अवैध बालू उठाव व लेवी वसूली से जुड़ा है मामला, नक्सलियों ने लगाए थे पोस्टर

जासं, सोनुवा (पश्चिमी सिंहभूम)

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुदड़ी में नक्सलियों द्वारा आम लोगों की हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार देर रात करीब ग्यारह बजे पीएलएफआइ के उग्रवादियों ने यहां चक्रधरपुर क्षेत्र के गिरु गांव में दो युवकों की धारदार हथियार व लाठी-डंडे से मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान गिरु गांव के 22 वर्षीय रवि तांती व खूंटी के युवक घनसा टोपनो के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर सोमवार सुबह चक्रधरपुर के एसडीपीओ नलिन कुमार मरांडी समेत पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और छानबीन कर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया।

पुलिस को प्रतिबंधित उग्रवादी माओवादी संगठन पीएलएफआइ के द्वारा अंजाम दिए जाने की आंशका है। ग्रामीणों के मुताबिक कि गिरु गांव के चौक में स्थित एक पेड़ पर नक्सलियों की ओर से पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें गुदड़ी के पींडिंग से गोइलकेरा के सेरेंगदा तक बालू उठाव बंद करने की चेतावनी दी गई थी। पोस्टर में यह धमकी भी दी गई थी कि बालू उठाव बंद नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। घटना में मारे गए युवक रवि तांती के पिता विनोद तांती ने बताया कि रविवार रात करीब 11 बजे पांच नकाबपोश हथियारबंद उग्रवादियों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही सभी अंदर घुस गए और घरवालों की पिटाई करने लगे।

बुजुर्ग दंपती को घर से होटल बुला किया डिजिटल अरेस्ट, पांच दिन ठगते रहे पैसे

- साइबर ठगों ने वाट्सएप पर भेजा फर्जी वारंट, मनी लांड्रिंग का दिखाया था भय
- 1.78 करोड़ की ठगी के बाद सदमे में दंपती, अस्पताल में हो रहा इलाज

जागरण संवाददाता, सोनीपत

मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर बुजुर्ग दंपती को घर से होटल बुला साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 1.78 करोड़ रुपये ठग लिए। साइबर ठगों ने वाट्सएप पर नकली अरेस्ट वारंट भेजे, जिससे दोनों डर गए। पांच दिन तक वे साइबर ठगों के विभिन्न बैंक खातों में अपनी जमा पूंजी ट्रांसफर करते रहे। ठगों ने सुरक्षा का हवाला देकर उनको घर से होटल बुला लिया। दंपती दो दिन तक होटल में रहे। ठगों ने सात बार में सारे पैसे ट्रांसफर करा लिए। घटना के बाद पीड़ित दंपती सदमे में हैं।

गत छह नवंबर को माडल टाउन निवासी 75 वर्षीय विनोद चौधरी के मोबाइल पर काल आई। पहली बार फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद दोबारा काल आई। दूसरी तरफ से कहा गया कि आपका नाम अशोक गुप्ता मनी लांड्रिंग केस में दर्ज है। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। वाट्सएप पर एफआइआर की डिटेल्स और अरेस्ट वारंट की कापी भेजी गई। विनोद उस समय अपने किसी रिश्तेदार की मौत पर शोक जताने के लिए फरीदाबाद में थे। उन्होंने कहा कि वह 11 नवंबर को सोनीपत आएंगे। यह सुनकर साइबर ठगों ने फोन काट दिया। 12 नवंबर को दोबारा काल किया और उन्हें वाट्सएप पर अरेस्ट वारंट भेजे। फोन करने वाले ने धमकी भरे लहजे विनोद और स्वजन की बैंक डिटेल्स मांगी। इसके लिए एक दिन का समय दिया गया। 13 नवंबर को फिर फोन कर उनसे पूरे दिन की दिनचर्या का विवरण मांगा गया। उन्होंने सारी जानकारी लिखित में ठगों को भेज दी। 14 नवंबर को फिर फोन आया। सिक्योरिटी के नाम पर 43.50 लाख ट्रांसफर कराए गए। 15 नवंबर को ठगों का फोन नहीं आया। इस दिन पीड़ित अपने किसी करीबी को घटना के बारे में जानकारी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। दूसरा नंबर पत्नी के पास था, करीब पंद्रह वर्ष पहले शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुई थीं। पत्नी के नंबर पर 16 नवंबर के बाद वाट्सएप काल आने शुरू हो गए। जांच के नाम पर खाते में रुपये ट्रांसफर कराए गए। 17 व 18 नवंबर को सुरक्षा का हवाला देकर होटल में ठहरने को कहा।

****

नई दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस-वे का कार्य पूरा करने की तय तिथि बढ़ी

- सितंबर 2024 में पूरा होना था एक्सप्रेस वे का निर्माण, सितंबर 2025 में काम पूरा होने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, कठुआ

दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे का कार्य अब अगले वर्ष सितंबर माह तक पूरा हो पाएगा। भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद और इससे कार्य की गति मंद होने के कारण फिलहाल जम्मू-कश्मीर के हिस्से का 60 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है। ऐसे में इस कार्य को पूरा करने में अब एक साल की देरी हो गई है।

करीब 39 हजार करोड़ की लागत से बन रही 670 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद नई दिल्ली से कटड़ा मात्र छह घंटे में पहुंचा जा सकेगा और अमृतसर मात्र चार घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसका 150 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र हरियाणा में और 261 किलोमीटर क्षेत्र पंजाब से होकर गुजरता है। हरियाणा में 135 किलोमीटर हिस्से पर कार्य पूरा होने के बाद इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पंजाब में भी ज्यादातर निर्माण अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवाद में फंसा हुआ है। इस परियोजना का शिलान्यास 2022 में किया गया था और इसे सितंबर 2024 तक पूरा किया जाना था। अब इसकी नई डेडलाइन सितंबर-2025 तक कर दी गई है। नेशनल हाईवे अथारिटी, जम्मू के परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा का कठुआ से लेकर जम्मू तक तीन खंडों में कार्य अब तेजी से चल रहा है। 60 प्रतिशत कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सितंबर-2025 तक शेष बचा 40 प्रतिशत कार्य को पूरा हो जाएगा।

गाबा के बाद आप्टस में तोड़ा आस्ट्रेलिया का घमंड

पिछले दौरे में गाबा में पहली बार आस्ट्रेलिया को हराया, इस बार आप्टस में भारत ने दर्ज की पहली जीत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पर्थ के आप्टस स्टेडियम में भारत ने सेना देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया) में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर सोमवार को इतिहास रच दिया। भारत ने दूसरी पारी में 238 रन पर आस्ट्रेलिया को आलआउट कर 295 रनों से मैच अपने नाम कर लिया और बार्डर-गावस्कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पिछले दौरे में गाबा में पहली बार आस्ट्रेलिया को हराने वाली भारतीय टीम ने इस बार आप्टस में आस्ट्रेलिया को पहली हार के दर्शन करा दिए।

विशेष है यह जीत: गाबा 2021, पर्थ (वाका) 2008 और एडिलेड 2003...भारत ने अतीत में कुछ ऐतिहासिक जीत हासिल की हैं, लेकिन इस जीत को भी इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां न रोहित थे, न गिल, न जडेजा, न अश्विन और न शमी। दो युवा खिलाड़ियों का पदार्पण और टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली फार्म से बाहर थे। भारत के लिए इस मैच से पूर्व कुछ भी अच्छा नहीं था। यहां तक कि 12 वर्षों के बाद घर पर न्यूजीलैंड से 0-3 की हार से टीम का मनोबल भी बहुत नीचे थे, पर चार दिनों तक चले इस टेस्ट मैच में बुमराह की अगुआई वाली इस भारतीय टीम ने जो किया है इसे वर्षों तक याद रखा जाएगा।

पर्थ का किला भेदा: दो बार से बार्डर-गावस्कर ट्राफी में घर पर मिल रही हार के कारण ही आस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट के साथ भारत के स्वागत करने की तैयारी की थी, पर उन्हें क्या पता था कि अब तक आप्टस में अजेय रहे कंगारुओं का घमंड यहां टूट जाएगा। पर्थ, एक ऐसा स्थान है जो विश्व के सबसे तेज टेस्ट स्थलों में से एक है। 2018 में भारत ने सीरीज जीती जरूर थी, लेकिन वे यहां आप्टस में हार गए थे। बुमराह की अगुआई में टीम ने पिछले तीन दिनों में जैसा क्रिकेट यहां खेला भारतीय टीम एक बार फिर सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार बन गई है। हालांकि, आस्ट्रेलिया वापसी के लिए प्रसिद्ध है और यही कारण है कि एडिलेड में होने वाले दिन-रात्रि (गुलाबी गेंद) टेस्ट में वे वापसी के लिए पूरा जोर लगाएंगे।

लय में लौटे दिग्गज, युवाओं ने भी दिखाया दम: भारतीय टीम ने पर्थ में जिस तरह से आस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना वर्चस्व दिखाया, शायद ही विगत दो दशकों में किसी टीम ने कंगारुओं को उनके घर पर ऐसा झटका दिया है। भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और युवा यशस्वी जायसवाल ने जहां शतक जड़कर फार्म प्राप्त कर ली है, तेज गेंदबाज सिराज ने भी विकेट चटकाकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लिया है। हालांकि, सबसे अच्छी बात यह रही कि पदार्पण करने वाले दोनों युवा भारतीय हर्षित राणा और नीतीश ने भी बहुत प्रभावित किया।

डब्ल्यूटीसी तालिका में फिर शीर्ष पर पहुंचे: आस्ट्रेलिया को सोमवार को पर्थ में पहले टेस्ट में 295 रन से हराकर भारत फिर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका के शीर्ष पर पहुंच गया। भारत डब्ल्यूटीसी तालिका के शीर्ष पर अच्छी बढ़त बनाए हुए था लेकिन घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड के विरुद्ध 0-3 की करारी हार के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गया। न्यूजीलैंड के विरुद्ध हार से भारत की डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को भी झटका लग गया था। भारत के अब 15 मैच में नौ जीत, पांच हार और एक ड्रा से 110 अंक हो गए हैं जो 61.11 प्रतिशत अंक होते हैं। आस्ट्रेलिया 57.69 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके 13 मैच में आठ जीत, चार हार और एक ड्रा से 90 अंक हैं।

जीत के बाद जोश में भारतीय टीम के खिलाड़ी • एएनआइ

21वीं सदी में आस्ट्रेलिया को मिली सीरीज की पहली हार

विरुद्ध	स्थान	वर्ष
दक्षिण अफ्रीका	पर्थ (वाका)	2008
दक्षिण अफ्रीका	पर्थ (वाका)	2016
भारत	एडिलेड	2018
भारत	पर्थ (आप्टस)	2024

आस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत की सबसे बड़ी जीत (रन)

रन	स्थान	वर्ष
320	मोहाली	2008
295	पर्थ (आप्टस)	2024
222	मेलबर्न	1977
179	चेन्नई	1998
172	नागपुर	2008

एशिया से बाहर भारत की सबसे बड़ी जीत (रन)

रन	विरुद्ध	स्थान	वर्ष
318	वेस्टइंडीज	नार्थ साउंड	2019
295	आस्ट्रेलिया	पर्थ (आप्टस)	2024
279	इंग्लैंड	हेडिंग्ले	1986
272	न्यूजीलैंड	आकलैंड	1968
257	वेस्टइंडीज	किंग्सटन	2019

रोहित ने पर्थ में 'गुलाबी गेंद' से किया अभ्यास

पर्थ: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पितृत्व अवकाश के बाद पर्थ पहुंचने पर तुरंत नेट पर अभ्यास करने पहुंचे। कुछ दिन पहले अपने बेटे के जन्म के बाद रोहित रविवार शाम को पर्थ पहुंचे और वह भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत का गवाह बनने के लिए ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। उन्हें सोमवार को लंच सत्र के दौरान नेट में बल्लेबाजी करते देखा गया, जहां उन्होंने गुलाबी गेंद से रिजर्व तेज गेंदबाज नवदीप सैनी, यश दयाल और मुकेश कुमार का सामना किया। छह दिसंबर से शुरू हो रहा दूसरा टेस्ट दिन-रात्रि का होगा।

स्कोर बोर्ड

आस्ट्रेलिया दूसरी पारी: 238 (58.4 ओवर) (12/3 से आगे)

	रन	गेंद	4/6
ख्वाजा का. पंत बो. सिराज	4	13	0/0
स्मिथ का. पंत बो. सिराज	17	60	0/0
हेड का. पंत बो. बुमराह	89	101	8/0
मार्श बो. रेड्डी	47	67	3/2
कैरी बो. हर्षित	36	58	2/0
स्टार्क का. जुरेल बो. सुंदर	12	35	0/0
लियोन बो. सुंदर	0	2	0/0
हेजलवुड अविजित	4	10	1/0

अतिरिक्त: 24 (बा-5, लेबा-2, वा-6, नोबा-11)

विकेट पतन: 17-4 (ख्वाजा, 5.3), 79-5 (स्मिथ, 24.4), 161-6 (हेड, 38.5), 182-7 (मार्श, 43.4), 227-8 (स्टार्क, 53.4), 227-9 (लियोन, 53.6)

गेंदबाजी: बुमराह 12-1-42-3, सिराज 14-2-51-3, हर्षित 13.4-1-69-1, सुंदर 15-0-48-2, रेड्डी 4-0-21-1

असाधारण गेंदबाज हैं बुमराह

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: 12 कदम चलकर, फिर छोटा सा रन-अप और उछाल के साथ असाधारण एक्शन से गेंदबाजी कर पर्थ में कंगारुओं को गुमराह करने वाले भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट में अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर ऐतिहासिक जीत की कहानी लिख दी। पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले भारतीय कप्तान ने पर्थ में बल्लेबाजी के लिए आसान दिख रही दूसरी पारी में भी पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए भारत के लिए हर बड़े टूर्नामेंट में सिरदर्द बनने वाले ट्रेविस हेड का विकेट तब चटकाया जब वह सबसे खतरनाक दिख रहे थे और भारत को बार्डर-गावस्कर सीरीज के पहले ही मैच में बढ़त दिला दी।

मीडियाकर्मी ने बुमराह को उकसा दिया था: मैच से पूर्व आस्ट्रेलियाई मीडियाकर्मी के यह पूछने पर कि बतौर मध्यम गति के तेज गेंदबाज भारतीय टीम की कप्तानी के अवसर को कैसे देखते हैं, बुमराह को यह बात बहुत पसंद नहीं आई थी। जवाब में उन्होंने कहा था, 'भाई मैंने 150 की गति की भी गेंदें फेंकी हैं, मध्यम गति नहीं तेज गेंदबाज हूं।' मैच के दौरान अपनी असाधारण गेंदबाजी से बुमराह ने अपना जवाब दे दिया है। स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड जैसे मेजबान दिग्गजों का सीधे तौर पर पछाड़ने वाले बुमराह क्यों सभी प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं यह उन्होंने एक बार फिर दर्शा दिया।

पर्थ की पिच में अलग दिखे जसप्रीत: भारत की साधारण उछाल और सीम को अधिक मदद नहीं देने वाली पिचों पर कई पंजे खोलने वाले बुमराह के लिए पर्थ की हरी पिच उनकी गेंदबाजी पर चार चांद से कम नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बुमराह ने पहली बार आस्ट्रेलिया में असाधारण गेंदबाजी की है। आस्ट्रेलिया में उनके रिकार्ड पर गौर करें तो पता चलता है कि आठ मैचों की 16 पारियों में उनके नाम 40 विकेट हैं। शनिवार को पहली पारी में पूरा हुआ पंजा आस्ट्रेलिया में उनका दूसरा पंजा है। साथ ही अपने 20.06 की ओवरआल औसत से भी कम केवल 18.80 की औसत से बुमराह ने आस्ट्रेलिया में टेस्ट में गेंदबाजी की है।

हेड का विकेट लेने के बाद बुमराह • एएफपी

टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ औसत से गेंदबाजी (कम से कम 150 विकेट)

खिलाड़ी	मैच	विकेट	औसत
सिडनी बार्नेस	27	189	16.43
जसप्रीत बुमराह	41	181	20.06
एलन डेविडसन	44	186	20.53
माल्कम मार्शल	81	376	20.94
जोल गार्नर	58	259	20.97

पहली पारी में खोला था पंजा

2018 में आस्ट्रेलिया के अपने पहले दौरे पर एडिलेड में छह विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में अपने उसी प्रदर्शन की याद दिला दी। केवल 150 रनों की बढ़त की रक्षा करने उतरी टीम का मनोबल उन्होंने पहले ही दिन चार विकेट चटकाकर बढ़ा दिया था। इसमें उन्होंने पदार्पण कर रहे मैकस्वीनी, अनुभवी उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया था। पहले दिन का शानदार अंत करने के बाद दूसरे दिन की शुरुआत भी बुमराह ने उसी अंदाज में की। उन्होंने पहली ही गेंद पर एलेक्स कैरी को पंत के हाथों लपकवाकर पंजा पूरा किया था।

जस्सी जैसा कोई नहीं

140 से अधिक की गति से गेंद को एक ही लेंथ से अंदर और बाहर दोनों लाने की क्षमता बुमराह को विशेष बनाती है। टेस्ट में बुमराह की 20.17 की औसत उन्हें वेस्टइंडीज के दिग्गज मैल्कम मार्शल और जोल गार्नर से भी अधिक प्रभावशाली बनाती है। पहली पारी में कंगारुओं के लिए अबूझ बने रहे बुमराह ने रविवार को दूसरी पारी में भी मैकस्वीनी, लाबुशेन और हेड को अपना शिकार बनाया। हालांकि, सबसे यादगार विकेट ट्रेविस हेड का रहा, जो एक बार फिर खतरनाक दिख रहे थे।

टेस्ट में भारतीय कप्तान की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी

गेंदबाजी	खिलाड़ी	विरुद्ध	स्थान	वर्ष
10/135	कपिल देव	वेस्टइंडीज	अहमदाबाद	1983
10/194	बिशन सिंह बेदी	आस्ट्रेलिया	पर्थ	1977
9/70	बिशन सिंह बेदी	न्यूजीलैंड	चेन्नई	1976
8/72	जसप्रीत बुमराह	आस्ट्रेलिया	पर्थ	2024
8/109	कपिल देव	आस्ट्रेलिया	एडिलेड	1985

केवल सात रन पर ढेर हुई आइवरी कोस्ट

लागोस (नाइजीरिया), प्रेट्र: नाइजीरिया के खिलाफ आइसीसी टी-20 विश्व कप उपक्षेत्रीय अफ्रीका क्वालीफायर के ग्रुप सी मैच में आइवरी कोस्ट की टीम महज सात रन पर ढेर हो गई, जो इस प्रारूप में सबसे कम स्कोर है। नाइजीरिया के 271 रन के जवाब में आइवरी कोस्ट रविवार को खेले गए मुकाबले में केवल 7.3 ओवर ही खेल पाई है।

इससे पहले टी-20 का न्यूनतम स्कोर 10 रन था, जो दो टीमों के नाम था। दो महीने पहले मंगोलिया की टीम सिंगापुर के विरुद्ध 10 रन पर आउट हुई थी और उससे पहले पिछले साल आइल आफ मैन की टीम स्पेन के विरुद्ध इसी स्कोर पर आउट हुई थी। आइवरी कोस्ट के सात बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए।

विराट के अनुरोध पर अनुष्का गई थीं आस्ट्रेलिया : शास्त्री

नई दिल्ली, जेएनएन : भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने रविवार को टेस्ट में 30वां शतक जड़ने के बाद मैच देखने पहुंचीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस भेजा। विराट के बेहद करीबी माने जाने वाले भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने सोमवार को 'विरुष्का' के रिश्ते के बारे में एक मजेदार किस्सा साझा किया।

कमेंट्री के दौरान उन्होंने कहा, 'मुझे याद है जब मैं 2015 में कोच था। विराट अविवाहित थे और अनुष्का को डेट कर रहे थे। वह मेरे पास आए और कहा, 'यहां केवल पत्नियों को अनुमति है। क्या मुझे गर्लफ्रेंड को लाने की अनुमति मिल सकती है?' मैंने कहा जरूर। उन्होंने कहा, 'बोर्ड अनुमति नहीं दे रहा है।' तब मैंने काल कर अनुमति दिलाई। वह आईं। और पहले मैच में जो बाक्सिंग डे टेस्ट था, उन्होंने 160 रन बनाए। फिर विराट ने अनुष्का को बैट से फ्लाइंग किस भेजा।'

विश्व शतरंज चैंपियनशिप की पहली बाजी लिरेन के नाम

14 मैचों के मुकाबले में पिछड़े भारतीय चैलेंजर ग्रैंडमास्टर डी गुकेश, शुरुआत में आक्रमकता पड़ी भारी

मैच के दौरान डी गुकेश और डिंग लिरेन • एएफपी

सिंगापुर, प्रेट्र : भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश को बाजी को बीच में अनावश्यक ढंग से जटिल बनाना भारी पड़ा, जिससे चीन के मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में सोमवार को उन्हें हरा दिया। विश्व चैंपियन के सबसे युवा चैलेंजर 18 वर्ष के गुकेश ने शुरुआत में ही राजा के आगे वाले प्यादे को दो घर चलकर गलती कर दी। इस तरह की चाल आक्रामक तेवर जताती है और लिरेन ने इसका जवाब 'फ्रेंच डिफेंस' से दिया।

गुकेश ने वही रणनीति अपनाई जो विश्वनाथन आनंद ने 2001 में स्पेन के एलेक्सी शिरोव के विरुद्ध पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के समय अपनाई थी। गुकेश को 12वीं चाल तक आधे घंटे का फायदा था, लेकिन आठ चाल बाद लिरेन को अतिरक्त मिनट मिले जिससे साबित हो गया कि शुरुआत की अपनी दिक्कत से वह उबर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके काले मोहरों से खेलते हुए 42 चालों में जीत दर्ज की और 14 बाजियों के खेल में बढ़त बना ली। शुरुआत में पिछड़ने को लेकर गुकेश ने कहा, ये होता रहता है। यह बहुत लंबा मैच है और मेरे प्रतिद्वंद्वी की फार्म के बारे में, मुझे इससे अधिक कुछ भी उम्मीद नहीं थी। मुझे उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद थी और हमारे सामने एक लंबा मैच है, इसलिए अब यह और भी रोमांचक हो गया है। गुकेश विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए सबसे युवा चैलेंजर हैं। उनसे पहले विश्वनाथन आनंद विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने पांच बार यह खिताब जीता है।

भुवनेश्वर को 10.75 करोड़ रुपये में आरसीबी ने खरीदा, मुंबई ने चाहर को दिए नौ करोड़ से ज्यादा

दूसरे दिन रहा भारतीय तेज गेंदबाजों का जलवा

नई दिल्ली, जेएनएन : सऊदी अरब के जेद्दा में हुई आइपीएल की मेगा नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को भारतीय तेज गेंदबाजों का जलवा रहा। फ्रेंचाइजियों ने अपने देसी तेज गेंदबाजों पर बड़ा दांव खेला। करीब दो साल से भारतीय टीम से भुवनेश्वर कुमार दिन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। यूपी के इस तेज गेंदबाज के अनुभव पर रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 10.75 करोड़ रुपये खर्च किए तो दीपक चाहर को मुंबई इंडियंस ने नौ करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी। इतना ही नहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अपने दूसरे आरटीएम का प्रयोग करते हुए बंगाल के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को आठ करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। बंगाल के लिए खेलने वाले आकाश दीप को लखनऊ सुपर जायंट्स आठ करोड़ रुपये दिए। दूसरे दिन विदेशियों में मार्को जेनसेन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने।

13 साल के वैभव सूर्यवंशी भी बने करोड़पति

आइपीएल नीलामी में सबसे युवा खिलाड़ी 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रायल्स ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा। बिहार के समस्तीपुर के वैभव ने हाल ही में आस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के विरुद्ध अच्छा खेल दिखाया था। वैभव के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने भी बोली लगाई थी, लेकिन अंत में बाजी राजस्थान ने मारी।

दूसरे दिन सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी

खिलाड़ी	टीम	राशि (रुपये में)
मार्को जेनसेन	पंजाब किंग्स	7.00 करोड़
विल जैक्स	मुंबई इंडियंस	5.25 करोड़
गजनफर	मुंबई इंडियंस	4.80 करोड़

दूसरे दिन ये गेंदबाज रहे सबसे महंगे

खिलाड़ी	टीम	राशि (रुपये में)
भुवनेश्वर कुमार	आरसीबी	10.75 करोड़
दीपक चाहर	मुंबई इंडियंस	9.25 करोड़
मुकेश कुमार	दिल्ली कैपिटल्स	आठ करोड़
आकाश दीप	लखनऊ सुपर जायंट्स	आठ करोड़
तुषार देशपांडे	राजस्थान रायल्स	6.50 करोड़

चले गए चेन्नई के भरोसेमंद

चेन्नई ने दीपक चाहर को नौ सत्र तक अपने साथ रखा था और उन्हें पावरप्ले का गेंदबाज बनाया था, लेकिन इस बार मुंबई उन्हें छीन ले गई। इसी तरह पिछले तीन सत्रों में सीएसके के साथ अपनी किस्मत चमकाने वाले तुषार देशपांडे भी इस बार राजस्थान चले गए।

प्रियांश बने करोड़पति

दिल्ली प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले प्रियांश आर्य दूसरे दिन सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने। प्रियांश को पंजाब ने 3.80 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं रणजी मुकाबले में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले अंशुल कंबोज को चेन्नई ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा।

इन बड़े नामों को नहीं मिला खरीदार

मुस्तफिजुर रहमान, बेन डकेट, फिन एलेन, आदिल रशीद, शार्दुल ठाकुर, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, उमेश यादव, नवीन उल हक, पृथ्वी शा, सरफराज खान, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, अल्जारी जोसेफ, काइल मेयर्स, मयंक अग्रवाल, सिकंदर रजा, केशव महाराज।

कभी 18 करोड़ पाने वाले कुर्रन को 2.40 करोड़

इंग्लैंड के आलराउंडर सैम कुर्रन 2023 में 18.50 करोड़ रुपये में तब के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे सैम कुर्रन को इस बार केवल 2.40 करोड़ रुपये में चेन्नई सुपरकिंग्स ने खरीदा।

कैसे होता है आइपीएल सैलरी का भुगतान?

आइपीएल नीलामी में खिलाड़ी जिस राशि में खरीदा जाता है वही उसकी सैलरी होती है। इस सैलरी से उचित टैक्स भी काटा जाता है। नीलामी में मिली राशि एक सत्र के लिए होती है। यदि खिलाड़ी पूरे तीन साल का अनुबंध पूरा करता है तो उसे हर सत्र में वही राशि मिलती है। खिलाड़ी टूर्नामेंट शुरू होने के पहले चोटिल हो गया तो फ्रेंचाइजी को उसे कोई राशि नहीं देनी होगी। हालांकि, यदि खिलाड़ी टूर्नामेंट के बीच में चोटिल हुआ तो उसे खरीदे गए रकम के 10 प्रतिशत के साथ ही प्रति मैच के हिसाब से भुगतान किया जाता है। टीमें अपनी सुविधा के हिसाब से भुगतान करती हैं जिसमें एक ही बार में पूरे भुगतान से लेकर तीन हिस्सों में भुगतान तक शामिल है। खिलाड़ी अपनी स्वेच्छा से अनुबंध तोड़ सकता है, लेकिन यदि टीम ने समय से पहले अनुबंध तोड़ा तो उसे खिलाड़ी को पूरे अनुबंध का पैसा देना होगा।

इस सत्र से खिलाड़ियों को मिलेगी मैचफीस

आइपीएल में अब तक खिलाड़ियों को नीलामी में मिली रकम के अलावा कोई मैचफीस नहीं मिलती थी, लेकिन इस सत्र से सभी को 7.5 लाख रुपये प्रति मैच फीस के रूप में मिलेंगे। प्लेइंग इलेवन के साथ इम्पैक्ट खिलाड़ी को भी ये फीस मिलेगी। यदि किसी खिलाड़ी ने सभी लीग मैच खेले तो 1.05 करोड़ रुपये उन्हें मैचफीस के रूप में मिलेंगे जो नीलामी में मिली राशि से अलग होगी।

पंजाब किंग्स
रिटेन: शशांक (5.5 करोड़), प्रभसिमरन सिंह (चार करोड़), खरीदे: श्रेयस (26.75 करोड़), चहल (18 करोड़), स्टोइनिस (11 करोड़), मैक्सवेल (4.20 करोड़), नेहाल (4.20 करोड़), हरप्रीत बरार (1.50 करोड़), विष्णु विनोद (95 लाख), यश ठाकुर (1.60 करोड़), विशाख (1.80 करोड़), जेनसेन (7 करोड़), इंग्लिश (2.60 करोड़), फर्ग्यूसन (2 करोड़), ओमारजई (2.40 करोड़), हरनूर (30 लाख), कुलदीप (80 लाख), प्रियांश (3.80 करोड़), हार्डी (1.25 करोड़), मुशीर (30 लाख), सूर्यांश (30 लाख), अविनाश (30 लाख), प्रवीण दुबे (30 लाख) आरटीएम : अर्शदीप (18 करोड़)

रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रिटेन: विराट (21 करोड़), पाटीदार (11 करोड़), यश (5 करोड़) खरीदे : साल्ट (11.50 करोड़) जितेश (11 करोड़), लिविंगस्टोन (8.75 करोड़), हेजलवुड (12.5 करोड़), रसिख (6 करोड़), सुयश (2.60 करोड़), कुणाल (5.75 करोड़), भुवनेश्वर (10.75), डेविड (3 करोड़), शेफर्ड (1.50 करोड़), नुवान तुषारा (1.60 करोड़), पड्डिकल (2 करोड़), चिकारा (30 लाख), लुंगी नगीदी (1 करोड़), अभिनंदन (30 लाख), मोहित राठी (30 लाख), आरटीएम: स्वप्निल सिंह (50 लाख)

लखनऊ सुपर जायंट्स
रिटेन: पूरन (21 करोड़), बिश्नोई (11 करोड़), मयंक (11 करोड़), मोहसिन (चार करोड़), बडोनी (चार करोड़), खरीदे: पंत (27 करोड़), मिलर (7.50 करोड़), मार्करम (दो करोड़), मार्श (3.40 करोड़), आवेश (9.75 करोड़), समद (4.20 करोड़), जुयाल (30 लाख), आकाश दीप (8 करोड़), हिम्मत (30 लाख), एम सिद्धार्थ (75 लाख), शाहबाज (2.40 करोड़), आकाश (30 लाख), युवराज (30 लाख), हंगरगेकर (30 लाख), मैथ्यू ब्रेट्जकी (75 लाख) आरटीएम: जोसेफ (75 लाख)

चेन्नई सुपर किंग्स
रिटेन: रुतुराज (18 करोड़), धौनी (4 करोड़), शिवम (12 करोड़), पथिराना (13 करोड़), जडेजा (18 करोड़), खरीदे: कान्वे (6.25 करोड़), नूर अहमद (10 करोड़), खलील (4.80 करोड़), राहुल त्रिपाठी (3.40 करोड़), विजय शंकर (1.20 करोड़), सैम कुर्रन (2.4 करोड़), शेख रशीद (30 लाख), अंशुल कंबोज (3.4 करोड़), मुकेश (30 लाख), दीपक हुड्डा (1.70 करोड़), गुरजपनीत (2.20 करोड़), एलिस (1.25 करोड़), ओवर्टन (1.50 करोड़), नागरकोटी (30 लाख), श्रेयस गोपाल (30 लाख), वंश (55 लाख), आरटीएम: रचिन रवींद्र (चार करोड़)

कोलकाता नाइटराइडर्स
रिटेन: रिंकू (13 करोड़), चक्रवर्ती (12 करोड़), नारायण (12 करोड़), रसेल (12 करोड़), हर्षित राणा (4 करोड़), रमनदीप ह (4 करोड़), खरीदे: वेंकटेश (23.75 करोड़), डि काक (3.60 करोड़), गुरबाज (दो करोड़), एनरिक नोर्त्जे (6.50 करोड़), अंगकृष रघुवंशी (तीन करोड़), वैभव अरोड़ा (1.80 करोड़), मयंक मार्कंडेय (30 लाख), रोवमैन पावेल (1.5 करोड़), मनीष पांडेय (75 लाख), स्पेंसर जानसन (2.80 करोड़), अजिंक्य रहाणे (1.5 करोड़), अनुकूल राय (40 लाख), मोइन अली (2 करोड़), उमरान मलिक (75 लाख)

मुंबई इंडियंस
रिटेन: बुमराह (18 करोड़), सूर्य (16.35 करोड़), हार्दिक (16.35 करोड़), रोहित (16.30 करोड़), तिलक (आठ करोड़), खरीदे: बोल्ट (12.50 करोड़), मिंज (65 लाख), कर्ण शर्मा (50 लाख), रिकेल्टन (1 करोड़), दीपक चाहर (9.25 करोड़), गजनफार (4.80 करोड़), विल जैक्स (5.25 करोड़), राजू (30 लाख), जैकब्स (30 लाख), अर्जुन तेंदुलकर (30 लाख), लिजाड (75 लाख), विग्नेश पुटुर (30 लाख) आरटीएम : नमन धीर (5.25 करोड़)

राजस्थान रायल्स
रिटेन: सैमसन (18 करोड़), यशस्वी (18 करोड़), रियान (14 करोड़), जुरैल (14 करोड़), हेटमायर (11 करोड़), संदीप (चार करोड़), खरीदे: आर्चर (12.50 करोड़), हसरंगा (5.25 करोड़), तीक्ष्णा (4.40 करोड़), मधवाल (1.20 करोड़), कार्तिकेय (30 लाख), नितीश राणा (4.20 करोड़), तुषार (6.50 करोड़), शुभम (80 लाख), फजलहक (2 करोड़), वैभव (1.10 करोड़), मफाका (1.50 करोड़)

सनराइजर्स हैदराबाद
रिटेन: क्लासेन (23 करोड़), कमिंस (18 करोड़), अभिषेक (14 करोड़), ट्रेविस हेड (14 करोड़), नीतीश रेड्डी (6 करोड़), खरीदे: इशान (11.25 करोड़), शमी (10 करोड़), हर्षल (8 करोड़), राहुल चहर (3.20 करोड़), जांपा (2.40 करोड़), अथर्व ताइडे (30 लाख), अभिनव मनोहर (3.20 करोड़), सिमरजीत (1.50 करोड़), जीशान अंसारी (40 लाख), उनादकट (1 करोड़), ब्रायडन कार्स (1 करोड़), कमिंडु मेंडिस (75 लाख), अनिकेत वर्मा (30 लाख), इशान मलिंगा (1.20 करोड़), लवनीथ सिसोदिया (30 लाख), सचिन बेबी (30 लाख)

दिल्ली कैपिटल्स
रिटेन: अक्षर (16.5 करोड़), कुलदीप (13.25 करोड़), स्टब्स (10 करोड़), पोरेल (चार करोड़), खरीदे: केएल राहुल (14 करोड़), स्टार्क (11.75 करोड़), हैरी ब्रूक (6.25 करोड़), नटराजन (10.75 करोड़), नायर (50 लाख), रिजवी (95 लाख), आशुतोष (3.80 करोड़), मोहित (2.20 करोड़), प्लेसिस (2 करोड़), नालकंडे (30 लाख), विप्रज निगम (50 लाख), दुश्मंता (75 लाख), फरेरा (75 लाख), अजय मंडल (30 लाख), मनवंथ कुमार (30 लाख), त्रिपुराना विजय (30 लाख), माधव तिवारी (40 लाख), आरटीएम: मैकगर्क (9 करोड़), मुकेश कुमार (8 करोड़)

गुजरात टाइटंस
रिटेन: राशिद (18 करोड़), गिल (16.50 करोड़), साई सुदर्शन (8.5 करोड़), राहुल तेवतिया (चार करोड़), शाहरुख खान (चार करोड़), खरीदे: जोस बटलर (15.75 करोड़), मोहम्मद सिराज (12.25 करोड़), कैगिसो रबाडा (10.75 करोड़), प्रसिद्ध कृष्णा (9.50 करोड़), महिपाल लोमरोर (1.70 करोड़) कुमार कुशाग्र (65 लाख), अनुज रावत (30 लाख), निशांत सिद्धू (30 लाख), मानव सुतार (30 लाख), वाशिंगटन सुंदर (3.20 करोड़), गेराल्ड कोएत्जे (2.40 करोड़), अरशद खान (1.30 करोड़), गुरनूर बराड़ (1.30 करोड़), शेरफेन रदरफोर्ड (2.60 करोड़), इशांत शर्मा (75 लाख), जयंत यादव (75 लाख), ग्लेन फिलिप्स (2 करोड़), करीम जनत (75 लाख), कुलवंत खेजरोलिया (30 लाख), आरटीएम: साई किशोर (2 करोड़)

नोट: राशि रुपये में

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
अंतस और अध्यात्म का
मंगलवार, 26 नवंबर, 2024

चिंतन धरोहर

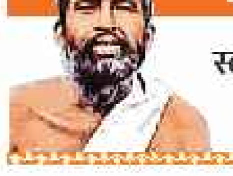

स्वामी रामकृष्ण परमहंस

अहंकार की छाया अनिष्टकारी नहीं

क्या अहं कभी पूरी तरह नहीं जाएगा? कमल की पंखुड़ियां समय पर झड़ जाती हैं, लेकिन उनका निशान रह जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसका अहंकार पूरी तरह चला जाता है, लेकिन उसका थोड़ा-सा चिह्न रह जाता है, किंतु उस अहंकार से कोई अनिष्ट नहीं होता। वह छाया मात्र है। जिसने ईश्वर के दर्शन किए हैं, वही ठीक-ठीक जानी है। उसका स्वभाव बालक जैसा हो जाता है। बालक का भी अलग व्यक्तित्व होता है। अलग अस्मिता होती है, परंतु वस्तुतः वह केवल आकारमात्र है। बालकों का अहं बड़ों के अहं की तरह हानिकारक नहीं होता।

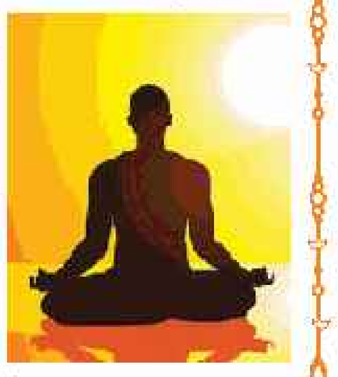

कुछ महापुरुष सप्तम भूमि या समाधि की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर भगवद्बोध में विलीन हो जाने के बाद भी लोककल्याण के लिए उस भूमि पर उतर आते हैं। समाधि के बाद भी वे इच्छापूर्वक विद्या का अहं रख लेते हैं। वह अहं का आभास मात्र है, जो पानी पर खींची गई रेखा के समान होता है। रस्सी जल जाने के बाद भी उसका आकार बना रहता है, पर उसके द्वारा किसी को बांधा नहीं जा सकता। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि में दग्ध होकर अहं का भी केवल आकार भर रह जाता है।

मनुष्य सपने में बाघ देखकर कि कोई उसे मारने आ रहा है, मारे डर के हड़बड़ाकर उठ बैठता है। यद्यपि वह उठकर देखता है कि कमरा बंद है और अंदर कोई नहीं है, फिर भी कुछ समय तक उसका हृदय धड़कता रहता है। इसी भांति अभिमान के चले जाने के बाद उसका कोई जोर नहीं रह जाता। वह आभास मात्र है।

समाधि के बाद भी 'मैं' (अहं) रह जाता है - जैसे 'दास का मैं', 'भक्त का मैं'। शंकराचार्य ने लोकशिक्षा के लिए 'विद्या का मैं' रख छोड़ा था। नारदादि को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ था, किंतु फिर भी वे कलकलनादिनी निर्झरिणी की तरह भगवन्महिमा का गुणगान करते हुए विचरण करते रहते थे। लोकशिक्षा और धर्मरक्षा के लिए उन्होंने 'विद्या का मैं' रख छोड़ा था। ब्रह्म में पूर्ण विलीन न होकर अपने अलग अस्तित्व का मानो थोड़ा-सा चिह्न रख छोड़ा था।

हनुमान जी को ईश्वर के साकार और निराकार दोनों ही स्वरूपों के दर्शन हुए थे, किंतु इन दर्शनों के बाद भी उन्होंने दास 'मैं' को रख छोड़ा था। नारद, सनक, सनंदन, सनातन और सनतकुमार आदि ने भी इसी तरह ब्रह्मदर्शन के बाद भी 'दास मैं', 'भक्त मैं' रख छोड़ा था। मुझमें भी थोड़ा 'मैं' बचा है, लेकिन उसे बनाए रखने वाला मैं नहीं, बल्कि जगदंबा हैं।

सप्ताह के व्रत त्योहार

26 नवंबर, मंगलवार : उत्पन्ना एकादशी व्रत।
28 नवंबर, गुरुवार : प्रदोष व्रत।
एक दिसंबर, रविवार : स्नान-दानादि की अमावस्या।

जीवन दर्शन

ब्रह्माकुमारी शिवानी
प्रेरक वक्ता

स्वयं को करें स्वीकार

जो जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकार करना सफल जीवन का मंत्र है, लेकिन हम यह क्यों भूल जाते हैं कि सब में हम स्वयं भी आते हैं। अतः सर्वप्रथम स्वयं को स्वीकार कीजिए...

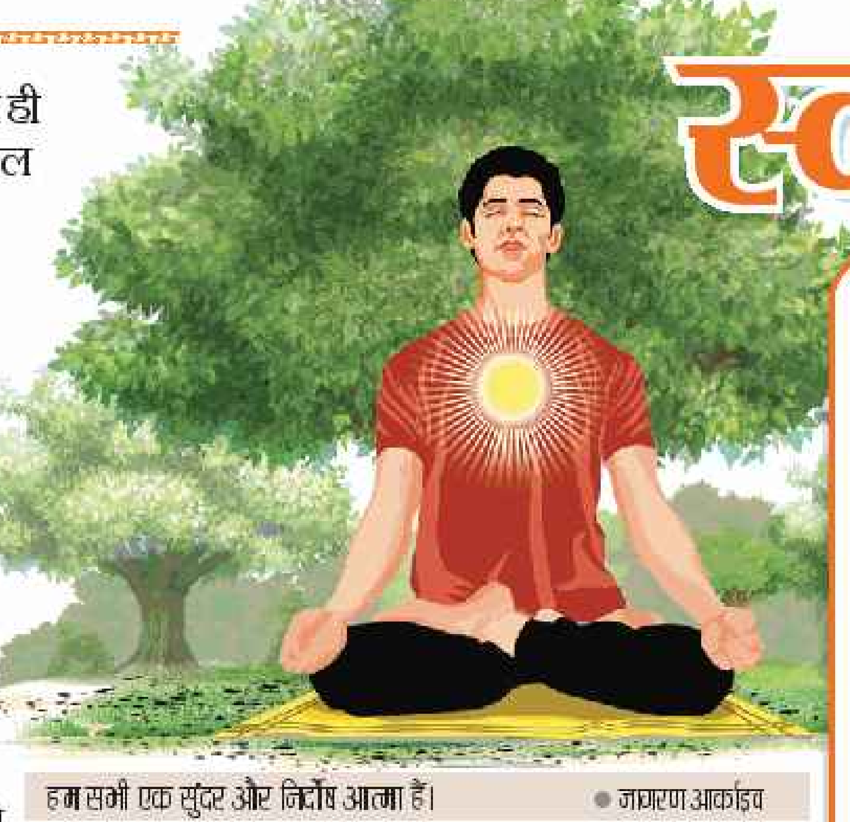

हम सभी एक सुंदर और निर्दोष आत्मा हैं। ● जागरण आर्काइव

मन की शांति, संबंधों में मधुरता तथा जीवन में आनंद के लिए, स्वयं को व अन्य लोगों को स्वीकार करना न सिर्फ एक गुण है, बल्कि कला व आपकी शक्ति है। जो जैसा है, उसे उसी रूप में अपनाने व स्वीकारने में ही बुद्धिमत्ता है। दूसरे लोगों, बाहरी बातों व परिस्थितियों को समझने व स्वीकारने से पहले स्वयं आप जैसे हैं, उसी स्वरूप में देख पाना व स्वयं को स्वीकार कर लेना ही सुखमय जीवन का आधार है। क्योंकि हम स्वयं को सही रूप में देख ही नहीं पाते। हम अपनी कमियों व विशेषताओं को स्वीकार ही नहीं करते। जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो न तो स्वयं को बदल पाएंगे, न दूसरों को। जब हम खुद को स्वीकार कर नहीं पाते तो स्वयं से ही असहमत होते हैं, इससे हमारा आत्मसम्मान नकारात्मक हो जाता है।

कई बार हम स्वयं को कमतर मानने लगते हैं। हीनताबोध से हमारी अपनी ऊर्जा कम होती है, वहीं जब हम स्वयं को अपनी कल्पना में अधिक मानने लगते हैं, तब भी समस्याएं खड़ी होती हैं। अतः सर्वप्रथम हम स्वयं जैसे हैं, उसे जानकर स्वीकार करें, तो हम सफल जीवन जी सकते हैं। अध्यात्म कहता है कि हम सभी एक सुंदर और निर्दोष आत्मा हैं। स्वयं को कमतर मानने से जब कोई आपसे मिलता है, तब आप सावधान होकर उससे बात करते हैं। आपके भीतर से हीनभावना प्रदर्शित हो ही जाती है। किसी भी व्यक्ति का संस्कार इस आधार पर तय होता है कि वह बार-बार क्या दोहराता है।

अगर कोई व्यक्ति अपने परिवारवालों की डांट-फटकार का कारण स्वयं को मानता है, स्वयं को दोषी स्वीकार करता है और आत्मग्लानि में डूबा रहता है, तो इसमें अधिकतर उसकी बचपन से आत्म-आलोचना करने की आदत ही सामने आती है।

बचपन में हम सबकी विचार प्रक्रिया परिपक्व नहीं होती है। सत और असत के बीच अंतर कैसे करना है, बचपन में हमें पता नहीं होता है। तब हम अपने लिए उन छवियों को ही स्वीकार कर लेते हैं, जो हमारे माता-पिता या बड़े लोगों ने तय की थीं। जब भी कोई माता-पिता अपने बच्चे के लिए कुछ कहते हैं, तो बच्चा उसको अपना परिचय मान लेता है। क्योंकि बच्चों के लिए उनके माता-पिता हमेशा सही होते हैं। इसलिए माता-पिता का यह दायित्व है कि बच्चों के सम्मुख हीनता का व्यवहार प्रदर्शित न करें। बच्चों को यह मत जताएं कि तुम कुछ नहीं कर सकते।

अगर किसी बच्चे को माता-पिता से अपने बारे में कोई नकारात्मक संदेश मिलता है, तो वह इसे सच मान लेता है और उसी नकारात्मक संदेश पर अपनी छवि बना लेता है। भले ही आगे चलकर उसे उसकी सकारात्मक छवि दी जाए, तब भी उस पर अधिक प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी कमियों को अपना मान लिया है। हालांकि, यह सच है कि कोई भी इंसान पीड़ित अवस्था में ही सारा जीवन नहीं बिता सकता। और, यह भी सच है कि हम अतीत की मनोस्थिति को अधिक बदल नहीं सकते।

जीने की एक ढंग यह हो सकता है कि हम स्वयं को बीते हुए समय की अवस्था में ही रहने दें, हम आत्म-आलोचक बने रहें। देखने में आता है, बहुत से बच्चे अपनी कमियों के लिए माता-पिता को दोषी ठहराते हैं। लेकिन, दूसरों को दोष देने से हमारी अपनी ऊर्जा कम होती है। हमें यह समझना होगा कि अतीत हमारे हाथों में नहीं है, पर उसके समाधान के बारे में विचार करने का समय हमारे पास अभी है। यह अब और भी महत्वपूर्ण है कि हम जो कर सकते हैं वह करें और अपने भीतर सुधार लाएं। अगर हम इस तरह दूसरों को दोष देते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा समाप्त होती जाएगी। पहले दूसरे हमारी हानि के दोषी थे, अब हम स्वयं अपनी स्थिति बिगाड़ने की दोषी होंगे।

दूसरों को कहने से पहले, हमें स्वयं को इस बात से प्रोत्साहित करना चाहिए कि सब कुछ भलाई के लिए होता है और हर बात में कल्याण है। जब तक हम अपने साथ अच्छी बात नहीं करते हैं, हमारे लिए दूसरों के सोच को बदलना संभव नहीं होगा। अगर हम स्वयं पर काम किए बिना दूसरों के सोच बदलने लगते हैं, तो उन पर कोई असर नहीं होगा। अगर हम विचार के स्तर पर, भीतर ही भीतर बहुत आलोचक हो गए हैं, तो हमें इस संस्कार को बदलना होगा। इसके लिए हमें कुछ मंत्रों का पालन करना होगा। पहले तो हमें दूसरों को दोष देने का खेल बंद करना होगा। हमें याद रखना है कि हमारी प्रतिक्रिया हमारी रचना है। दूसरा मंत्र है, हमें अपनी निंदा करना बंद करना होगा। अगर हमने कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं है, तो बेहतर होगा कि हम उसे स्वीकार कर लें और अपनी निंदा करने के बजाय इसे भविष्य में अलग तरीके से करें। दृढ़ संकल्प से प्रतिदिन कुछ सकारात्मक चिंतन करें।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

प्रतिदिन के शुभ संकल्प

आज से ही अपनी व दूसरों की आलोचना बंद करें और इस प्रकार शुभ संकल्प करें :

- मुझे स्वयं को देखना है। मूल रूप में मैं एक सुंदर और निर्दोष आत्मा हूं।
- अतीत के अनुभवों पर मैंने जो अपनी छवि बनाई थी, उसे अभी तक अपना सच मान रहा था। आज से मैं बदल रहा हूं। अब मुझे स्वयं को अनासक्त रूप में देखना होगा।
- मैं प्रशंसा व प्रोत्साहन के रंगों का प्रयोग कर अपनी छवि बनाऊंगा। जो भी विचार पैदा करूंगा, वे स्वीकार व प्रशंसा से भरे होंगे।
- मेरे भीतर बहुत से गुण हैं। मैं स्वयं के लिए सहजता का मार्ग चुनता हूं।
- मैं अपने आप से ध्यानपूर्वक बात करता हूं। केवल शुद्ध, सकारात्मक व शक्तिशाली शब्दों को चुनता हूं।
- मैं स्वयं से प्रेम करता हूं और जीवन में सबके प्रति आत्मिक स्नेह, प्रेम व कल्याण की कामना करता हूं।

गीता सार

आचार्य शिवेंद्र नागर
श्रीमद्भगवद्गीता मर्मज्ञ

**कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्।
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिकरमर्जुन।।**

अध्याय 2, श्लोक : 2

अर्थ : भगवान श्रीकृष्ण बोले – हे अर्जुन, कहां इस विषम स्थिति में तू कार्यरता को प्राप्त हुआ है, जो आर्यों को न शोभा, न स्वर्ग और नही कीर्ति देने वाली है।

व्याख्या : पहले अध्याय में चुप रहकर अर्जुन को सुनने के बाद दूसरे अध्याय में भगवान अपनी वाणी प्रारंभ करते हैं। युद्ध क्षेत्र में मोहाविष्ट अर्जुन के भीतर के संशय देखकर भगवान कहते हैं कि कहां से तू इस विषम स्थिति में कायरता को प्राप्त हुआ है। अर्थात अर्जुन की कायरता बाहर से नहीं आई है, भीतर से आई है। ऐसे कठिन समय और परिस्थिति में जब 18 अक्षौहिणी सेना बिगुल बजा चुकी है, ऐसे समय में तू गांडीव छोड़कर रणभूमि में बैठ गया है। भगवान कृष्ण अपनी वाणी से अर्जुन को झकझोरते हैं। वे मात्र अर्जुन को नहीं चेताते, इसमें हमारे लिए भी संदेश है। क्योंकि हम सभी इस संसार के प्रति मोहाविष्ट हैं। भगवान आम जनमानस को भी यह सोचने को विवश कर रहे हैं कि जिस सांसारिक मोह जाल में हम फंसे हुए हैं, वह न तो हमें अभी अर्थात वर्तमान में सुख देगा न भविष्य में। अर्जुन को तो भगवान लक्ष्य तक पहुंचा ही देंगे, लेकिन आम जनमानस का क्या होगा। हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है खाना, पीना, मौज-मस्ती इत्यादि। यदि आप जीवन में लक्ष्मी चाहते हैं तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। यदि यह लक्ष्य नारायण से जुड़ने का बन जाए तो लक्ष्मी आपके पांव दबाएंगी। इसलिए अपने आलस्य रूपी उल्लू को वश में करके अध्यात्म के लक्ष्य पर आगे बढ़ें, जहां जीवन की संपूर्णता प्राप्त होगी। तब अर्जुन की तरह आपकी गति नहीं होगी।

लोककल्याण के लिए हुआ एकादशी का प्रादुर्भाव

सनातन धारा

डा. चिन्मय पण्ड्या
प्रति कुलपति, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी (आज) को उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने इसी दिन मुर नामक दैत्य का वध करने के लिए एकादशी को उत्पन्न किया था...

हिंदू पर्व-त्योहारों में एकादशी तिथि का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे तो यह प्रत्येक हिंदी माह के कृष्ण व शुक्ल पक्ष में एक-एक बार आती है। एकादशी को हरिदिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को स्त्री-पुरुष सभी करते हैं। एकादशी व्रत की एक मान्यता यह भी है कि व्रत करने वाले उपासक के पितरों को आत्मसंतुष्टि मिलती है और वे अपनी अगली पीढ़ी पर कृपा बरसाते हैं।

हिंदू कैलेंडर में मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाई जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार, देवताओं और ऋषियों को मुर नामक एक महादैत्य अत्यधिक कष्ट पहुंचाया करता था। देवताओं और ऋषियों की तप साधना में विघ्न डाला करता था। उसकी क्रूरता से व्यथित होकर देवताओं [illegible]

एकादशी का नियमित रूप से व्रत-अनुष्ठान करने से साधक, उपासक के जीवन में कई महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आते हैं। व्रत करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और कई प्रकार के आंतरिक विषैले तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे आंतरिक अंगों को ऊर्जा प्राप्त होती है।

भगवान विष्णु की उपासना करने से आत्मा को शांति मिलती है और मनुष्य का आंतरिक शुद्धीकरण होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत न [illegible] आध्यात्मिक उन्नति करता है, वरन यह [illegible] के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी [illegible] करता है। मानसिक स्थिरता और संकल्प [illegible] में वृद्धि करता है।

[illegible] एकादशी द्वारा वध किए गए मुर जैसे [illegible] आज हमारे भीतर भी हैं, जिनमें हमारा [illegible] अहंकार, मत्सर आदि अनेक प्रवृत्तियां [illegible]लित हैं। भगवान विष्णु की भांति हमें भी [illegible] भीतर इस एकादशी को जाग्रत करना [illegible] ताकि इन प्रवृत्तियों का समूल नाश हो [illegible]और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो [illegible] हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो [illegible] जिससे हम नवसृजन के [illegible]र अग्रसर हो सकें, तभी [illegible] एकादशी व्रत करना [illegible] हो पाएगा।

प्रेरक प्रसंग

ईश्वर को पहचानें

एक गांव में एक व्यक्ति था, जो मानता था कि उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ईश्वर करेंगे। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी ही पानी। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। कई लोग ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। लोगों ने देखा कि वह व्यक्ति भगवान के ध्यान में बैठा हुआ है। सभी ने उसे समझाया कि वह अपनी जगह छोड़ दे और भाग चले, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे।

धीरे-धीरे पानी बढ़ता गया, उस व्यक्ति की कमर तक पहुंच गया। इतने में ही उसके पास से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने उससे कहा, आप इस नाव पर आ जाएं, मैं किसी सुरक्षित स्थान पर आपको पहचान दूंगा, लेकिन उसने फिर वही उत्तर दिया कि मुझे भगवान बचाएगा। कुछ देर बाद पानी और अधिक बढ़ गया। वह व्यक्ति वहीं बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। इतने में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक हेलिकाप्टर मदद के लिए आया है। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और उससे पकड़ने को कहा, मगर वह टस से मस न हुआ। उसने कहा कि मुझे तो भगवान बचाएगा। मैं इसे नहीं पकड़ूंगा।

कुछ ही देर में बाढ़ की धारा में वह व्यक्ति डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब वह व्यक्ति स्वर्ग पहुंचा तो उसने भगवान से पूछा कि मैंने आपकी आराधना इतने मन से की, लेकिन फिर भी मैं डूबकर मरा। मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा, 'मैं तो तीन बार तुम्हारी मदद करने आया था। एक बार ग्रामीणों के रूप में, एक बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए।'

अगले अंक में पढ़ें श्री श्री रविशंकर का चिंतन

आज का भविष्यफल- 26 नवंबर, 2024 मंगलवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी।
आज का राहुकाल : अपराह्न 03 बजे से 04 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल : उत्तर।
आज का पर्व एवं त्योहार : उत्पन्ना एकादशी।
विशेष : बुधवक्री।

कल 27 नवंबर, 2024 का पंचांग

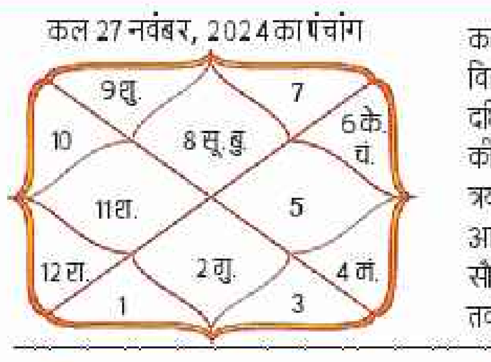

कल का दिशाशूल : उत्तर
विक्रम संवत 2081 शके 1946 दक्षिणायण, दक्षिणगोल, हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास कृष्णपक्ष की द्वादशी, 30 घंटे 25 मिनट तक, तत्पश्चात त्रयोदशी, चित्रा नक्षत्र 30 घंटे 27 मिनट तक, आयुष्मान योग 15 घंटे 13 मिनट तक, तत्पश्चात सौभाग्य योग, कन्या में चंद्रमा, 18 घंटे 07 मिनट तक, तत्पश्चात तुला में।

मेष : मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।
वृष : रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
मिथुन : संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। सृजन, शोध व रचनात्मक दिशा में किया गया प्रयास सार्थक होगा।
कर्क : निजी सुख में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा।
सिंह : अधीनस्थ कर्मचारी या रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा। संपत्ति के मामलों में विवाद की स्थिति कष्टदायी होगी।
कन्या : आर्थिक मामलों में सुधार होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी।
तुला : रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी।
वृश्चिक : कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपके हित में न हो। व्यावसायिक मामलों में जोखिम न उठाएं।
धनु : नेत्र या उदर विकार की संभावना है, जबकि संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
मकर : आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।
कुंभ : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाई या बहन से तनाव मिल सकता है।
मीन : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

वर्ग पहेली- 2819

बाएं से दाएं
1 आश्चर्य, चकित होना (4)।
4 गतिहीन, निर्जीव (3)।
7 स्वाद लेना, अनुभूति लेना (3)।
8 माता के पिता, अनेक (2)।
9 बड़ी लड़ाई, युद्ध, संग्राम (5)।
11 काव्यशास्त्र के अनुसार नौ रसों का समाहार (4)। 13 विष, जहर (4)। 15 श्रेष्टतम (5)।
17 विचार, नहीं (2)।
18 खनिज पदार्थों की प्राप्ति के लिए की गई खुदाई (3)।
20 इच्छा, चाह, स्वप्न (3)।
21 प्राणयुक्त, सजीवता (4)।

ऊपर से नीचे
2 चमड़ा, खाल (2)।
3 पानी में निवास करने वाला जीव (4)। 4 अपनत्व (5)।
5 मुगलकालीन रनिवास, अंत:पुर (3)।
6 एकाएक, अचानक (4)।
10 भीड़, समाहार, समुदाय (3)।
12 मुख, मुंह (3)।
13 दाढ़ी और बाल बनाने काम (4)।
14 डिगना, डगमगाना (5)।
15 अपने मन की करने वाला, दूसरे की परवाह नहीं करने वाला (4)।
16 सुगंध, नमक (3)।
19 मनोयोग से लगा हुआ, मग्न (2)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

च	तु	र		ह	मे	शा			म
	त		त	ब		ल	ज	वा	ना
	ला			क		भं			ही
प	ना	ह	दे	ना		जि		ता	
ट						क	था	न	क
नी	नी	वि	धं						प
	भ		मा		धं	ब	रा	ह	ट
मं			व		ना			थ	
शा	ली	न	ता		धं	ट		ना	
ल			र	ह	न		बा	ल	क

जागरण सुडोकू- 2819

4		6		3		8		1
		2			1		5	
7				4				
6			5			7	1	
		9			8			
5				9		3		2
9	6		8				4	
		7		6		5		8
	4		3		7		2	

कल का हल

3	5	8	4	7	9	2	6	1
4	1	9	2	6	8	3	5	7
2	7	6	5	1	3	4	8	9
6	3	2	9	4	7	8	1	5
1	4	5	8	2	6	7	9	3
9	8	7	3	5	1	6	4	2
8	2	3	6	9	5	1	7	4
5	6	1	7	3	4	9	2	8
7	9	4	1	8	2	5	3	6

नए वर्ष में 1800 करोड़ से संवरेगी योगनगरी ऋषिकेश

राज्य ब्यूरो, जागरण ● देहरादून

- ऋषिकेश के लिए जर्मन विकास बैंक से वित्त पोषित परियोजना को मूर्त रूप देने को होगी कंसल्टेंट की तैनाती
- न केवल ऋषिकेश शहर, बल्कि इससे लगे तपोवन, मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र भी होंगे विकसित

गंगा तट पर स्थित योगनगरी ऋषिकेश नए वर्ष में नए कलेवर में निखरेगी। शहर के लिए जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) से वित्त पोषित 1800 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में सरकार अब तेजी से कदम उठाने जा रही है। इसके अंतर्गत न केवल ऋषिकेश बल्कि इससे लगे तपोवन, मुनिकीरेती व स्वर्गाश्रम निकायों के क्षेत्रों में भी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परियोजना को धरातल पर मूर्त रूप देने के दृष्टिगत अब डिजाइन एवं सुपरविजन के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की कसरत शुरू की गई है। कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद वह परियोजना के तहत होने वाले कार्यों की डीपीआर को अंतिम रूप देगा। इसके पश्चात उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी कार्य प्रारंभ करेगी।

शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार बाह्य सहायतित परियोजनाओं पर भी जोर दे रही है। इसी क्रम में पूर्व में केंद्र सरकार के माध्यम से ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ की परियोजना के वित्त पोषण का प्रस्ताव जर्मन विकास बैंक को भेजा गया था। जर्मन विकास बैंक इस ऋण की मंजूरी दे चुका है और इस सिलसिले में समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हो चुका है। परियोजना के तहत क्षमता वर्द्धन, जागरूकता गतिविधि, प्रशिक्षण जैसे कार्यों के लिए 25 करोड़ का अनुदान भी मिलेगा। परियोजना 80:20 के अनुपात में होगी। यानी, कुल लागत का 80 प्रतिशत केंद्र और शेष राज्य सरकार वहन करेगी।

महायज्ञ [illegible]र आज नेपाल के जनकपुर प्रस्थान करेगी राम बरात

जागरण संवाददाता, अयोध्या

- सुबह साढ़े आठ बजे रामसेवकपुरम से जनकपुर के लिए प्रस्थान करेगी राम बरात
- चार दिन चलेंगी रस्में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के रामभक्त बनेंगे बराती

रामनगरी से मंगलवार को सुबह साढ़े आठ बजे राम बरात नेपाल के जनकपुर के लिए गाजे-बाजे व उल्लासपूर्ण माहौल में प्रस्थान करेगी। बरात कारसेवकपुरम में चल रहे श्री महानारायण दिव्य रुद्र यज्ञ की परिक्रमा कर रवाना होगी। कांची कामकोटि पीठ के संयोजन में कारसेवकपुरम में 45 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। यहां पर 1200 वैदिक आचार्य वेदमंत्रों के साथ यज्ञकुंड में आहुतियां डाल रहे हैं। सुदूर प्रदेशों के बरातियों का रामनगरी आगमन शुरू हो चुका है। रामनगरी से लगभग 200 साधु-संतों के साथ बरात चलेगी। बरात में चार रथ व दर्जनों वाहन गाजे-बाजे व वाद्य यंत्रों के साथ सम्मिलित होंगे। बरात के लिए 180 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रास्ते में भी बराती शामिल होंगे। जनकपुर तक बरातियों की संख्या 500 से अधिक होने की संभावना है।

राम बरात के लिए रामसेवक पुरम में बनकर तैयार हुआ तीर्थ रथ। जागरण

रामबरात को लेकर अयोध्या से लेकर जनकपुर तक उल्लास छाया है। यह बरात वर्ष 2004 से पांच वर्ष के अंतराल पर जाती रही है, लेकिन इस वर्ष रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद पहली राम बरात के चलते उत्साह कई गुना अधिक है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री व बरात के संयोजक राजेंद्र सिंह पंकज ने बताया कि बरात कारसेवकपुरम में महायज्ञ की परिक्रमा करते हुए मणिरामदास की छावनी से लता चौक होते हुए प्रस्थान करेगी। राम बरात में राजा दशरथ की भूमिका का निर्वहन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय करेंगे। राम तिलकोत्सव में भी वह इसी भूमिका में रहे हैं। वह सीधे जनकपुर पहुंचेंगे।

जनकपुर में चार दिन तक प्रभु श्रीराम व माता सीता के विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। रामनगरी से मंगलवार को बरात प्रस्थान के साथ ही सीताराम विवाहोत्सव शुरू हो जाएगा। 26 नवंबर से नौ दिसंबर तक यानी 14 दिनों तक चलने वाले विवाहोत्सव में अयोध्या और जनकपुर के लाखों श्रद्धालु इस दिव्य अवसर के साक्षी बनेंगे।

तिथि के अनुसार 11 जनवरी को मनेगी प्राण-प्रतिष्ठा की वर्षगांठ

जागरण संवाददाता, अयोध्या

रामजन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ यानी प्रथम पाटोत्सव अगले वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाएगा। रामलला के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा इसी वर्ष 22 जनवरी को हुई थी, किंतु इसकी प्रथम वर्षगांठ हिंदी तिथि के अनुसार से मनाने का निर्णय किया गया है। हिंदी तिथि के अनुसार से प्राण-प्रतिष्ठा पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुई थी और यह तिथि अगले वर्ष 11 जनवरी को पड़ रही है। सोमवार को रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद महासचिव चंपतराय व अन्य सदस्यों ने यह जानकारी दी। रामलला का प्रथम पाटोत्सव तीन दिवसीय होगा। बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा भी की गई। पदाधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि आठ एकड़ के परकोटा सहित तीन तल के संपूर्ण राम मंदिर और उसके सहायक 16 अन्य मंदिरों का कार्य अगले वर्ष अक्टूबर तक अंतिम रूप से पूरा हो सकेगा, अगले वर्ष मार्च तक सप्त ऋषियों के मंदिर तथा अप्रैल तक शेषावतार मंदिर का निर्माण पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

ट्रस्ट ने गत वर्ष से ही जिन अर्चकों को प्रशिक्षित किया है, उन्हें राम मंदिर सहित राम जन्मभूमि परिसर के अन्य सहायक मंदिरों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें शुचिता और मर्यादा का पूरा ध्यान रखना होगा और उन्हें रोटेशन के तहत राम मंदिर तथा सहायक मंदिरों में पूजा का अवसर मिलेगा।

****

ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने राजा तूतनखामेन की कब्र में प्रवेश किया

1922 में आज ही मिस्र में हावर्ड कार्टर व लार्ड कार्नरवान ने तीन हजार से ज्यादा वर्षों से बंद राजा तूतनखामेन की कब्र में प्रवेश किया था। इसमें सोने से बना 11 किलो का मुखौटा सहित कई अमूल्य वस्तुएं थीं। इसे इतिहास के सबसे प्रसिद्ध खोजों में गिना जाता है।

फ्रांस में खुला विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत स्टेशन

1966 में आज ही फ्रांस में विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत स्टेशन खुला था। रेंस नदी पर बने इस स्टेशन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल ने किया था। इसे बनाने का विचार जेराड बोइसनोवर ने दिया था। आज यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली ज्वारीय विद्युत स्टेशनों में से एक है।

छोटे से गांव आणंद को दूध राजधानी में बदलने वाले कुरियन

भारत के मिल्कमैन वर्गीज कुरियन का जन्म 1921 में आज ही केरल में हुआ था। 1949 में गुजरात के आणंद गए। यहां कम पैसों में आपूर्तिकर्ता को दूध बेचने की व्यवस्था को तोड़ने के लिए डेरी किसानों की एक छोटी-सी सहकारी संस्था (इसे आज अमूल कहा जाता है) के साथ काम करना शुरू किया। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंध स्थापित करने में मदद की। 1965 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना की। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की।

बादाम खाने से दूर होगी व्यायाम से होने वाली थकान

अध्ययन ▶ एक से दो दिन में दर्द की तकलीफ में महसूस की जा सकती है 33 से 37 प्रतिशत तक की राहत

प्रतिदिन 60 ग्राम बादाम के सेवन से मिलता है फायदा

नई दिल्ली, प्रेट्र : बादाम या अन्य मेवे में मौजूद पोषक तत्वों तथा उसके औषधीय गुणों का अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है। इसी क्रम में एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नियमित रूप से बादाम खाने से व्यायाम से होने वाली मांसपेशियों की थकान और दर्द से राहत मिलने में मदद मिल सकती है। अमेरिका स्थित सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों द्वारा किए इस अध्ययन में बताया गया है कि शारीरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में यह निष्कर्ष काफी अहम साबित हो सकता है। यह अध्ययन करंट डेवलपमेंट्स इन न्यूट्रिशन नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

अध्ययन के लिए विज्ञानियों की टीम ने 26 ऐसे वयस्कों का चयन किया, जो प्रति सप्ताह एक से चार घंटे व्यायाम करते थे। उनका बाडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) 23-30 के बीच था। आठ सप्ताह तक, प्रतिभागियों ने प्रतिदिन या तो 60 ग्राम साबुत कच्चे बादाम का सेवन किया। आठ सप्ताह बाद प्रतिभागियों को मांसपेशियों की क्षति को प्रेरित करने के लिए 30 मिनट की डाउनहिल ट्रेडमिल दौड़ से गुजरना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत बादाम का दैनिक सेवन किया। उसके बाद शोधकर्ताओं ने मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों के कार्य प्रदर्शन (संकुचन परीक्षण और वर्टिकल जंप) और मांसपेशियों की क्षति और सूजन के ब्लड मार्करों, जैसे कि सी-रिएक्टिव प्रोटीन और क्रिएटिन काइनेज का मापन किया।

ट्रेडमिल पर दौड़ने से पहले और उसके 24, 48, और 72 घंटे बाद यह माप परीक्षण किया गया और इस दौरान

पौष्टिकता के साथ ही औषधीय गुण भी।

प्रतिभागियों ने बादाम का दैनिक सेवन जारी रखा। पोस्ट रिकवरी अवधि के दौरान - ट्रेडमिल पर दौड़ने के 72 घंटे बाद तक - बादाम खाने वाले समूह में क्रिएटिन काइनेज का निम्न स्तर देखा गया, जो कम मांसपेशियों की क्षति का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, बादाम खाने वाले समूह के लोगों में ट्रेडमिल दौड़ के बाद 24 और 72 घंटों में मांसपेशी का बेहतर प्रदर्शन देखा गया। इतना ही नहीं, बादाम खाने वाले प्रतिभागियों में दर्द का स्तर प्रेट्जेल (एक प्रकार का बेक्ड प्रेस्ट्री) खाने वालों की तुलना में 24 और 48 घंटों में क्रमशः 37% और 33% कम पाया गया।

अध्ययन के लेखकों के मुताबिक, इस अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिदिन दो औंस (करीब 56 ग्राम) बादाम दर्द को कम करता है तथा मांसपेशियों की ताकत को बेहतर बनाए रखता है। ये नतीजे व्यायाम के बाद की रिकवरी में बादाम की भूमिका को पुष्ट करते हैं। सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी में व्यायाम और पोषण विज्ञान के प्रोफेसर मार्क केर्न ने बताया, बादाम में प्रोटीन, एंटीआक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स सहित व्यायाम रिकवरी (व्यायाम से होने वाले मांसपेशियों के नुकसान की भरपाई) में मददगार माने जाने वाले पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। अलग-अलग विटामिन की खुराक के विपरीत, ये पोषक तत्व पूरे खाद्य पैकेज प्रदान करते हैं।

एक औंस (28 ग्राम) बादाम 6 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फाइबर, 13 ग्राम अनसैचुरेटेड फैट, 1 ग्राम सैचुरेटेड फैट और 15 आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है - जिसमें 77 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 210 मिलीग्राम पोटेशियम और 7.27 मिलीग्राम विटामिन ई शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि बादाम व्यायाम रिकवरी को कैसे बेहतर बनाता है, इसके तंत्र को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। व्यायाम रिकवरी के तरीके को बेहतर बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि आप बेहतर तरीके से ठीक हो रहे हैं तो बाद के वर्कआउट के लिए जल्दी सक्षम होने की संभावना बढ़ती है।

रोशनी से जगमग क्रिसमस बाजार

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित रामेर स्क्वायर में शुरू हुआ क्रिसमस बाजार लोगों को जमकर आकर्षित कर रहा है और यहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग इस बाजार में हर तरफ क्रिसमस की खुशबू लोगों को अपना दीवाना बना रही है। लोग यहां विभिन्न चीजों की खरीदारी कर रहे हैं, गर्म पेय और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं और क्रिसमस के जादू में खोए से नजर आ रहे हैं। क्रिसमस की भावना को जीवंत करता यह विहंगम दृश्य हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। एएफपी

इधर-उधर की

होटल को उड़ाकर मनाया जाएगा नए वर्ष का जश्न

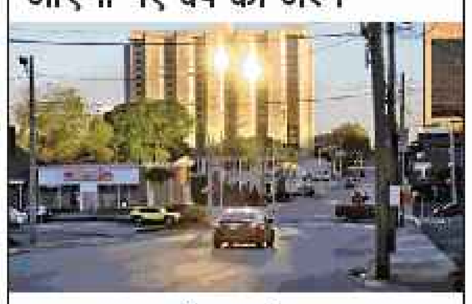
26 लाख डालर में ध्वस्त होगा 45 लाख डालर का होटल। इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी : आतिशबाजी के साथ नए वर्ष मनाने की बात अब पुरानी हो चुकी है। अमेरिका का एक शहर मैकान बिब काउंटी नए साल की पूर्व संध्या पर खाली पड़े 16 मंजिला होटल को ध्वस्त कर नए साल का स्वागत करेगा। दिवालिया कार्यवाही के तहत मैकान बिब काउंटी ने पिछले साल 45 लाख डालर में होटल का अधिग्रहण किया था। अब वह 26 लाख डालर खर्च कर होटल को ध्वस्त करेगा। मेयर ने बताया कि इसे उड़ाने के लिए ही इसका अधिग्रहण किया गया था।

सूर्य की सतह पर उभरे दो नए स्पाट, जारी रहेंगे विस्फोट

रमेश चंद्रा • जागरण

- आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ेगी सन स्पाट की सक्रियता
- दो दिन के भीतर एम और सी क्लास की 11 सौर ज्वालाएं भड़कीं

नैनीताल : 11 वर्षीय सौर चक्र इन दिनों चरम पर है और आने वाले दिनों में सूर्य की सतह पर बड़े विस्फोटों की संभावना सौर विज्ञानियों ने जताई है। बीते दो दिन के भीतर एम व सी क्लास की 11 सौर ज्वालाएं सूर्य की सतह पर भड़की हैं। फिलहाल सूर्य की सतह सन स्पाट से पटी है। एआर (एक्टिव रीजन) 3905 और एआर 3906 नाम के दो नए सन स्पाट उभरे हैं, जो आने वाले दिनों में सक्रिय रहेंगे और विस्फोट करेंगे। इनमें एआर 3906 को विज्ञानी अधिक शक्तिशाली मान रहे हैं। इनके साथ ही सन स्पाट एआर 3901 व एआर 3903 पहले से अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं।

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के विज्ञानियों के अनुसार एम क्लास की ज्वाला से बीते दिनों ब्राजील क्षेत्र में रेडियो ब्लैकआउट हुआ था। जिसका मामूली प्रभाव देखा गया। इसके अलावा प्रशांत महासागर के फ्रेंच पोलिनेशिया पर रेडियो ब्लैकआउट हुआ।

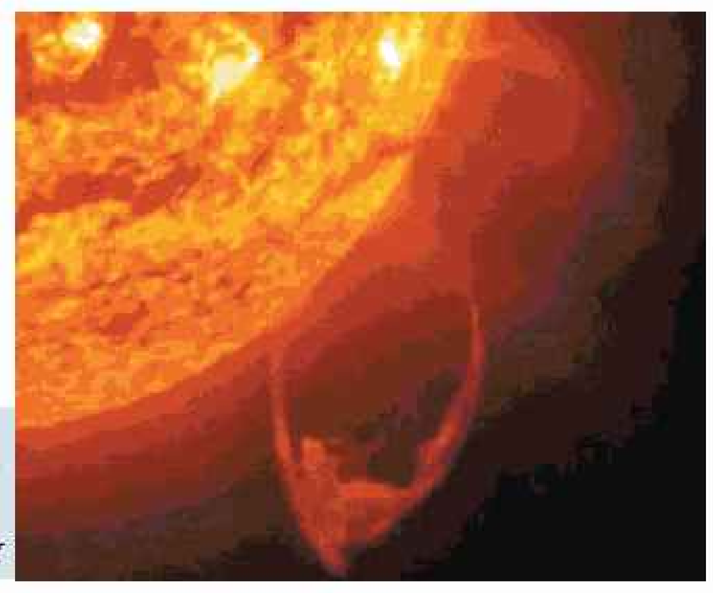
पिछले दिनों सूर्य की सतह से उठी सौर ज्वाला की तस्वीर। सौजन्य- इंटरनेट

इधर, सूर्य के पृथ्वी की ओर वाले हिस्से में नौ सनस्पाट क्षेत्र बने हैं। जिनसे अगले 24 घंटे में न्यूनतम सी क्लास ज्वाला की संभावना 99 प्रतिशत रहेगी। जबकि मध्यम एम क्लास की संभावना 60 प्रतिशत है। एरीज के पूर्व कार्यवाहक निदेशक व सौर विज्ञानी डा. वहाबउद्दीन के अनुसार, यह 25वां सौर चक्र है और इसमें ऐतिहासिक विस्फोट या सौर ज्वालाएं देखने को मिली हैं।

इसलिए होते हैं विस्फोट : सन स्पाट सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधि यानी सौर सक्रियता को बढ़ाते हैं और विस्फोटित होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। विस्फोट के बाद सूर्य की सतह पर ज्वाला भड़कती है। सौर विज्ञानी डा. वहाबउद्दीन कहते हैं कि इन दिनों जो दो नए सन स्पाट उभरे हैं उन्हें 'एआर 3905 व एआर 3906' नाम दिया गया है। एआर 3901 व 3903 कई दिन पहले उभरे थे, जिन्होंने कई शक्तिशाली विस्फोट किए। अब ये दोनों शिथिल पड़ रहे हैं। दुनियाभर के सौर विज्ञानी इन सन स्पाट पर नजर रखे हुए हैं।

दो तरह के अनुभव कराती हैं सौर ज्वालाएं : डा. वहाबउद्दीन का कहना है कि सौर ज्वालाएं दो तरह के अनुभव कराती हैं। सेटेलाइट, हवाई सेवाओं के लिए यह बेहद खतरनाक हैं। रेडियो ब्लैकआउट होता है। जबकि दूसरा अनुभव आरोरा के रूप में रंगबिरंगी रोशनी बिखेरना है। इस सौर चक्र में आरोरा की रोशनी पिछले सौर चक्र की तुलना में अधिक देखने को मिली।

तीन वर्गों में विभाजित सौर ज्वालाएं : सूर्य की सतह में होने वाले विस्फोटों से पैदा होने वाली ज्वालाएं लाखों किमी में हो सकती हैं। अभी तक सबसे लंबी ज्वाला आठ लाख किमी मापी गई है। सौर ज्वालाओं का मापन तीन वर्गों में किया जाता है। जिनमें एक्स श्रेणी की सर्वाधिक घातक होती है। एम श्रेणी की मध्यम आकार और सी श्रेणी की सबसे छोटी होती है।

गर्भावस्था में प्रोबायोटिक का उपयोग शिशु को सुरक्षा देने में मददगार

अनुसंधान

घरों में उपयोग होने वाले अपहोल्स्ट्री, कालीन, पर्दे, इलेक्ट्रानिक्स और शिशु उत्पादों में पालीब्रोमिनेटेड डिफेनिल ईथर (पीबीडीई) का इस्तेमाल होता है। यह अग्निरोधी रसायन है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार, हार्मोन को बाधित करने और पर्यावरण में बने रहने के लिए जाने जाने वाला यह प्रदूषक पानी, मिट्टी, हवा, खाद्य उत्पादों आदि में भी पाया जाता है। चूहों पर किए गए शोध में पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान पीबीडीई के संपर्क में आने से बच्चों में आटिस्टिक व्यवहार और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसी समस्या हो सकती है। तंत्रिका विज्ञान की प्रोफेसर मार्गरीटा सी. क्यूरस-कोलाजो ने कहा कि पीबीडीई के संपर्क में आने से न्यूरोडवलपमेंट, मेटाबालिज्म संबंधी समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान प्रोबायोटिक लिमोसिलेक्टोबैसिलस रेउटेरी दिए जाने से इन नकारात्मक प्रभावों को रोकने में मदद मिल सकती है। एल रेउटेरी या एलआर आमतौर पर पाचन तंत्र में रहता है, जहां यह लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है। प्रोबायोटिक एलआर बीन्स, शकरकंद, फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों, दही और अन्य डेरी उत्पादों में पाया जाता है।

शोधकर्ताओं ने गर्भावस्था के दौरान चूहों को पीबीडीई मिश्रण दिया। उन्हें उसी जोखिम वाली स्थिति में रखा गया। कुछ चूहों को एलआर दिया गया। फिर उनके बच्चों का अध्ययन किया गया। पीबीडीई के संपर्क में आने वाले नर संतानों के शरीर का वजन बढ़ने में देरी हुई। वहीं, एलआर दिए गए चूहों के संतानों के वजन वृद्धि और दांत निकलने का समय सामान्य पाया गया। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

अभिषेक बोले, घर पर आराध्या के साथ ऐश्वर्या हैं

साल 2007 में ऐश्वर्या के साथ परिणय सूत्र में बंधे थे अभिषेक। इंटरनेट मीडिया

बीते कुछ महीनों से अभिनेता अभिषेक बच्चन तथा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के बीच अलगाव और तलाक की खबरें खूब सुर्खियों में रहीं। कई अहम मौकों पर दोनों को अकेले देखे जाने की घटनाओं से इन खबरों को और हवा मिली। हालांकि, इसी बीच हाल ही में अभिषेक ने न सिर्फ ऐश्वर्या का धन्यवाद किया, बल्कि यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि घर पर ऐश्वर्या आराध्या के साथ हैं। दरअसल, हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक से पूछा गया कि क्या सितारों के बच्चों के दिमाग में यह स्वाभाविक तौर पर रहता है कि ज्यादातर समय उनके माता-पिता उनके साथ नहीं रहने वाले हैं? इस पर अभिषेक ने अपनी मां और अभिनेत्री जया बच्चन का उदाहरण देते हुए कहा कि बचपन में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने अभिनय करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहती थीं। हमने अपने आस पास अपने पिता के न होने की कमी कभी नहीं महसूस की।' आगे अभिषेक ने कहा कि भाग्यशाली हूं कि मैं बाहर जा सकता हूं और फिल्में बना सकता हूं। मैं जानता हूं कि घर पर आराध्या के साथ ऐश्वर्या हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बच्चे इस नजरिए से सोचते हैं। वे आपको किसी तीसरे व्यक्ति के नजरिए से नहीं देखते हैं। वह आपको माता-पिता के तौर पर ही देखते हैं।

...जब अनन्या को लगा कि वह बालीवुड के लिए नहीं बनी हैं

'कंट्रोल' अभिनेत्री अनन्या इन दिनों खासी व्यस्त हैं। हालांकि, अपने शुरुआती वर्षों में इंटरनेट पर ट्रोल होने के बाद वह सेट पर जाकर काम नहीं करना चाहती थीं। उन्हें लगता था कि वह बालीवुड के लिए नहीं बनी हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों से निपटने के लिए उन्हें थेरेपी से गुजरना पड़ा था। थेरेपी कराने को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी थेरेपी करवाई है, लेकिन अब मैं उतनी नियमित नहीं हूं। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती थी। मैं बहुत उदास महसूस करती थी। इंटरनेट मीडिया के साथ मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप उस समय कुछ पढ़ सकते हैं और आपको यह अहसास नहीं होता कि यह आपको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं अभी ठीक हूं, मेरा दिन अच्छा चल रहा है, मैं कार में हूं, मैं व्यस्त हूं। मैं कोई टिप्पणी पढ़ूंगी और उसे अनदेखा कर दूंगी। लेकिन हफ्तों बाद भी यह आपके अवचेतन में कहीं मौजूद हो सकता है और ऐसी चीजें वास्तव में जमा हो सकती हैं। थेरेपी की मदद से मैं अपनी भावनाओं को समेकित करने और अपने विचारों को थोड़ा बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हुई।

अनन्या को याद आए पुराने दिन। @ananyapanday (इंस्टाग्राम)

कार्तिक को लग रहा सीक्वल का चस्का, अब लुका छुपी 2 पर विचार

भूल भुलैया 2 की सफलता ने अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ इस फ्रैंचाइजी की एक और फिल्म भूल भुलैया 3 बनाने के लिए प्रेरित किया। दीवाली पर प्रदर्शित भूल भुलैया 3 अच्छी कमाई करने में सफल रही। ऐसे में अब लग रहा है कि कार्तिक को भी सीक्वल और फ्रैंचाइजी फिल्मों का चस्का लग गया है। एक तरफ निर्माता जहां उनके साथ भूल भुलैया 4 बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं। वहीं मुदस्सर अजीज निर्देशित उनकी फिल्म पति पत्नी और वो की सीक्वल भी कतार में हैं। अब खबरें है उनकी साल 2019 में प्रदर्शित फिल्म लुका छुपी की भी सीक्वल बनाने की योजना है। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्टों के अनुसार, कार्तिक हाल ही में निर्माता दिनेश विजन से मिले थे। इस दौरान दोनों की कई फिल्मों पर बात हुई। इनमें एक फिल्म लुका छुपी की सीक्वल भी है। हालांकि, लुका छुपी की सीक्वल पर बात कितनी आगे तक बढ़ेगी, इस पर दोनों एक महीने बाद ही निर्णय लेंगे। हालांकि, टिकट खिड़की के आंकड़ों के आधार पर देखें तो कार्तिक को सीक्वल फिल्म रास आ रही हैं। ऐसे में दिनेश उनके साथ लुका छुपी 2 बनाने पर भी विचार कर सकते है। इसके अलावा कार्तिक की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी की भी सीक्वल बनने की खबरें हैं।

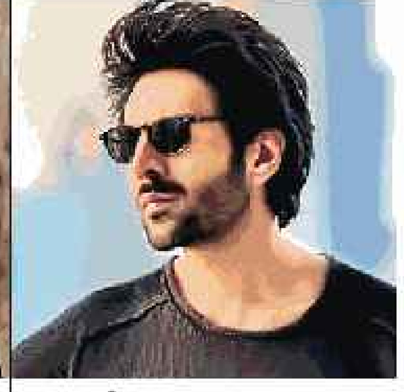
कई सीक्वल कर रहे हैं कार्तिक। @kartikaaryan (इंस्टाग्राम)

चुनौतियों का अपना आनंद है : भूमि

महिला प्रधान फिल्मों को प्राथमिकता देती रही हैं भूमि। @bhumipednekar (इंस्टाग्राम)

कई फिल्मों में सशक्त भूमिका निभा चुकी भूमि पेडणेकर अपनी पहली फिल्म दम लगाके हईसा में संध्या की भूमिका सबसे खास मानती हैं। भूमि कहती हैं कि जब मैंने अभिनय में कदम रखा था तो सौंदर्य को तवज्जो दी जाती थी, पर मैंने पहली ही फिल्म में मोटी व सामान्य दिखने वाली लड़की संध्या का पात्र निभाया। ऐसी नायिका की कल्पना करना भी लोगों के लिए मुश्किल था। मैं स्वयं भी चकित थी। यशराज की फिल्म की ये नायिका उसकी पिछली फिल्मों की नायिकाओं से बिल्कुल अलग थी, पर उसे जो प्यार मिला वो भी कल्पनाओं से बढ़कर था। भूमि आगे कहती हैं कि चुनौतियों का अपना आनंद है। आगामी वेब सीरीज दलदल में वह पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखेंगी। भूमि बताती हैं कि दलदल में मैं पुलिस अधिकारी रीता की भूमिका में दिखूंगी। पुरुषों की दुनिया में वह अपने नियम गढ़ती है। वह महत्वाकांक्षी है। अपने काम को लेकर जुनूनी है। सामने से चुनौतियां स्वीकार करना उसका मिजाज है। ऐसी महिलाओं का मैं स्वयं अनुकरण करती हूं। सच कहूं तो असल जीवन में मैं भी ऐसी ही हूं। भूमि इन दिनों ओटीटी पर अधिक सक्रिय हैं। उनके खाते में अमृत राज गुप्ता निर्देशित वेब सीरीज दलदल के अलावा द रायल्स वेब भी है, जो शीघ्र ही नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी।

रिलेशनशिप स्टेटस 'हीहीही...'

मलाइका और अर्जुन ने साल 2018 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। फिर इस साल दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया।

अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के बीच ब्रेकअप की खबरें अब सार्वजनिक हो चुकी हैं। अर्जुन ने सार्वजनिक मंच से स्वयं को सिंगल घोषित किया था। हालांकि इस बारे में मलाइका का कोई प्रत्यक्ष बयान सामने नहीं आया था। अब मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताया है। रविवार की रात किए इस पोस्ट में लिखा है कि फिलहाल के लिए मेरी रिलेशनशिप स्थिति, आगे इस पोस्ट में तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला किसी के साथ रिश्ते में हूं, दूसरा सिंगल और तीसरा हीहीही...। इन तीनों बिंदुओं के बीच तीसरे यानी कि हीहीही... विकल्प को चिन्हित किया गया है। मलाइका का यह पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है। जिसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किया है कि फिलहाल वह भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है।

« करीब छह वर्षों तक एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में रहे मलाइका और अर्जुन • @malaikaaroraofficial (इंस्टाग्राम)

जब संजय को खींचने पड़े थे माधुरी के बाल

« कामेडी के साथ-साथ विषय प्रधान फिल्में भी कर रहे हैं संजय • @imsanjaimishra (इंस्टाग्राम)

जब किसी कलाकार को उसकी पहली ही फिल्म में किसी स्थापित अभिनेत्री के बाल खींचने का सीन करना पड़े, तो उसे घबराहट होना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ अभिनेता संजय मिश्रा के साथ भी हुआ था। संजय बताते हैं, 'फिल्म राजकुमार में मुझे एक ग्रामीण की भूमिका मिली थी। फिल्म के एक सीन में मुझे माधुरी दीक्षित के बाल पकड़ कर खींचना था। यह सोचकर मेरी तबीयत ही खराब होने लगी कि ये तो एक दो तीन... गाने वाली अभिनेत्री है, उनके बाल कैसे खींच सकता हूं। फिर मैंने माधुरी जी से पूछा कि मैडम आपके बाल ऐसे पकड़कर खींच सकता हूं? उन्होंने प्यार से कहा कि हां हां..। आप खींच सकते हो। फिर जाकर वो शाट हुआ था।'

द फैमिली मैन 3 की कहानी में शामिल होगा चीन एंगल

जयदीप अहलावत शो में मुख्य खलनायक की भूमिका में होंगे • जागरण आर्काइव

साल 2019 में प्रदर्शित मनोज बाजपेयी अभिनीत वेब सीरीज द फैमिली मैन के तीसरे सीजन की शूटिंग फिलहाल अंतिम चरणों में है। शो से जुड़े सूत्रों ने रहस्योद्घाटन किया कि नागालैंड में शो की शूटिंग करना कहानी का अहम हिस्सा होगा। दरअसल, इस बार शो की कहानी न सिर्फ भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में जा रही है, बल्कि इस बार कहानी में भारत और चीन के बीच तल्ख रिश्तों और पूर्वोत्तर भारत में चीन की दखलंदाजी की कोशिशें भी दिखाई जाएंगी। उसी उद्देश्य के साथ शो को असम के काजीरंगा और नागालैंड के कोहिमा में कुछ ऐसी जगहों पर शूट किया गया है।

पहली फिल्म के बाद सालभर बेरोजगार था

डेब्यू फिल्ममेकर सुकुमार ही थे जिन्होंने मेरे करियर को सही दिशा दी
@alluarjunonline

अभिनेता अल्लू अर्जुन और पुष्पा : द राइज फिल्म के निर्देशक सुकुमार ने करीब 20 साल पहले फिल्म आर्या में एकसाथ काम किया था। उसके बाद यह जोड़ी सफल रही है। 2021 में, उन्होंने पुष्पा : द राइज में साथ काम किया और अब, वे पुष्पा 2 : द रूल के लिए फिर से साथ हैं। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान अल्लू अर्जुन ने सुकुमार के बारे में कहा, 'सुकुमार ही थे जिन्होंने मेरे करियर को सही दिशा दी। पहली फिल्म गंगोत्री के बाद अगले एक साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। फिल्म रिलीज के बाद कोई मेरे साथ काम करने नहीं आया। फिर, एक डेब्यू फिल्ममेकर (सुकुमार) आए और आर्या की पेशकश की। तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।' पुष्पा : द रूल पांच दिसंबर को रिलीज होगी।

****